RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 255
नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

बजट 2024-25

www.dailypioneer.com

रेलवे का बड़ा ध्यान सुरक्षा संबंधी कार्यों पर

राष्ट्रीय-10

मध्यम वर्ग को कर राहत, रोजगार सृजन पर जोर

फोटो: रंजन डिमरी

राहुल दत्ता। नई दिल्ली

मध्यम वर्ग तक पहुंचते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बड़ी आयकर राहत की घोषणा की और कहा कि चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को बदलावों से लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करते हुए, उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया, मोबाइल फोन और सोने पर सीमा शुल्क में कटौती की और पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा ने अगले पांच साल में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों- बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के लिए ग्रामीण असंतोष और बेरोजगारी को जिम्मेदार माना गया है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है।

सीतारमण ने अपना सातवां और नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजेल कर समाप्त करने की घोषणा की। जब कोई गैर-सूचीबद्ध या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका मूल्य कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजेल कर लगाया जाता है। हालांकि, वित्त मंत्री ने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ा दिया। इस कदम से शेयर बाजारों में गिरावट आई। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की। यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार को वित्तीय समर्थन पूंजीगत परियोजनाओं के रूप में है। यह सब्सिडी या नकद सहायता के रूप में नहीं है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू (जनता दल यूनाइटेड) राज्य के लिए आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में (शेष पेज 9)

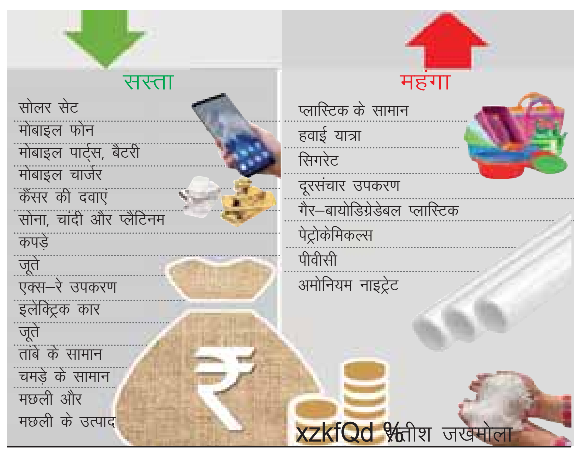

सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है जिसमें सहयोगियों को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट की नकल है -**राहुल गांधी,** नेता प्रतिपक्ष, का एक्स पर एक पोस्ट

भारत के युवाओं, नारी शक्ति और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए, बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर देश की गति को बढ़ाएगा - **अमित शाह,** केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा

युवाओं के लिए खोला खजाना

राजेश कुमार। नई दिल्ली

आलोचकों को चुप कराते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया और इसी तरह रोजगार के मुद्दे को हल करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, जिसके लिए भाजपा सरकार को पिछले दो कार्यकाल के दौरान आलोचना का सामना करना पड़ा था। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रोजगार के लिए घोषणा की थी, दोनों योजनाएं ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर केंद्रित होंगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ा होगा। यह योजना कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महीने (शेष पेज 9)

सुनहरे भविष्य वाला बजट: मोदी

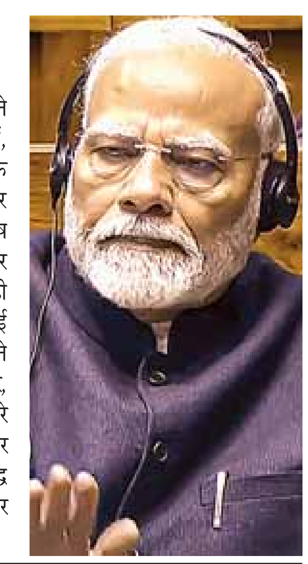

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समाज के हर वर्ग के लिए किए गए उपायों के लिए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि इसने बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद उन्होंने टेलीविजन पर अपनी टिप्पणी में कहा, बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और विकसित भारत के लिए एक ठोस नींव रखेगा। मोदी ने बजट में युवाओं, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के साथ-साथ विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की सराहना की और कहा कि प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं करोड़ों नई नौकरियां पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेहतर वृद्धि (ग्रोथ) और सुनहरा भविष्य लेकर आया है। (शेष पेज 9)

नई कर व्यवस्था में संशोधित दर

0-3 लाख रुपये	शून्य
3-7 लाख रुपये	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये	20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500/- तक की बचत होगी।

बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज की सौगात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू फाइल फोटो

- बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रहस्यमय प्रतिक्रिया व्यक्त की

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी शासित बिहार और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई, लेकिन केंद्र द्वारा 'विशेष श्रेणी का दर्जा' देने से इनकार करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रहस्यमय प्रतिक्रिया व्यक्त की। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ जदयू नेता की राजनीतिक पैंतरेबाजी को देखते हुए दिन के दौरान राजनीतिक भाषाएं लड़खड़ाती रहीं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन द्वारा विशेष दर्जा की उनकी मांग को पूरा करने से खारिज कर दिए जाने के एक दिन बाद पटना में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, आपको धीरे-धीरे सभी चीजें पता चल जाएंगी। नीतीश ने हाल ही में अपनी पार्टी के एक प्रस्ताव का पेश किया था, जिसमें विशेष दर्जे की मांग और इस मुद्दे पर भाजपा को सशर्त समर्थन की बात दोहराई गई। हालांकि, शाम तक नीतीश ने दावा किया कि बजट 'विशेष सहायता की हमारी मांग को पूरा करता है, यदि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विशेष दर्जा देना संभव नहीं था।'

जेडीयू ने विशेष दर्जे की मांग पर हंगामा करने के लिए विपक्षी राजद-कांग्रेस-वाम गठबंधन पर हमला बोला, 'यह भूलकर कि यूपीए, जिसका वे हिस्सा थे, ने केंद्र में शासन करते समय हमारी मांग को खारिज कर दिया था।' नीतीश ने कहा, हम विशेष दर्जे की बात कर रहे थे और बहुत से लोगों ने कहा कि विशेष दर्जे का प्रावधान बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। इसलिए इसके बदले बिहार में विकास में मदद के लिए सहायता दी जानी चाहिए, अब, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। गठबंधन की राजनीति और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सहयोगियों - टीडीपी और जेडी (यू) की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। जहां 16 सांसदों के साथ टीडीपी एनडीए में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है, (शेष पेज 9)

होम बायर्स को फायदा, रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा जोश

रिंकू यादव। नोएडा

साल 2024-25 का आम बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ हद तक खुशी लेकर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों को स्टांप ड्यूटी कम करने का सुझाव दिया। इसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार को सकारात्मक उम्मीद जगी है। डेवलपर्स का कहना है कि इससे घर खरीदारों को लाभ होगा और वे घरों की ओर निवेश की ओर उत्साहित होंगे। इसका सीधा लाभ सेक्टर को होगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व शहरी घरों को बनाने में सरकार दस लाख करोड़ से अधिक का फंड खर्च करेगी।

मनोज गौड़, अध्यक्ष, क्रेडाई एनसीआर और सीएमडी, गौड़ ग्रुप के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी घोषणा 10 लाख करोड़ रुपए का शहरी आवास के लिए निवेश है। यह देश में किफायती आवास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा। उच्च मांग के बावजूद, इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है क्योंकि बजटरी सपोर्ट की कमी थी। 30 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर, संजय शर्मा का कहना है कि सरकार ने 11.1 लाख करोड़ का आवंटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा, अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ रोजगार सृजन के लिए खर्च किए जाएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी घटाने की सलाह दी गई है, जिससे खरीदारों को रजिस्ट्रेशन की लागत कम होगी। अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप के अनुसार यह बजट भारत-केंद्रित है। सरकार की लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, युवाओं को कौशल प्रदान करने, एमएसएमई को सशक्त करने और शहरी आवास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना व्यापक विकास की ओर इशारा करती है। वित्त मंत्री का राज्यों से स्टांप ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव एक प्रोत्साहक कदम है जो आवास की मांग और विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाओं पर ध्यान देना शहरी विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। स्पेक्ट्रम मेट्रो के वाइस प्रेजिडेंट सेल्स व मार्केटिंग अजेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे, रोजगार, युवाओं की स्किल, छोटे और मध्यम उद्योगों और शहरी आवास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें स्टांप शुल्क घटाने और टीओडी और औद्योगिक पार्क बनाने पर जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे रोजगार और स्किल के विकास के साथ वाणिज्यिक संपत्तियों की वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग व बिजनेस मैनेजमेंट सलिल कुमार के अनुसार प्रदेश सरकारों को स्टांप ड्यूटी कम करने का जो सुझाव दिया गया है वह बेहद सकारात्मक कदम हैं। इससे लाखों फ्लैटधारकों को लाभ होगा और रजिस्ट्री में उनका खर्च कम होगा। लंबे समय से कई संगठन यह मांग उठा रहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसके अलावा शहरों में घरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का का निवेश एक बड़ा कदम है जिसके दूरगामी प्रभाव बेहद सकारात्मक होंगे।

बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य

- इसमें माता-पिता और अभिभावक करेंगे योगदान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की। सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक योगदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के उपायों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत नियोक्ताओं द्वारा खर्च की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में समाधान विकसित किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का हल करेगा और राजकोषीय सूझबूझ सुनिश्चित करेगा।

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में जरूरत होने पर किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटने का फैसला किया था और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है। लोकसभा में अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में समाधान निकाला जाएगा। इसके तहत राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती रहती है।

अदालत ने जीएम सरसों पर दिया खंडित फैसला

- पर्यावरण में उत्पादन और परीक्षण के लिए छोड़ने पर केंद्र के फैसले को चुनौती

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सरसों की संकर (हाइब्रिड) किस्म डीएमएच-11 को बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण में छोड़ने के केंद्र सरकार के वर्ष 2022 के फैसले की वैधता पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़े जाने की सिफारिश करने के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 18 अक्टूबर, 2022 के फैसले और उसके बाद 25 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11 को पर्यावरण में छोड़े जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

जीईएसी आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों के लिए देश की नियामक संस्था है। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अलग-अलग राय दी। पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया, ताकि कोई दूसरी पीठ इस पर फैसला दे सके। हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का केंद्र को एकमत से निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करे और यदि इस प्रक्रिया को चार महीने में पूरा कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जीएम फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर, 2022 को दिए गए जीईएसी के निर्णय दोषपूर्ण थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने से इनकार

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें विवादों से घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। न्यायालय का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुम्परा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं। पीठ फैसला सुरक्षित रखने के बजाय शाम करीब 4:50 बजे फिर बैठी और आदेश सुनाना शुरू किया। पीठ ने कहा, इस तरह के मामले में अदालत के अंतिम निष्कर्ष वर्तमान चरण में दर्ज किए जाने चाहिए क्योंकि इस विवाद को निश्चितता और अंतिम रूप प्रदान करने की तत्काल

आवश्यकता है, जो 20 लाख से अधिक छात्रों के करियर को प्रभावित करता है। एनटीए और अन्य द्वारा पेश सामग्री की स्वतंत्र जांच का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "वर्तमान चरण में, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश देने से पिछली परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उसने कहा कि इससे नामांकन कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और वंचित समूहों को गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए, कदाचार व्यापक स्तर पर और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हो। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि व्यवस्थित तरीके से प्रश्नपत्र लीक हुआ था और अदालत के पास फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। पीठ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केन्द्रों में 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। उसने कहा कि चूंकि दागी छात्रों को अन्य छात्रों से अलग पहचाना जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि दोबारा परीक्षा ही एकमात्र विकल्प है। पीठ ने इसके साथ ही विभिन्न वजहों से 1,563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के एनटीए के निर्णय को भी बरकरार रखा।

बजट : ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, चमकेगा सर्राफा बाजार

● नोएडा के व्यापारी समूह बोले- नए प्रस्ताव से एमएसएमई सेक्टर को गति मिलेगी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

2024-25 का बजट ग्रीन रिवेल्यूशन की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा तो होगा साथ ग्रीन एनर्जी जिसमें बायो फ्यूल के क्षेत्र में विकास होगा। डॉ. पीयूष द्विवेदी, अध्यक्ष, नेक्सजेन एनर्जी लिमिटेड, ने कहा बजट मध्य वर्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), और हरी ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है।

डॉ. द्विवेदी ने बताया कि मध्य वर्ग के लिए राहत के तहत नए आयकर स्लैब और स्वास्थ्य बीमा व आवास ऋण के लिए बढ़ी हुई छूट शामिल की गई हैं। एमएसएमई के संदर्भ में, क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। इसके अलावा, हरी ऊर्जा क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए, ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए 2,500 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया गया है। डॉ. द्विवेदी ने इन पहलुओं को सकारात्मक और विकासात्मक कदम मानते हुए, सरकार की दृष्टि की सराहना की है। सुशील कुमार जैन अध्यक्ष , सेक्टर 18 मार्केट एसोसिएशन और कैट के संयोजक ने कहा कि इस बजट में कुल मिलाकर सरकार ने सभी लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। नए रिजाइम में आयकर दर में परिवर्तन से करदाताओं को 17500 का निश्चित फायदा होगा। यद्यपि व्यापारियों को कोई सीधा कर लाभ नहीं मिला किन्तु विकास पर होने वाले खर्चों का सीधा लाभ व्यापारियों एवं उद्यमियों को ही मिलेंगा। केंद्रीय बजट घोषणा जिसमें सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है एक सराहनीय और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। यह कटौती अवैध लेनदेन पर अंकुश लगाएगी, लीगल व इल्ली गल तस्करी को रोकेगी और अधिक पारदर्शी और कानूनी बाजार को बढ़ावा देगी। ग्राहकों को 9 प्रतिशत सस्ता सोना मिलेगा। पूरा रत्न और आभूषण उद्योग इस महत्वपूर्ण कदम के लिए हमारे वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता है। नोएडा एंट्रप्रिन्यौर्स एसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि दुनिया में मंदी आने के बावजूद हमारी इकोनॉमी मजबूत है।

एमएसएमई सेक्टर के लिए गारंटी तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया है। जिससे अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एमएसएमई सेक्टर को गति मिलेगी। शहरी इलाकों में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 करो? मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों का अपना घर होने का सपना साकार होगा। युवाओं को स्टार्टअप अप योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना एक अच्छा संकेत है। इससे रोजगार के अवसर बढेगें। कौशल विकास पर भी सरकार ने एक बार पुन: जोर दिया है इससे लोगों के कार्य करने की गुणवत्ता एंव क्षमता में विकास होगा । इंफ्रास्ट्रचर के लिए 11.11 लाख करोड़ का बजट एक अच्छा कदम है। युवाओं को 500 बडी कंपनियों में इन्टर्नशिप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इससे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे

युवाओं को रोजगार का अवसरः विकास जैन

नोएडा। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के बरौला स्थित प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने कहा कि इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर मातृ शक्ति को सशक्त और मजबूत करने का कार्य किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई में 100 करोड़ तक लोन गारंटी खत्म कर छोटे उद्यमियों को नई ऊर्जा दी गई है।

ऊंची इमारतों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी जांच

● गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी करने के साथ 10 हजार का जुर्माना लगेगा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा हाइराइज इमारतों का शहर है। यहां वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। आगामी 10 साल में ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति खराब हो सकती है। औसतन सालाना डेढ़ से दो मीटर तक वाटर लेवल गिर रहा है। जिससे यहां पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए भवन नियमावली के तहत 100 वर्गमीटर और बड़े प्लाट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। ये सिस्टम यहां बनी रिहाइशी इमारत, कॉमर्शियल मॉल, होटल, स्कूल, सरकारी इमारतों में एक्टिव है या नहीं इसकी पड़ताल की जा रही है।

नोएडा प्राधिकरण के पर्यावरण सेल ने इसके लिए दो टीम गठित की है। ये टीम चार दिन में नोएडा के सभी श्रेणी की प्रॉपर्टी पर जाकर रैंडम जांच करेगी। पहले चरण में 10-10 स्थानों पर जाएंगी।

इसकी एक रिपोर्ट सीईओ नोएडा प्राधिकरण को दी जाएगी। जिस स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मानकों पर काम करता नहीं पाया जाएगा। वहां नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की समय 15 दिन का होगा। 16वें दिन प्रॉपर्टी मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 17वें दिन में रोजाना 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नोएडा प्राधिकरण में पर्यावरण सेल के सलाहकार गुंजन मिश्रा ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच के लिए आदेश मिल गया है।

इसकी प्रति प्राधिकरण के सभी वर्क सर्किल और सभी आरडब्ल्यूए और एओए को जारी कर दी गई है। एओए और सेक्टर के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने यहां स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच कराकर रिपोर्ट सब्मिट करे देखा जाए तो जनपद गौतमबुद्ध नगर में शुरुआती दौर में 1,018 तालाब थे। इसमें 67 तालाब नोएडा प्राधिकरण, 281 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र और 277 तालाब यमुना विकास प्राधिकरण और करीब ×61 तालाब ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। विगत एक साल में तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में कई तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। जिसमें से 217 के करीब तालाबों पर अतिक्रमण था। जिसमें नोएडा में 40 तालाब शामिल है।

यीडा 40 हजार करोड़ से न्यू आगरा बसाएगा

● 10 हजार 500 हेक्टेयर होगा एरिया, 9 महीने में तैयार होगा मास्टर प्लान

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) आगरा के पास न्यू आगरा बसाएगा। न्यू आगरा अर्बन सेंटर की स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप का चयन किया गया है। कंपनी 9 महीने में मास्टर प्लान का ब्लू प्रिंट तैयार करेगी।

आगरा के पास 40 हजार करोड़ रुपए से 10,500 हेक्टेयर में यह शहर बसेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र छह जिलों तक फैला हुआ है। प्रथम चरण में गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर को विकसित कर रहा है। दूसरे फेज में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस जबकि तीसरे फेज में आगरा को विकसित किया जाना है। सलाहकार चयनित कंपनी स्काई ग्रुप मास्टर प्लान- 2031 के तहत आगरा के पास बसाए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर में औद्योगिक, आवासीय, हरित क्षेत्र समेत सभी प्रकार की गतिविधि शामिल करेगी। कंपनी जनसंख्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क, पर्यावरण की स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति, सुविधाएं, उद्योग की स्थिति एवं संभावनाएं, कारोबार की स्थिति, यमुना नदी समेत मौजूद अन्य जल स्रोत की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर नौ माह में प्राधिकरण को सौंपेगी। न्यू आगरा में आवासीय के लिए 20, व्यवसायिक के लिए 4, उद्योग के लिए 25, ट्रांसपोर्ट के लिए 13, ग्रीनरी के लिए 15 व पर्यटन के लिए 7 और मिक्स लैंड यूज के लिए भी 7 फीसदी जमीन आरक्षित रहेगी।

न्यू आगरा की सबसे खास बात यह होगी कि यहां पर पर्यटन के साथ ही स्मोक लैस फैक्टरी और कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। यहां पर कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री नहीं होगी जो प्रदूषण पैदा करती हो। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके बाद आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। एक बार मास्टर प्लान को अप्रूवल मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की जाएगी।

गाजियाबाद में मामूली बारिश से कई स्थानों में जलभराव

● नाले का पानी श्याम पार्क में आया

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में मंगलवार दोपहर कुछ देर के लिए बारिश हुई। इससे गरमी से तो राहत मिली, लेकिन तमाम जगहों पर जलभराव हो गया। लोगों को निकलने में खासी मुश्किलें हुईं। नगर निगम के वार्ड-60 श्यामपार्क मैन गली नंबर-4 में नाले का पानी सड़कों पर आ गया।

सड़क पर करीब एक फीट तक पानी भर चुका था। गंदा पानी कई घरों में भी घुस गया। बच्चों की छुट्टी का वक्त हो रहा था, इसलिए उनको घर पहुंचने में काफी परेशानियां हुईं। स्थानीय लोगों ने बताया- साल 2019 में इस रोड पर नाले का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। इस वजह से हर बरसात में यहां ऐसा ही नजारा दिखता है। गाजियाबाद में मंगलवार दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये पूरे हफ्ते मौसम ऐसा ही रहेगा और बीच-बीच में बारिश होती रहेगी। हालांकि थोड़ी की बारिश से नगर निगम की पोल खुल जाती है। जलभराव को लेकर कोई तैयारी नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

विदेश में बैठकर व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार।

28 को होगा वाल्मीकि महासभा का सम्मेलन

गाजियाबाद। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की उत्तर प्रदेश कार्यसमिति का सम्मेलन 28 जुलाई को किया जाएगा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि सम्मेलन में महासभा के 22 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें वाल्मीकि समाज के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान, सफाईकर्मियों से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। महासम्मेलन लोहियानगर के हिन्दी भवन में होगा।

सुभासपा ने मनाई शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती

गाजियाबाद। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती मनाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा चन्द्रशेखर आजाद बाल्यकाल अवस्था से ही भारत माता को आजाद कराने के लिए अंग्रेजो के खिलाफ लडने लगे थे। पार्टी संयोजक सतेन्द्र यादव ने कहा आजाद ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनमें सम्पूर्ण भारत को समझने कि व क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करने की क्षमता थी। प्रदेश प्रभारी अनिल सिन्हा ने कहा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आजाद जैसे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को भारत की युवा पीढ़ी को बतलाना चाहिए। इस मौके पर अशोक तिवारी, मनोज कुमार शर्मा, अनिल मिश्रा, विनोद अकेला, अशोक शर्मा, डीसी माथुर, पवन सक्सेना, राजकुमारी यादव ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सुरेश यादव, राजीव गौतम, गोपाल सिंह, दीपक वर्मा, सुनील दत्त, प्रदीप पाठक, धीरेंद्र भदोरिया, डीसी माथुर, कमल यादव, पन्नालाल, संजय पासवान, संजय कुमार, राम गणेश सिंह, गणेश शर्मा, अशोक शर्मा, अजय श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, दिग्विजय सिंह, शिव कुमार, एनडी दीक्षित, राम नरेश ठाकुर, हरीश कुमार, सूरज सन्यासी, रणधीर कुमार, विकास कुमार, धर्मेंद्र यादव, राहुल, विनोद गुप्ता, राम गोपाल शामिल रहे।

5० लाख की वसूली पर मुख्यमंत्री से की शिकायत

नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के हाथीपुर खेड़ा गांव में महिला से 50 लाख रुपए वसूली की मांग की गई है । नहीं देने पर इकलौते बेटे को जान से मारने की धमकी देने को लेकर पुलिस से शिकायत की गई । पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान पीड़ित महिला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को पत्र भेज कर शिकायत की है । हाथीपुर खेड़ा निवासी राजवती परिवार के साथ रहती है । राजवती पर इकलौता बेटा प्रवीण नागर है । महिला पर परिवार के ही कुछ लोग 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं । और नहीं देने पर जमीन पर कब्जा कर लेने की धमकी दी जा रही है । साथ ही धमकी दी कि अगर समय रहते 50 लाख रुपए नहीं दिए तो इकलौते पुत्र प्रवीण को मार देंगे । जिससे भयभीत होकर पीड़िता ने डायल 112 नंबर पर पुलिस से शिकायत की गई थी । उसके बाद 25 मई को वह परिवार के साथ अपने खेत पर कार्य कर रही थी । तभी खेत पर आरोपी पहुंच गए । और अवैध असलहा दिखा पैसे की मांग को पूरा नहीं किया तो जमीन पर कब्जा कर वसूली करेंगे । पुलिस से शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई ।

महिला सुरक्षा को लेकर 29 को केन्द्र को घेरेगी कांग्रेस

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

महिला आरक्षण बिल लागू करने और महिला सुरक्षा को लेकर 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कांग्रेस विशाल प्रदर्शन करने जा रही है।

गाजियाबाद महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष सोनल नागर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि इस प्रदर्शन में जिले से पांच सौ महिला कार्यकर्ता शामिल होंगी। महानगर अध्यक्ष ने केन्द्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिला आरक्षण बिल लागू करने में क्यों देरी कर रही है। उसे लागू करने में सरकार क्यों पीछे हट रही है। महिला उत्पीडन् के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले के ही राकेश मार्ग पर युवती की हत्या कर दी गई, घूकना में बच्ची के साथ गलत काम किया गया। मध्यप्रदेश में दो महिलाओं को जिंदा दबाने का प्रयास किया गया। सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है यह सशक्तिकरण सिर्फ कागजों में हो रहा है। महिलाओं की स्थिति पर इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। महिलाएं अधिकार और न्याय के लिए भटक रही हैं।

किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएंः जिलाधिकारी

पायनियर समचार सेवा। नोएडा

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों क्रम में उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त कृषकों को बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्ययोजना को जारी किया गया है।

योजना को जनपद में संचालित करने हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को नामित किया गया है। खरीफ की फसल में धान एवं बाजरा तथा रबी की फसल में गेहूं की फसल को इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। फसल की बुवाई ना कर पाना /असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं रोगों, कीटों से क्षति. ओलावृष्टि जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सूखने हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में खरीफ में धान एवं बाजरा तथा रबी में गेहूँ अधिसूचित फसल है। धान की फसल में कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू 1682 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा। बाजरा में कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत (धनराशि रू 672 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा तथा गेहूं की फसल में कृषक अंश के रूप में 1.5 प्रतिशत (धनराशि रू 1157.25 प्रति हैक्टेयर) प्रीमियम लिया जायेगा।

यह योजना जनपद गौतमबुद्धनगर के सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषकों के लिये लागू होगी। ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है। यदि ऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते है तो उन्हें अपनी बैंक शाखा प्रबंधक को 24 जुलाई 2024 तक अनिवार्य रूप में लिखित में सूचित करना था।

सुरक्षा के मुद्दनेजर कांवड़ कंट्रोल रुम का निरीक्षण करते पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार व अन्य।

शहीदों को याद कर परिवारों का किया सम्मान

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीदों की वीरता को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस - शौर्य गाथा (माटी को नमन , वीरो का वंदन, शहीदों को शत- शत नमन) कार्यक्रम का आयोजन सभागार हाल में नगर पालिक पिलखुवा में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर शहीद चमन सिंह, शहीद सतपाल सिंह, शहीद धर्मपाल सिंह तथा वीर योद्धा सत्यनारायण यादव के परिवारों की उपस्थित रही। अतिर्थियों ने वीर परिवारों को शॉल, माला, पटका व सम्मान प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन पंकज शर्मा व आयोजन के.पी. सिंह की अगुवाई में हुआ।

अपने संबोधिन में विधायक धर्मेश ने पूर्व सैनिक व शहीदों के लम्बित कार्य शीघ्रता से करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कारगिल पर डाक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अनिल अग्रवाल, विधायक धर्मेश तोमर व पालिका अध्यक्ष विभु बसंल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विवेक सिंह, एटीएमएस चैयरमैन नरेंद्र अग्रवाल, एईडीसी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष शीशराम यादव, पूर्व अध्यक्ष सुखबीर और मानव अस्पताल के डायरेक्टर रजत गुप्ता ने विचार व्यक्त किए। संस्था के पूर्व अध्यक्ष डा. सुखबीर बीर ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर बीडी शर्मा, मनबीर, राजेश , उमेश त्यागी, प्रदीप राना, महिपाल, शेरावत, लोकेन्द्र, शाहिद अली, वेद प्रकाश, उमेश शर्मा व अनिल उपस्थिति रही।

बच्ची के अपहरण के मामले में महिला गिरफ्तार

● जेल से बेटा छुड़ाने को मौलवी के सामने कराना था सजदा, अंध विश्वास के चलते वारदात को दी अंजाम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

इंदिरापुरम इलाके से 20 जुलाई को अगवा हुई 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने सोमवार शाम सकुशल बरामद कर लिया।

अपहरण करने वाली महिला जानकार ही निकली। उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला का बेटा रेप केस में जेल में बंद था। किसी व्यक्ति ने कहा था कि बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए अबोध बच्चे से मौलवी के समक्ष सजदा करा दो। इसलिए ही महिला ने बच्ची का अपहरण किया था। स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया- मूल रूप से बिहार में लखीसराय निवासी रिंकू महतो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कनावनी झुग्गियों में पत्नी और तीन बेटियों संग रहता है। 20 जुलाई को पति-पत्नी मजदूरी करने गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो छह महीने की बेटी लापता थी। दूसरी बेटियों से पता चला कि परिचित महिला इदन खातून उर्फ रूबीना उर्फ नूरजहां आई थी और बच्ची को साथ लेकर चली गई। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में अपहरण का केस दर्ज किया और महिला को पक ?ने के लिए दो पुलिस टीमें लगाईं। आरोपी महिला इदन खातून को सोमवार शाम वसुंधरा रामलीला ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वो मूल रूप से जिला देवरिया में मईल थाना क्षेत्र के वगाही की रहने वाली है। उससे बच्ची को बरामद करके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया- मेरा बेटा लड़की भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद है। मैं बेटे को जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी। किसी ने मुझसे कहा कि बेटे को छुड़ाने के लिए एक उपाय करना होगा। वो ये कि किसी अबोध बच्चे से मौलवी के समक्ष सजदा करा दो। इसलिए मैंने बच्ची का अपहरण किया था।

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि फिलहाल ये महिला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहती है और उसका भतीजा कनावनी झुग्गियों के पास ही रहता है।

मोदीनगर में दलित छात्र के साथ अभद्रता का ऑडियो सामने आया

पायिनयर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद के मोदीनगर हापुड़ मार्ग स्थित एक निजी कॉलेज के संचालक पर दलित छात्र से अभद्रता करने का ऑडियो सामने आया है।

रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने लोगों के साथ भोजपुर थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हरिजन एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साढे छह मिनट के ऑडियो में मोदीनगर हापुड़ मार्ग स्थित ज्ञानस्थल कॉलेज के संचालक एक छात्र से अभद्रता कर रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे। इतना हीं नहीं वह जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि भास्कर वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत सदस्य अनिल गौतम व बसपा नेता मोहित जाटव ने सुबह के समय भोजपुर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि कॉलेज संचालक दलित समाज के बारे में आपित्तजनक टिप्पणी कर रहा है।

हजारों करोड़ टैक्स देने के बाद भी दिल्ली को कुछ नहीं मिला : आतिशी

● बोलीं, नगर निगम के लिए 10,000 करोड़ मांगा था

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि इसमें दिल्ली वालों को कुछ भी नहीं मिला। यह धोखा देने वाला बजट है।

मंत्री ने कहा दिल्ली देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक है। पिछले साल उन्होंने केंद्र सरकार को कुल 2.32 लाख करोड़ रुपये का कर चुकाया था। फिर भी दिल्ली को अपने शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटन नहीं मिलता है।केंद्रीय बजट एक बार फिर धोखे और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बजट साबित हुआ है।

आतिशी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन मे कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली को एक पैसा नहीं मिला है। दिल्ली वालों ने अपने आयकर का मात्र 5 फीसदी दिल्ली के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए माँगा था लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली को इतना भी नहीं दे सकी। करों में हिस्सेदारी के रूप में बाकी राज्यों को 1.24 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला।

लेकिन सर्वाधिक इनकम टैक्स देने वाले राज्यों में शामिल दिल्ली को एक पैसा नहीं मिला। केंद्रीय बजट में राज्यों की लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ रुपये का आवंटन लेकिन यहाँ भी दिल्ली को निराशा मिली और एमसीडी को भी एक पैसा नहीं मिला। भाजपा ने एक बार और स्पष्ट किया पिछले 11 सालों में उनकी केंद्र सरकार ने न तो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ किया है न ही करेगी।

हर बार की तरह भाजपा शासित केंद्र सरकार ने लोगों को उनका हक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि, जिस तरह से देश भर में स्थानीय निकाय को बजट का आवंटन होता है, वैसे ही दिल्ली नगर निगम के लिए बजट आवंटन होना चाहिए। हमारी माँग थी कि, दिल्ली के टैक्स का 5 फीसदी एमसीडी को मिलना चाहिए लेकिन एमसीडी को भी केंद्र सरकार से बजट में एक रुपया भी नहीं मिला।

ऐसा नहीं है कि, केंद्र सरकार ने और राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा नहीं दिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज से स्पष्ट है कि, इस वित्तीय वर्ष में 1.24 लाख करोड़ रुपये का बजट अलग अलग राज्यों को दिया गया है। उसी तरह लोकल बॉडीज को ग्रांट के रूप में 82,207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। लेकिन इस सब में दिल्ली को एक पैसा आवंटित नहीं किया गया है।

आतिशी ने कहा कि दिल्लनी देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन है। दिल्ली के लोगों ने पिछले साल केंद्र सरकार को 2.07 लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स और 25,000 करोड़ रुपये सीजीएसटी दिया था। इसके बदले 5 फीसदी हिस्सा मूलभूत ढांचा और 5 प्रतिशत हिस्सा साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए माँगा।

कुल मिलाकर केंद्र सरकार से मात्र 20,000 करोड़ रुपये की माँग की। जो उनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का मात्र 10 फीसदी है और ये केंद्र सरकार के कुल बजट का मात्र 0.4 प्रतिशत है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने न तो टैक्स शेयर में और न ही एमसीडी के लिये एक पैसा दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि,अब लोगों के सामने 2 मॉडल सामने हैं। एक मॉडल अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है। दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड़ रुपये का टैक्स दिल्ली सरकार को देते है। दिल्ली सरकार ने इन पैसों का इस्तेमाल चौबीस घंटे मुफ्त बिजली और पानी देने, अनाधिकृत कालोनियों में पानी का नेटवर्क डालने में, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने में, फ्लाई ओवर, सड़क बनवाने व बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को 2.32 लाख करोड़ रुपये टैक्स देते हैं लेकिन केंद्र सरकार इसमें एक पैसा नहीं देती है।

युवाओं के लिए लाभकारी है बजट: सचदेवा

● दिल्ली पुलिस, बुनियादी ढांचे के विकास, मेट्रो, आरआरटीएस, समेत कुल 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कुल करों का लगभग 30 फीसदी है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है, इसे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण के भारत को विकसित करने का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि अगले एक दशक या उससे अधिक समय तक भारत को सभी के लिए घर के एजेंडे पर काम करना होगा और जाहिर तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए आवास योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चालू वित्त वर्ष में आवास योजना निवेश में वृद्धि से दिल्ली के गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय आवास योजनाओं को लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है। सचदेवा ने कहा कि इसके अलावा, यह बजट महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी है क्योंकि यह सीधे तौर पर छोटे शहरों के नए नियुक्त युवाओं, दूसरी, तीसरी नौकरियों को अपना रहे हैं, को आयकर में राहत प्रदान करता है। 50 फीसदी मानक कटौती राहत पूरे वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। महिलाओं के विशेष प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल और बाल केंद्रों के विकास पर बढ़ते ध्यान से देश की कामकाजी महिलाओं को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली सरकार की मांग से कहीं अधिक देने और दिल्ली के लिए विभिन्न मदों के तहत आवंटन में लगातार वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है, जिससे दिल्लीवासियों को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली से एकत्रित प्रत्यक्ष करों का 10 फीसदी जो लगभग 21,000 करोड़ रुपये है, की मांग कर रही थी, लेकिन बजट विभिन्न सेवा शीर्षों के तहत दिल्ली से एकत्रित करों का लगभग 30 फीसदी वापस देता है। सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के लिए सीधे बजटीय आवंटन 1,168 करोड़ रुपये है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के परिचालन खर्चों के लिए 11,180 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 220 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा मेट्रो, एनएचएआई, आरआरटीएस, एनडीएमसी परिचालन खर्च, विभिन्न केंद्रीय अस्पतालों एम्स और आरएमएल आदि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की लागत, केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों के बजट आदि के शीर्षों के तहत आते हैं। कुल मिलाकर यह 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो दिल्ली से एकत्रित प्रत्यक्ष करों का लगभग 30 फीसदी है। दिल्ली सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह लोगों को गुमराह करना बंद करें क्योंकि वे केंद्र सरकार के योगदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसने दिल्ली को एक अच्छी राष्ट्रीय राजधानी बनाने में मदद की है।

विकसित भारत के सपने को साकार करेगा : बिधूड़ी

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को संपूर्ण बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। यह बजट विकसित भारत का रोडमैप है। वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प और सपने को यह बजट पूरा करेगा। बिधूड़ी ने कहा कि रक्षा के लिए सबसे ज्यादा धनराशि का प्रावधान भारत की संप्रभुत्ता और आधुनिकता के इरादे को साफ प्रकट करता है। शहरी विकास से लेकर गांवों में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। शहरी विकास का सीधा लाभ दिल्ली को मिलेगा। इसके अलावा सड़कों के विस्तार के लिए विशेष योजना बनाई गई है। वेतनकर्मियों को आयकर से छूट देकर उनकी मुराद पूरी की गई है। मोबाइल, कैंसर की दवाइयां, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरियां, सोने-चांदी पर ड्यूटी कम करने के साथ-साथ कपड़े और जूते पर टैक्स कम होने से आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बजट की संपूर्णता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि विपक्ष भी बजट में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा।

मूलभूत ढांचा, गरीबों के लिए आवास के प्रति उदासीनता : देवेन्द

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले बजट में दिल्ली की रक्षा, सुरक्षा, साफ-सफाई , ढांचागत विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों की रिहायश के प्रति उदासीनता दिखाई है। पूरा बजट निराशाजनक और कुर्सी बचाने वाला बजट दिखाई दिया, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के न्याय पत्र का कॉपी पेस्ट है। बजट देश की 95 प्रतिशत जनसंख्या की उम्मीदों से दूर रहा, गरीबों से किए गए वादों का बजट में विचार तक नहीं हुआ।

बजट-2024-25 पर क्या है राय

युवाओं के लिए बेहतरीन पहल

अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना एक बेहतरीन पहल है, इससे रोजगार क्षमता और करियर की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे आर्थिक विकास में बढ़ोतरी के साथ बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।

-नैन्सी खन्ना, कार्यवाहक प्रिंसिपल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल

युवा, महिला, ग्रामीण और एमएसएमई पर फोकस

कुल मिलाकर सरकार ने सभी लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब इन सब का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाएगा। सरकार का फोस युवा, महिलाओं, ग्रामीण और एसएसएमई पर रहा है। वहीं बैंकों सही तरीके से नई भर्ती करनी होगी। नहीं तो इन सब योजनाओं को लागू करने का सरकार का सपना पूरा नहों हो सकेगा। मिडिल क्लास को भी इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दिया है।

-अशवनी राणा फॉउंडर (वॉयस ऑफ बैंकिंग)

आयुष्मान योजना का बढ़े दायरा

केंद्रीय बजट चिकित्सा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। आयुष्मान योजना में लाभ की सीमा में बढ़ोतरी मरीजों के हित में करनी चाहिए थी। इसके अलावा दवाइयों और अन्य चिकित्सकीय सामान को जीएसटी दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। कैंसर की तीन दवाओं का सस्ता होना और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और एक्सरे पर छूट निश्चित रूप से राहत देने वाली है।

- डॉ. अनिल तोमर, चिकित्सा निदेशक नवीन अस्पताल समूह

एंजेल टैक्स समाप्त करना महत्वपूर्ण कदम

बजट काफी अच्छा है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स समाप्त करना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देगा और नवाचार को बढ़ावा देगा। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और महिलाओं के लिए एआई-संचालित अपस्किलिंग पर जोर लैंगिक समानता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

-डॉ. ख्याति शर्मा, निदेशक, प्रत्यक्ष मेडिकल केयर

आर्थिक बढ़ोतरी के उपाय वाला बजट

बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के कई प्रगतिशील उपाय पेश किए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट सतत विकास और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। युवाओं के लिए भी बजट में शिक्षा और कौशल विकास जैसे खास इंतजाम किया गया है।

-प्रशांत शुक्ला, जनरल मैनेजर, बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड

सभी के लिए संतुलित व बेहतर बजट

बजट सभी पहलुओं से संतुलित है। एंजल टैक्स को खत्म करने से निश्चित रूप से स्टार्ट-अप और उनके निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आई है। एमएसएमई के लिए यह प्रेरणादायक है। यह बजट नागरिकों के जीवन को आसान और बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

-अमित ठक्कर, संस्थापक एक्सेंचुएट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

आयुष चिकित्सा को मिलेगी नई दिशा

केंद्रीय बजट में 23.74 फीसदी की वृद्धि के साथ आयुष का बजट 3000 करोड़ से 3712.49 करोड़ होने से आयुर्वेद व अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। आयुष दवाओं के उत्पादन से उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके साथ दवाओं की टेस्टिंग और मानक में सुधार के साथ निर्यात में बढ़ोतरी होगी।

-डॉ. आरपी पराशर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (आयुष)

राजनीति से प्रेरित व शिक्षा के क्षेत्र में छलावा

वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट राजनीति से प्रेरित तथा खासकर शिक्षा के क्षेत्र में छलावा मात्र है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 63320.26 करोड़ का आवंटन अपर्याप्त है। इंटेक(आई) यूजीसी का बजट घटाने की भी निंदा करता है। सरकार को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

अश्विनी शंकर अध्यक्ष, इंटेक (आई)

युवाओं के लिए रोजगार का नया आयाम खोलना वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सर्वांगीण विकास की पहल की गई है। बजट में युवाओं के लिए की विशेष चिंता करते हुए वित्त मंत्री ने कौशल विकास और इंटर्नशिप का विशेष प्रावधान रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। यह देश में रोजगार के नए आयाम खोलेगी। छात्रों की शिक्षा के लिए होमलोन की सुविधा

युवा साथियों के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेगी। इंटर्नशिप से युवाओं को 12 महीने तक वास्तविक कारोबारी परिवेश, विविध व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा।

-डॉ. प्रभाशु ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है : विजेंद्र गुप्ता

● कहा-हर वर्ग का रखा ध्यान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मोदी सरकार के 2024-25 के बजट को सर्व समावेशी और सर्व स्पर्शी बजट है बताया है। साथ ही कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जनहितैषी नीतियों का प्रतिबिंब है। तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देने से मध्यम वर्ष को बड़ी राहत मिलेगी।

भाजपा विधायक ने कहा कि शिक्षा और कौशल पर विशेष ध्यान देकर मोदी सरकार ने रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दे को शांत करने का तो प्रयास किया ही है साथ ही युवाओं को विकसित भारत में उनके योगदान का आह्वान भी किया है। पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकान देने से करोड़ों गरीब परिवारों का अपने घर का सपना साकार हो सकेगा। यह बजट विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करेगा। बजट में शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करके युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। महत्वपूर्ण आर्थिक निवेश, कर राहत और नवीन रोजगार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का स्वागत किया। बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने और समृद्ध भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने के प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया।

गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर जोर देकर प्रगति के चार स्तंभों के लिए अवसर पैदा करने के प्रति ये बजट सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स के अवसर मिलने से युवाओं को लाभ होगा। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन की राह आसान बनाएगा।

'सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ वाला बजट'

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पेश केंद्रीय बजट को 'सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ वाला करार दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस बजट से देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों के हिस्से तो कुछ नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने टैक्स न बढ़ाकर कॉरपोरेट घरानों को राहत जरूर दी है।

यह बजट किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, अग्निवीर योजना को खत्म करने, ओल्ड पेंशन, पेट्रोल-डीजल समेत रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स में छूट पर पूरी तरह खामोश है। वहीं, पंजाब से आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि केंद्र सरकार जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है, उसमें 50 फीसद का योगदान अकेले पंजाब देता है।

फिर भी बजट में पंजाब को कुछ नहीं मिला। यह बजट पंजाब विरोधी है और वह इसे सिरे से खारिज करते हैं। संजय सिंह और मलविंदर सिंह कांग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश बजट में दो-तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, पिछले कई वर्षों से बजट की खुशहाली का अंदाजा शेयर मार्केट के गिरने और उठने से लगाया जाता है। मोदी सरकार का बजट आने के बाद शेयर मार्केट में करीब 12,00 अंक की गिरावट देखी गई। यानि इस बजट के आने के बाद शेयर मार्केट में भी कोई उत्साह नहीं है। दूसरा, बजट से उम्मीद लगाए अलग-अलग वर्गों के लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। देश का अन्नदाता किसान केंद्र के तीन काले कानून के खिलाफ एक साल तक सड़कों पर बैठा रहा। वह एमएसपी की मांग कर रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना किया जाएगा, लेकिन बजट में कोई प्रवधान नहीं है। जबकि 750 किसान शहादत दे चुके हैं और अभी भी सिंघु बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू समेत देश के अलग-अलग क्षेत्रों में आंदोलनरत है। मोदी सरकार ने किसानों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। उनको याद ही नहीं कि देश में किसान भी रहते हैं।

कृषि व किसान हितैषी है बजट : मोहिनी मिश्र

नई दिल्ली। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि भारतीय किसान संघ कृषि व किसान हितैषी तथा इनसे जुड़े क्षेत्रों के हित संवर्धन वाले इस बजट का स्वागत करता है। सरकार ने इस बजट में अनाज की अधिक उत्पादकता व प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिये अनुसंधान व शोध के लिये सरकार ने बजट में प्रावधान किया है।

साथ ही जलवायु के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिये 32 व बागवानी फसलों की अधिक उपज देने वाली नई 109 किस्में किसानों को देने की बात कही है, जो कि अच्छा कदम है। मिश्र ने आगाह करते हुए कहा कि अधिक उत्पादन के नाम पर यदि जी एम फसलों को अनुमति दी जायेगी तो किसान संघ इसका विरोध करेगा।

मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को बजट से निराशा : सीटीआई

नई दिल्ली। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बजट पर निराशा जाहिर करते हुए बताया कि देश और दिल्ली के 6 करोड़ व्यापारियों और मध्यम वर्ग परिवार को इस बजट से निराशा हुई है।

यह बजट राजनैतिक बजट ज्यादा नजर आया है और सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। मध्यम वर्ग परिवार की की चिंता है कि 10 साल से इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही बनी हुई है। इसको 7 लाख कर देना चाहिए था, क्योंकि सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने के बावजूद सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है।

इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ने से मिडिल क्लास के उन करोड़ों कारदाताओं को लाभ होता जिन्हें टैक्स ना होने के बावजूद रिटर्न जमा करानी पड़ती है। कार्पोरेट्स एवं बड़ी कंपनियों को बैंक लोन 8 - 10 फीसदी की ब्याज दर से मिल जाता है लेकिन मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केन्द्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उसको बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख जरूर किया गया है लेकिन उसमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है।

पटेल नगर में करंट लगने से युवक की मौत

नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पटेल नगर में भारी वर्षा के बाद कथित रूप से करंट लगने से सिविल सेवा परीक्षा के 26 वर्षीय एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्द्धन ने कहा, सोमवार को दो बजकर 43 मिनट पर रणजीत नगर थाने में सूचना आई कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक पावर जिम के पास एक व्यक्ति बिजली का करंट लगने से लोहे के गेट से चिपक गया। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने पाया कि लोहे के गेट में बिजली का करंट आ जाने से यह व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और सड़क पर पानी भी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान नीलेश राय के रूप में की गई है। वह सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इस घटना के सिलसिले में रणजीत नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, नौ महिलाएं समेत 20 गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए नौ महिलाएं समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी योजनाओं के तहत ऋण मुहैया कराने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इन लोगों को 400 से अधिक पीड़ितों से कुल 40 लाख रुपये की ठगी की है।

इनमें से 50 से अधिक पीड़ितों की पहचान पुलिस कर चुकी है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय इलाके से संचालित यह फर्जी कॉल सेंटर सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। डीसीपी ने बताया कि वे एकत्रित किए गए विवरणों का इस्तेमाल अपने खातों में पैसे हस्तांतरित करने के लिए करते थे। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को नौ महिला टेली-कॉलर्स समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कुल 32 मोबाइल फोन, 48 फर्जी सिम कार्ड, चार लैपटॉप और 23 बैंक खाते जब्त किए गए।

पक्ष ने बजट को कहा विकासशील तो विपक्ष ने बताया सरकार बचाने वाला

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए देश के आम बजट को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला बताया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों व आम आदमी को इस बजट से लाभ होने की बात कही है। वहीं, विपक्षी नेताओं ने इस बजट को मजबूरी का बजट बताया है। गठबंधन सरकार का यह बजट सिर्फ दो राज्यों पर केंद्रित बताया है और इसे बैसाखियों वाला बजट कहा है।

बजट देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला: पवन यादव:

जिला मीडिया सह-प्रमुख भाजपा पवन यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। देश के लिए नए रोजगार-स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा। बेहतर बजट है, इसलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। आने वाले समय में यह बजट देश को और आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस को बजट हजम नहीं हो रहा। देश का हर वर्ग इस बजट को बेहतर बता रहा है। औद्योगिक घरानों ने भी बजट की सराहना की है।

कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ की घोषणा: अमित गोयल:

भारत तिब्बत सहयोग मंच के हरियाणा प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि आम बजट में वित्त मंत्री की ओर से नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। यह अति सराहनीय है। देश को इसकी जरूरत थी। एजुकेशन लोन के ब्याज में छूट करते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। इससे गरीब छात्रों को पूरा लाभ होगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के आगे वित्तीय संकट नहीं आएगा। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर 3 लाख करोड़ खर्च करने की घोषणा का भी स्वागत है। अमित गोयल ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस करता है।

2047 तक विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट: सीकरी: बजट पर अपनी प्रतिक्रिया

में उद्योगपति बोधराज सीकरी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, अभिलाषाओं का यह बजट सराहनीय है। इस बजट में देश के गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जनभागीदारी का एक जन आंदोलन है। बजट में महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सराहनीय कदम है। देश में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक करोड़ किसानों को सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल खरीफ फसल सर्वे 400 जिलों में किया जाएगा। साथ ही 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण और सराहनीय घोषणाएं की हैं। जैसे बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

यह बजट मोदी की सरकार बचाओ योजना है: कैप्टन अजय यादव: हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री

कैप्टन अजय सिंह यादव ने बजट पर कहा कि इस बजट से ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बचाओ योजना है। बिहार और आंध्र प्रदेश को फंड आवंटन किया है। क्योंकि इन्हीं प्रदेशों की बैसाखी पर मोदी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में होने वाले चुनाव में भाजपा सरकार ने अपनी हार मान ली है। तभी इन प्रदेशों को कुछ नहीं दिया गया है। मोदी सरकार के इस बजट में आंध प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 60 हजार करोड़ का बजट में आवंटन किया है। जिससे पहले ही बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली है। कैप्टन यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। इस बजट में जनता को राहत देने वाला कुछ भी नहीं है। केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए संकट पैदा कर दिया है।

हरियाणा को बजट में कुछ ना देकर भाजपा ने मानी हार: पंकज डावर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज

डावर ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हरियाणा को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। यह हाल तो तब है जब हरियाणा में अगले दो महीने में चुनाव होने हैं। सरकार की इस कार्यशैली से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने हरियाणा में हार मानी ली है। यह हकीकत भी है कि हरियाणा में अब बदलाव होना निश्चित है। पंकज डावर ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। औचित्यहीन है। जिनकी बैसाखियों से सरकार चल रही है, उन राज्यों पर सरकार ने सब कुछ लुटाने का काम किया है। बाकी देश को झुनझुना पकड़ा दिया है। महिलाओं की सुरक्षा देश में अहम मुद्दा रहता है। इसे सरकार ने दरकिनार कर दिया। युवाओं को अस्थायी रोजगार की राह दिखाकर उन्हें भटकाने का काम किया है।

जनता को भ्रमित करने वाला है यह आम बजट: सुखबीर तंवर:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबीर तंवर ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने वाला है। रोजगार व महंगाई को लेकर बजट में कोई बात नहीं की गई। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रहीं। किसानों की समस्याएं जस की तस है। यह कुर्सी बचाओ बजट कहा जा सकता है। बिहार, आंध्रप्रदेश को लेकर जिस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है, उससे साफ है कि यह बजट सरकार ने अपने सहयोगियों, बड़े औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए बनाया है। आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। तंवर ने कहा कि यह बजट देश के विकास का नहीं है, बल्कि मोदी सरकार बचाने का बजट है।

अच्छे दिनों की आस लगाए आम, गरीब व मध्यमवर्गीय आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है। सोना, चांदी आम आदमी की सोच व पहुंच से बाहर है। अगर सरकार को कुछ सस्ता करना था तो रसोई पर ध्यान देती। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन व कमजोर तबके के उत्थान के लिए सरकार की नीति में कुछ नजर नहीं आ रहा।

बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं को मजबूत करने वाला है: दीपक मैनी: प्रोग्रेसिव

फैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी ने बजट को रोजगार पर केंद्रित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि बजट में विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। एमएसएमई के लिए टर्म लोन की क्रेडट स्कीम लाने की घोषणा बजट में की गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी देना भी विकासात्मक दृष्टि से बेहतर है। 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

बिजली के क्षेत्र में छोटे परमाणु रिएक्टर की स्थापना करके बिजली की किल्लत को खत्म करने का निर्णय भी सराहनीय है। पांच साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर देकर युवाओं को रोजगार की दृष्टि से मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की घोषणा बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगी। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान भी सराहनीय है।

सरकार ने सामाजिक विकास की प्रतिबद्धता दोहराई: शिशिर बैजल: नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष

एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट ने दीर्घकालिक सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 लाख करोड़ का परिव्यय, जो वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3.4 प्रतिशत हो गया है। देश में रेलवे, सड़कों और समग्र रसद बुनियादी ढांचे के विकास के एजेंडे का समर्थन करना जारी रखेगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 12 औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट बड़े उपक्रम हैं, जिनमें आर्थिक केंद्रों को विकसित करने के साथ रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा सराहनीय: रितु कटारिया: समाजसेवी रितु कटारिया

ने कहा कि बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा देने का निर्णय सराहनीय है। महिलाओं को बजट में विशेष महत्व देकर सरकार ने उनका सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आम, मध्यमवर्गीय कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल मिलने से उनमें काम करने के प्रति सकारात्मक सोच आएगी। वे निडर, निर्भर होकर काम करने के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि किराये के आवास को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल औद्योगिक श्रमिकों के लिए हॉस्टल का निर्माण महत्वपूर्ण बिंदू है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए 1.48 लाख करोड़ का घर खरीदने वालों की आय बढ़ाने में भी यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महिलाओं को रहने के लिए हॉस्टल सुविधा जरूरी: अन्नू यादव: समाजसेवी अन्नू यादव ने

कहा कि केंद्र सरकार ने आम बजट में महिलाओं के लिए जो हॉस्टल सुविधा में बढ़ोतरी करने की बात कही है, वह महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। उन्हें आर्थिक बचत भी होगी। अनेक महिलाएं अपने कामकाजी जीवन में खुद की सुरक्षा को भी महत्व देती हैं। उन्हें रहने के लिए सही जगह मिलती है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि देश को विकासशील बनाने में महिलाओं की भी अहम भूमिका है। ऐसे में महिलाओं को किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं रखा जा सकता।

देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बजट: चौहान

● बोले, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साबित होगा वरदान

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मंगलवार को संसद में पेश हुए बजट पर जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने ना केवल आम बजट पेश किया, बल्कि एक इतिहास भी बनाया है। लगातार सातवीं बजट पेश करने वाली वे देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं।

कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग तैयार किया गया है। यह आम बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय योजना किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि कुर्सी मिलने के बाद नेता जनता को भूल जाते हैं। इस कहावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असत्य साबित करते हुए किसानों,

महिलाओं, युवाओं और कामगारों को समर्पित व न्याय देने वाला बजट देश को दिया है। यह एक तरह से देश को आगे बढ़ाने, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की नीवं रखी है। बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों को भी तोहफा दिया गया है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा।

पांच साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की भी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। युवाओं के रोजगार के लिए इसमें जो रोडमैप बनाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है।

आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी सराहा

फरीदाबाद। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसएिशन ने बजट की सराहना की है। आईएमटी के प्रधान प्रमोद राणा ने कहा कि सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए।। मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख किया गया यह छोटे उद्योगों के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया है यह बहुत अच्छा कदम है तथा एक करोड़ युवाओ के लिए दो लाख करोड़ का बजट इन्टर्नसीप के अलग से प्रावधान यह प्रशंसनीय कदम है।

आईटी क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा: विशेषज्ञ

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

आम बजट को आईटी इंडस्ट्री ने क्षेत्र के लिए बेहतर बताया है। नए इनोवेशन, एआई तकनीक पर सरकार का फोकस बजट में नजर आया है। भारत को दुनिया में आईटी के क्षेत्र में मजबूत बनाने वाला यह बजट है। इसमें कोई दोराय नहीं कि आईटी उद्योग को यह बजट गति देगा।

बजट आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है: मोहित मलिक: आईटी

इंडस्ट्री से मोहित मलिक ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। ओवरऑल चीजों पर फोकस किया गया है। जीएसपीएएनएन टेक्नॉलोजिस के सीओओ मोहित मलिक कहते हैं कि एआई तकनीक, डिजिटलीकरण भारत का पहले से मोटो रहा है। हमारे पास ब्रेन इंजीनियर हैं। काफी अपोरच्यूनिटी हमें मिलेंगी। एक लाख रुपये तक की सेलरी वाले सभी कर्मचारियों के लिए योजना सराहनीय है। हमारे विकसित भारत के प्लान के लिए यह बजट बेहतरीन है।

एआई तकनीक में खुद को मजबूत करने वाला बजट: वेनू:

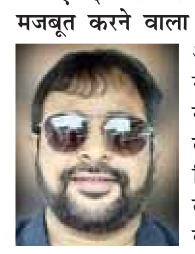

आईटी इंडस्ट्री से जुड़े वेनू ने बजट को लेकर कहा कि एआई तकनीक में वैश्विक दौड़ को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में खुद को तैयार किया है। दुनिया एआई को विकसित करने और तैनात करने के लिए तेज गति से इस पर काम कर रही है। ऐसे में भारत ने भी खुद को मजबूती से इसमें आगे बढना् शुरू किया है। इस पर किस गति से कार्य होता है, यह देखना होगा। वही गति भारत की भविष्य की सफलताओं को तय करेगी। जिस तरह से अमेरिका में सरकार ने एआई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संघीय एजेंसियों के लिए 4 बिलियन डॉलर से अधिक का बजट रखा है, उसी तर्ज पर भारत सरकार खास बजट एआई के लिए ला रही है।

रिसर्च व अन्य कार्यों के लिए बजट में प्रावधान सराहनीय: कुलदीप: आईटी कंपनी में सीनियर

टेक्निकल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कुलदीप कादयान ने कहा कि आईटी के एम्पलॉयज के नए स्लैब के अनुसार साल के साढ़े 17 हजार के करीब बचेंगे। यह अच्छी पहल है। साथ ही निजी क्षेत्र को रिसर्च व अन्य कार्यों के लिए एक लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सराहनीय है। जो कपंनियों ऑनलाइन ट्रेनिंग कराती हैं, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक्स में कस्टम ड्यूटी कम की गई हैं।

मोबाइल के अलावा चार्जर, अडॉप्टर सस्ते होंगे। कुलदीप कादयान ने यह भी कहा कि स्टार्टअप के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रखा गया है। इसके बिना इको सिस्टम बिल्डअप नहीं पाए। सरकार ने इसे मिस किया है।

कांग्रेस नेताओं ने विजय प्रताप को दी जन्मदिन की बधाई

फरीदाबाद। पूर्व चेयरमेन संजय कौशिक मंगलवार को कई अन्य कांग्रेसी कार्यकताओं के साथ बडखल विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप सिंह के सेक्टर-49 सैनिक कालोनी स्थित निवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। संजय कौशिक ने विजय प्रताप सिंह को पुष्प गुच्छा देकर व मिष्ठान खिलाकर भगवान से उनकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना की। संजय कौशिक ने कहा कि विजय प्रताप सच में महान है जिन्होनें जनता की भलाई और खुशहाली के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। उन्होनें कहा कि छोटे से छोटे कार्यकताओं का मान सम्मान करना कोई विजय प्रताप से सीखे।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मॉडल पर बनेगी जम्मू-कश्मीर में स्किल यूनिवर्सिटी

● जे एंड के अधिकारियों ने किया मॉडल का अध्ययन

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

जम्मू एवं कश्मीर में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के उद्देश्य से मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पहुंचा। कुलपति डॉ. राज नेहरू ने जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ कौशल विश्वविद्यालय के मॉडल पर विस्तार से चर्चा की। इससे पूर्व कुलपति डॉ. राज नेहरू जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू के साथ भी परामर्शी बैठक कर उन्हें कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में सुझाव दे चुके हैं। इस योजना को धरातल पर लाने के मकसद से अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मॉडल का अध्ययन करने पहुंचा है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कौशल विकास के निदेशक सुदर्शन कुमार, कौशल विकास के संयुक्त निदेशक फारूक अहमद खान, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किश्तवाड़ के प्रिंसिपल मेहमूद अहमद खान, कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक रवि गुप्ता और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अनंतनाग के लेक्चरर शकील अहमद डार शामिल हैं।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा की अगुवाई में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उच्च शिक्षा में स्किल एजुकेशन मॉडल के विभिन्न आयामों पर अपनी प्रेजेन्टेशन दी।

हाईवे टीमों ने हटाया अतिक्रमण, मची खलबली

फरीदाबाद। हाईवे घटना प्रबंधन टीमों ने जेसीबी चौक से लेकर बल्लभगढ़ बस स्टैंड तक आरओबी में स्थित रेहडी, अवैध पार्किंग और खोखों को हटाया। इससे अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। टीमों ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि उन्होंने दोबारा अतिक्रमण किया तो पुलिस की उपस्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि मंगलवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें झाडसेतली, जेसीबी चोक और बल्लभगढ़ में हाईवे किनारे रखे खोखो, रेहड़ियों और अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों को हटाया गया।

गरीबों को सशक्त बनाने वाला है बजट: राजकुमार

● वित मंत्री निर्मला सीतारमण को सर्वस्पर्शी, जन हितैषी बजट के लिए दी बधाई

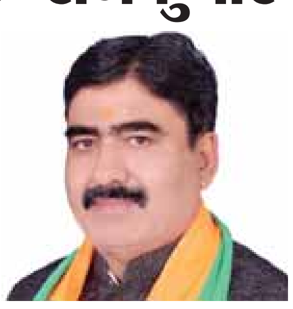

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा ने कहा कि मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट जनता की आशाओं के अनुरूप है और गरीबों को सशक्त करने वाला है। इस बार का बजट सर्वस्पर्शी व सर्व हितैषी है और महिला, गरीब, युवा किसान एवं मध्यम वर्ग के पक्ष में है। यह सर्वग्रही बजट नए भारत को विकास के पथ पर तीव्रता से आगे लेकर जायेगा।

भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व भारत का आर्थिक विकास देख रहा है। युवाओं को नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का बजट, 30 लाख युवाओं को नौकरी, 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, नए 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी, छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम, मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना, नेचुरल फार्मिंग पर रहेगा फोकस, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़, 25 हजार गांवों में पक्की सड़क, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर, 109 फसलों पर रहेगा सरकार का फोकस, 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन, 30 लाख की आबादी वाले शहर के लिए नई ट्रांसपोर्ट योजना, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती करना, शिक्षा लोन पर ब्याज 3.0 करना, न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर टैक्स में छुट, प्राइवेट जॉब में भी एनपीएस 14 प्रतिशत तक करना आदि महत्वपूर्ण निर्णय है जिनसे देश में विकास के साथ देश का आम जनमानस और अधिक सशक्त होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित मंत्री निर्मला सीतारमण को सर्वस्पर्शी, जन हितैषी और देश के विकास में सहायक इस बजट के लिए बधाई दी।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आवेदन आमंत्रित

फरीदाबाद। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर पलवल के सत्र 2025-26 में कक्षा 06 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक विद्यार्थी आगामी 16 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर के प्राचार्य ब्रजमोहन रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमानुसार छात्र-छात्राओं का आरक्षण आरक्षित होगा। सत्र 2024-25 में पलवल जिला में कक्षा 5वीं में पढाई कर रहे सरकारी, मान्यता प्राप्त एवं गैर सरकारी संस्थान के विद्यार्थी जिनकी जन्म तिथि 01 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच है, वह आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा आगामी 18 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी।

नर्सिंग ऑफिसर्स का विरोध शुरू, 28 को घेरेंगी सीएम आवास

● मांगों के समर्थन में नर्सिंग ऑफिसर्स ने दिखाई एकजुटता

● 28 जुलाई से पहले सरकार से मांगें पूरी करने का किया आग्रह

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

वर्षों से लम्बित पड़ी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मंगलवार को ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले गुरुग्राम जिला के सभी नागरिक अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच में नर्सिंग ऑफिसर्स ने एकजुटता दिखाई। सभी ने ब्लैक बैज लगाकर स्वास्थ्य विभाग, सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की गुहार लगाई।

ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले

गुरुग्राम के सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर ब्लैक बैज लगाए हुए नर्सिंग ऑफिसर्स।

यहां नागरिक अस्पताल सेक्टर-10 में ब्लैक बैज लगाकर एकजुट हुईं नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के समान नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये किया जाए। साथ ही उन्हें ग्रुप-सी से ग्रुप-बी में शामिल किया जाए। वर्षों से एसोसिएशन इन मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है, लेकिन आज तक इन पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही ठोस जवाब दिया है। इसे लेकर हरियाणा के नर्सिंग ऑफिसर्स में रोष है। नर्सिंग ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि वैसे तो उन्हें अस्पतालों की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन उनकी मांगों को मानने के लिए स्वास्थ्य विभाग, सरकार कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ दो ही मांगों को लेकर वे वर्षों से अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जिस जिम्मेदारी से नर्सिंग ऑफिसर्स काम करती हैं, उस तरह की जिम्मेदारी सरकार को भी निभानी चाहिए। पहले जहां नर्सिंग ऑफिसर्स का काम सिर्फ मरीजों के उपचार तक सीमित था, अब उनका काम और अधिक बढ़ा दिया गया है। उपचार करने के अन्य कार्यों में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नर्सिंग ऑफिसर्स उपचार के अलावा बाकी कामों में भी अपनी भरपूर योगदान देती हैं।

नर्सिंग ऑफिसर्स से उम्मीदें तो बहुत जताई जाती हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को दरकिनार किया जाता है। ब्लैक बैज लगाकर अपनी मांगों को उठाते हुए नर्सिंग ऑफिसर्स ने कहा कि सरकार इस सांकेतिक विरोध को देखते हुए उनकी दो प्रमुख मांगों को 28 जुलाई से पूरा करे। ऐसा नहीं किया जाता है तो 28 जुलाई को प्रस्तावित करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेशभर से नर्सिंग ऑफिसर्स करनाल पहुंचेंगी। ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की ओर से यह जानकारी दी गई कि मंगलवार को पूरे प्रदेश के छोटे-बड़े सरकारी अस्पतालों में ब्लैक बैज लगाकर नर्सिंग ऑफिसर्स ने विरोध जाहिर किया। शत-प्रतिशत नर्सिंग ऑफिसर्स की इसमें भागीदारी रही।

बजट में हर वर्ग के लिए राहत: सीएम

● रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा: बड़ौली

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश सरकार ने सराहना की है। सत्ता पक्ष ने इसे भविष्य के विकास वाला बजट करार दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है।

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग का पूरा-पूरा ख्याल रखा है। बडौली ने 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार देने वाले इस बजट का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।

हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ.सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दूरदृष्टि से बनाया गया समग्र और समावेशी बजट बताया है। पूनिया ने इसे किसान, युवा, महिला और गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट तो ट्रेलर है, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता स्वर्णिम युग की है। खेती किसानी के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट सामान्य बात नहीं है। मोदी सरकर का किसानों के प्रति समर्पण है।

मोदी सरकार ने ऐसी 25 हजार बस्तियों को चिन्हित किया है जिन्हें सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम सड़क योजना के तहत अब तक 6 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डा. पूनिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा सुधरी है। मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

भाजपा हरियाण के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी और लचीलापन आएगा। रोजगार एवं कौशलता बढ़ेगी।

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट को विपक्ष ने पूरी तरह से नकारते हुए हरियाणा के लिए निराशाजनक करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष **भूपेंद्र सिंह हुड्डा** का कहना है कि केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी निराशा हाथ लगी है। बजट में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया।

हुड्डा ने कहा कि इस बजट ने देश के किसान, छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास, गरीब और गृहणियों को भी पूरी तरह निराश किया है। क्योंकि लगातार महंगाई और भारी टैक्स की मार झेल रही जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं दी गई। किसान के हाथ एक बार फिर खाली रहे और एमएससी गारंटी पर यह बजट खामोश रहा। किसान सम्मान निधि की राशि में भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई। जून 2022 में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या 11.39 करोड़ थी, जो अब घटकर 9.26 करोड़ रह गई है।

बेरोजगारी पर नकेल कसने को लेकर भी बजट में कोई रोडमैप नजर नहीं आया। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए बीजेपी ने बजट पेश करने की एक औपचारिकता निभाई है। हुड्डा ने कहा कि बिना

आम आदमी को कोई राहत दिए सरकार द्वारा लगातार देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस बार भी कर्जे में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद **रणदीप सुरजेवाला** ने बजट के बाद जारी बयान में कहा कि हरियाणा में तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद थी की केंद्र के बजट में प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से धरना दे रहे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।

हरियाणा को जल्द मिलेंगे पांच हजार होमगार्ड

● पुलिस विभाग के प्रस्ताव को गृह विभाग ने दी मंजूरी, डीजीपी ने की थी छह हजार की मांग

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पांच हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। पहले चरण में इन जवानों की तैनाती 30 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षकों की मांग पर अगला फैसला लिया जाएगा। यह फैसला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है।

होमगार्ड जवानों की नियुक्ति तीन माह की होगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से छह हजार होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की डिमांड भेजी थी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंजूरी का छह हजार की जगह पांच हजार जवानों की भर्ती को हरी झंडी दे दी है।

गृह सचिव की मंजूरी के बाद डीजीपी ने इस संदर्भ में सभी रेंज के एडीजीपी/ आईजी, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (होमगार्ड) को पत्र जारी करके इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य में होमगार्ड के 14 हजार 25 स्वीकृत पद हैं, जिसकी एवज में 11 हजार 98 कार्यरत हैं। अब पांच हजार अतिरिक्त होमगार्ड नियुक्त किए जाएंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पुलिस के सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

होमगार्ड जवानों की तैनाती पहली अगस्त से 31 अक्टूबर तक इनकी नियुक्ति रहेगी। इस दौरान हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी सम्पन्न हो चुके होंगे। यानी विधानसभा चुनावों के बाद होमगार्ड जवानों की जरूरत नहीं रहेगी। इस संदर्भ में डीजीपी ने होमगार्ड के कमांडेंट जनरल तथा सिविल डिफेंस के निदेशक को भी पत्र लिखा है।

कहां कितनी होगी नियुक्ति

जिला	संख्या	जिला	संख्या
सोनीपत	300	दादरी	100
गुरुग्राम	300	भिवानी	200
फरीदाबाद	300	हिसार	200
पंचकूला	200	हांसी	100
अंबाला	100	सिरसा	200
कुरुक्षेत्र	100	फतेहाबाद	100
यमुनानगर	200	जींद	200
करनाल	200	डबवाली	200
कैथल	200	रेवाड़ी	200
पानीपत	200	महेंद्रगढ़	300
रोहतक	300	पलवल	300
झज्जर	300	नूंह	200

जीएमडीए के प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी

चंडीगढ़। उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का निर्माण और सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, सोहना में लगभग 17 करोड़ की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बड़खल में 16 करोड़ की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें, 290 करोड़ की खरीद को मिली मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

● सीएम की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

हरियाणा रोडवेज के बेड़े में अब 650 नई बसें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

बैठक में परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने के लिए रखे गए 150 एसी बसों तथा 500 सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन बसों की खरीद पर लगभग 290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। बैठक के बाद जारी की गई जानकारी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत आज बीमा कंपनियों का चयन किया गया है।

मेवात और हरियाणा कैडर में होगी शिक्षकों की भर्ती

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये 4216 शिक्षकों को ऑफर लेटर भेजने के बाद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने तीन हजार पीजीटी की भर्ती करेगा। आयोग की ओर से मंगलवार को इस आशय में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

एचपीएससी की ओर से मेवात और शेष हरियाणा कैडर के तहत 20 विषयों में 3069 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती मैथ और फिजिक्स विषय में होंगे। एचपीएससी की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 25 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को आयु में पांच-पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिला को भी पांच-पांच साल और अन्य निर्धारित की गई श्रेणियों में भी नियमानुसार छूट मिलेगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 7 हजार युवाओं को ऑफर लेटर भेजे थे। इनमें 4216 शिक्षक, 650 चपरासी, 787 सफाई कर्मी, 466 चौकीदार, 226 पटवारी, 52 ड्राइवर, 50 शिफ्ट अटेंडेंट, 14 स्टाफ नर्स, 22 लीगल असिस्टेंट तथा 24 सहायक लाइनमैन सहित अन्य पद शामिल थे।

सीएम ने दिए कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा के निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए उन्हें कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था सुचारू रहे।

इसके साथ ही कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग से लेन बनाई गई है। श्रद्धालुओं के रात्रि ठहराव के लिए रूटों पर सामाजिक संगठनों द्वारा शिविर भी स्थापित किए गए हैं जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि 2 अगस्त को शिवरात्रि का त्यौहार है ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से पैदल चलकर कावड़ लेकर आते हैं जिसका पवित्र जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा। जिन मार्गों से श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ लाई जाती है उन सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा व कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही दुर्घटना संभावित स्थानों तथा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।

किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का निर्णय ऐतिहासिक: नवीन जिंदल

कुरुक्षेत्र। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों को जोडने का जो इनीशिएटिव उन्होंने लिया था। उसे लेकर केंद्र सरकार ने रुचि दिखाई है। हाल ही में उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर प्राकृतिक खेती के इस कांसेप्ट को बढ़ावा देने संबंधी बात की थी। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मंगलवार को प्रस्तुत किए गए बजट में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रावधान सरकार ने तय किया है।

सांसद जिंदल ने कहा कि यह विषय लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि बंजर और जहरीली हो रही भूमि को बचाने का एकमात्र जरिया प्राकृतिक खेती है। यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड की परत ने मिट्टी को इस कदर सख्त बना दिया है कि जमीन में पानी जाने के लिए रिसाव के छेद भी बंद होने लगे हैं। इसी वजह से जमीन बरसात का भी पूरा पानी अंदर नहीं सोख पा रही। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मिलकर उन्होंने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में उनकी ओर से स्टाफ की लगभग 20 सदस्यों की टीम व उनके आग्रह पर 8 से 10 किसान गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र में संबंधित विषय की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के उपरांत ये लोग किसानों के बीच जाएंगे।

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client SHRI SUMIT JINDAL has revoked his power of attorney executed on 10.07.2024 pertaining to **ROOM PVT. No. 300, ON THIRD FLOOR, PART OF PROPERTY No. 2605 to 2611, SITUATED AT WARD No. III, GALI NAI BASTI, ZARA FASEEL, NAYA BAZAR, DELHI, in favor of S. JASJOT SINGH** as it was a fraudulent act done by some fraud persons with the active connivance of JASJOT SINGH. My client never intended to execute any power of attorney in favor of JASJOT SINGH as he is completely a stranger for my client. If anybody deals with JASJOT SINGH regarding the said shop the same shall be treated as the cheating and fraud with my client and he would be enal provisions.

RAVI BHARGAVA (Advocate)

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client SHRI SUMIT JINDAL has revoked his power of attorney executed on 10.07.2024 pertaining to **SHOP PVT. NO. 212, ON SECOND FLOOR, PART OF PROPERTY No. 2605 to 2611, SITUATED AT WARD No. III, GALI NAI BASTI, ZARA FASEEL, NAYA BAZAR, DELHI, in favor of S. JASJOT SINGH** as it was a fraudulent act done by some fraud persons with the active connivance of JASJOT SINGH. My client never intended to execute any power of attorney in favor of JASJOT SINGH as he is completely a stranger for my client. If anybody deals with JASJOT SINGH regarding the said shop the same shall be treated as the cheating and fraud with my client and he would be liable provisions.

RAVI BHARGAVA (Advocate)

सार्वजनिक सूचना

श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता की ओर से आम जनता को सूचित किया जाता है कि संपत्ति का पता :- संपत्ति संख्या 109/ए, पटपड़गंज गांव में स्थित, खसरा नंबर 109/ए में से, पटपड़गंज गांव, खसरा नंबर 490/106 में से, गांव घरोंदा नीम का बांगर उर्फ पटपड़गंज, दिल्ली-110091 में स्थित संपत्ति के मालिक है। जो पंजीकृत त्याग विलेख दिनांक 09.10.2017 (1) श्री गिरिराज गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता, (2) श्री महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता, (3) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता (4) श्रीमती शशि प्रभा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता (5) श्री सुमित कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री अरुण गुप्ता के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता के पक्ष निष्पादित संपत्ति का क्षेत्रफल 66 वर्ग गज, SR-VIII-नई दिल्ली के कार्यालय में बुक सं. 01, खंड सं. 3180, पृष्ठ 122/124 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार है। श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नी लाल गुप्ता इस संपत्ति को सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास गिरवी रख रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार/स्वामित्व/हित/बंधक बनाने में कोई आपत्ति है तो वह आज से 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों के बारे में नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में सूचित कर सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार, ग्रहणाधिकार आदि से मुक्त है। दीपांशु शर्मा, अधिवक्ता 12A, 14 S3 टावर ऋषभ क्लाउड-9, वैशाली गाजियाबाद, उ.प्र-201010

Public Notice

This is to inform the general public that **Mrs. Kanta Salhotra** purchased entire Property No. 139, area measuring 70 Sq. Mtrs. situated in Block A Prashant Vihar Delhi 110085 vide Sale Deed dated 21.07.2006 as Doc No. 12686 executed by Sh. Bipan Behari Saxena in favour of Smt. Kanta Salhotra. Unfortunately, Mrs. Kanta Salhotra died on 23.07.2008 and as per SMC shared with us, she left behind Mrs. Anshu Salhotra and Mrs. Shipra Sudan as her legal heirs who acquired Property No. 139 in Block A Prashant Vihar vide succession.
Mrs. Anshu Salhotra and Mrs. Shipra Sudan intends to transfer the Upper Ground Floor without roof rights of aforementioned property by way of Sale Deed to **Ankit Bansal.** Subsequently, **Ankit Bansal** is in the process of mortgaging the said **RBL BANK.** Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.
If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-day period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in**

PUBLIC NOTICE

Public notice regarding mortgage/cancellation of property as per Terms of the Tripartite Agreement.

This Public notice is from JKG Construction Private Limited for Aakash Gupta bearing unit no B2-1106 JKG Palm Court Plot No GH-1D Sec 16C Greater Noida West Uttar Pardesh-201009 With reference to the cancellation notice received form HDFC Bank dated 02.03.2024 for cancellation of aforesaid unit in lieu of default in payment of Emi/Pre-Emi towards Home Loan Account no **623701448** and Baldeep Aurora unit no D-1701 Loan Account no **616016957**. The bank is invoked the provisions of the Tripartite Agreement entered between you as Borrower, **JKG Construction Private Limited and HDFC BANK LTD** and has asked us to refund as per terms of the Tripartite Agreement.

This is further to inform you that we are refunding the amount to HDFC BANK LTD towards cancellation of the given unit after forfeiting the amount as per terms of the Builder Buyer Agreement on cancellation of the given unit. Further to the cancellation and refund to the Banker you as allotee/ owner of the given unit will have no claim on the given unit.

प्रपत्र-3

[विनियम -15(1)(क)]/16(2) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. ओए/204/2024

Exh. No. 22513

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

बनाम

कल्पना जैन

सेवा में,

(1) कल्पना जैन पुत्री/पत्नी/पुत्र विवेक जैन कल्पना जैन पत्नी श्री विवेक जैन, निवासी फ्लैट नं. 701, 7वीं मंजिल, टावर पी, सुपरटेक ह्यूज, गांव बादशाहपुर, सेक्टर 68, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001
दूसरा पताः- मकान नंबर 10, रोजवुड सिटी, सेक्टर 49-50, गुरुग्राम हरियाणा- 122001
तीसरा पताः सी/ओ प्लेनेट नीड्स, दुकान नंबर 6, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिसपाल विहार, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001, गुड़गांव, हरियाणा
औरः मकान नं. 10, रोजवुड सिटी, सेक्टर 49 50, गुरुग्राम, हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा -122001
औरः
प्लेनेट नीड्स, दुकान नं. 6, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिसपाल विहार, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा, गुड़गांव, हरियाणा- 122 001
(2) उत्कर्ष जैन, मकान नं. 10, रोजवुड सिटी, सेक्टर 49 50, गुरुग्राम, हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा- 122001
(3) विवेक जैन, डी 10, तीसरी मंजिल, रोजवुड सिटी, सेक्टर 49, 50, साउथ सिटी ।।, गुरुग्राम, हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा - 122001

सम्मन

जबकि, ओए/204/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **20.04.2024** को प्रस्तुत किया गया था।
जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. **58,29,635.50** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-
(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;
(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;
(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;
(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।
आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **24/07/2024 को पूर्वा. 10.30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **22.04.2024** को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Shankar Ram, S/o Divan Ram, R/o H.No-229, New Defence Colony, 4 Muradnagar, Modinagar, Ghaziabad, UP-201206 have changed my name from Sunder Singh to Shankar Ram for all future purposes.

PD(618)C

I, Divan Ram, F/o Shankar Ram, R/o H.No-229, New Defence Colony, 4 Muradnagar, Modinagar, Ghaziabad, UP-201206 have changed my name from Diwan Singh to Divan Ram for all future purposes.

PD(619)C

I, Poonam, W/o, Ashok Kumar, R/o, K-217-18, IInd Floor, Jahangirpuri Delhi-33, that my name wrongly written in Bank Passbook. I, have changed my name from Poonam to Poonam Wadhwa.

PD(617)C

I, Khushboo Agrawal, D/o Binod Agrawal, aged about 38 years, currently residing at Flat No 1-A-111, G C Grand, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad-201014, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm declare that my name mentioned in my passport as Khushaboo Agraval instead of Khushboo Agrawal. Hence Khushaboo Agraval and Khushboo Agrawal both are same and one person.

PD(620)C

मैं, सुखदेई मलिक पत्नी श्री जगजीत सिंह मलिक निवासी म0न0-11/31 मलिक कालोनी गोहाना रोड निकट छोटूराम चौक सोनीपत। मेरा नाम सुखदेई और सुखदेई मलिक है जो कि ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं भविष्य में मुझे सुखदेई मलिक से ही जाना जाये।

PD(622)C

LOST & FOUND

I, Sanjay Gupta have lost original sale deed of my company name Manesar Developers Private Limited. The sale deed was executed as on 03.07.2007, with reg. No. 7434 of land falling Under khasra no. 42/ 12/2, 42 13/2, 42/ 14/2, 42/ 17/1, 42/ 18/1 and 42/ 19/1 measuring a total of 20 kanal-17 marla in village-nakhraula, dist.- Gurgaon, Haryana. If someone finds the documents please contact 981016733

PD(621)A

सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि विनीता चौधरी, सम्पति Flat No. 301 on Second Floor, without roof rights, covered area 56.435 Square Meters, out of Khasra No. 6, Situated at Village-Dargal, Pargana Jalalabad, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. को अमली देवी को बेचना चाह रही है जो मेरे मुवक्किल हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा-प्रथम तल, प्लॉट नं.-17, संजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201003 द्वारा वित्तपोषित व बंधक प्रस्तावित है ! उपरोक्त संपत्ति के स्वामित्व सम्बंधित मूल दस्तावेज़ विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2019 का मूल पंजीकरण पृष्ठ कही गुम हो गए है जिसका दस्तावेज़ संख्या 12854, जिल्द संख्या 16123, बही संख्या 1 पृष्ठ संख्या 85-134, इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश को सूचना शिकायत L.A.R. No. 20240000607901 दिनांक 22.07.2024 में दर्ज करवाई गई है।
यदि उपरोक्त मूल दतावेज़ किसी भी व्यक्ति के कब्जे में हो तो कृपया हमे इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित पते पर संपर्क करें! उपरोक्त गुम हो गए मूल दस्तावेज़ों के आधार पर उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा अमान्य माना जाएगा!

राघव तिवारी, अधिवक्ता
830, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली 110001
Mob.:+91-8076188328

PUBLIC NOTICE

General public is hereby Informed that my client Kalwinder Singh R/o GH-14, H. No. 137, MIG Flat. Paschim Vihar, Delhi, has severed all his relations and ties from his son Amander]eet Singh and his wife Simran Kaur due to their disobeying, misbehaving and threatening attitude and behaviour towards my client. My client has disowned and debarred them from his entire movable and Immovable properties and anyone dealing with said person in future In any manner shall do so at their own risk and consequences and my client shall not be responsible for any acts and deeds done by said son and daughter-in-law In future.

RAJESH KUMAR (ADVOCATE) Seat No -67, P.S. Rathi Block, Tis Hazari Courts Delhi -54

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **उमाकांत और अनिता** को **17.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOD00353076** की राशि **रू.19,30,443.82 /- (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार चार सौ तैंतालीस और बयालीस पैसे मात्र)** और **26.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके **19.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।
विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.19,30,443.82 /- (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार चार सौ तैंतालीस और बयालीस पैसे मात्र) 26.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.1103, ग्यारहवीं मंजिल, टॉवर-ए, महालक्ष्मी ग्रीन मेंशन, एचआरए-14, सूरजपुर साइट-सी. जी.नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201303।

दिनांक :19.07.2024
स्थान :गौतम बुद्ध नगर

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

ELECTION PROGRAMME

Election programme for the election of the Managing Committee of The Pataudi Primary Agriculture Co-operative Society Ltd., Pataudi to be held on 01.09.2024.

SR.NO.	PARTICULAR	DATE	TIMES	PLACE
01.	Exhibition of List of voters as required under Sub Para(2) of rule 35 and objection on the list of Voters will be submitted on the last day Exhibition of Voter list in the office of Assistant registrar, Coop. Societies Gurugram	19-07-2024 to 29-07-2024	9:00 a.m. to 5:00 p.m.	(1). In the Regd. Office of the Society & Village failing in the area operation of the Society. (2). Assistant Registrar Co-operative Societies, Gurugram Near John Hall Civil Line, Gurugram (3). Central Cooperative Bank, Gurugram
02.	Hearing of objection of the list of voters as required under sub para(4) of rule 35	30-07-2024	10:00 a.m. to 3:00 p.m.	ARCS Office, Gurugram
03.	Filing of Nomination Papers.	09-08-2024	10:00 a.m. to 2:00 p.m.	In the office of Assistant Registrar, Co-operativeSocieities, Gurugram, Near John Hall, Civil Line, Gurugaon
04.	Scrutiny of Nomination Papers.	13-08-2024	10:00 a.m. to 2:00 p.m.	---------- Do-------------
05.	Display of List of Validity nominated Candidates.	13-08-2024	4:00 p.m.	---------- Do-------------
06.	Withdrawal of Nomination Paper display of list of candidates.	16-08-2024	10:00 a.m. to 2:00 p.m.	---------- Do-------------
07.	Allocation of Symbols	16-08-2024	03:00 p.m.	---------- Do-------------
08.	Display of List of contesting candidates.	16-08-2024	04:00 p.m.	---------- Do-------------
09.	Taking of poll, if necessary.	01-09-2024	08:00 a.m. to 4:00 p.m.	In the premises as per list of booth attached.

Note:- (1) Election of the Managing Committee of the said society will be held as per section 28 ibid of the Haryana Cooperative Societies Act 1984 (2) Election will be held as per orders of Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in BejulSomaia Vs. State of Haryana in CWP no. 3648 of 2007

(Devender Beniwal)
Assistant Registrar, Co-operative Societies, Gurugram, (Returning Officer)

ICICI Bank **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।
सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार(रों)/ सह-कर्ज़दार(रों)/ ज़मानतदार(रों) के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	वंदना सिन्हा (आवेदक), कमलेश कौर सिन्हा (सह आवेदक) ऋण खाता संख्या LBDEL00003217779	संपत्ति बेयरिंग संख्या आर जेड-एफ-1/49, प्लॉट संख्या 49 पर, गली नंबर 1-ए, संपूर्ण प्रथम तल बिना छत अधिकार के और एक छोटी कार पार्किंग स्थान के साथ, खसरा संख्या 88/7 से बाहर, ग्राम पालम के राजस्व स्टाम्प में स्थित, महावीर एन्क्लेव दिल्ली-110045 क्षेत्रफल- 900 वर्ग फीट	रु. 36,49,710/- (जुलाई 20, 2024 तक)	रु. 57,00,000/- / रु. 5,70,000/-	अगस्त 05,2024 को दो. 02:00 बजे से दो. 04:00 बजे तक	सितम्बर 04, 2024 को सु. 11:00 बजे से दो. 12:00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **URL Link- https://www.bankeauctions.com** पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **सितम्बर 03, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/इन संरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बोलीकर्ता(ओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम **ई** देखें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005** में **सितम्बर 03, 2024** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज (छायाप्रति) **सितम्बर 03, 2024** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। यदि संभावित बोलीकर्ता(ओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **सितम्बर 03, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैड्यूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।
संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** कर्मचारी के फोन नंबर 8928935040/8584874809 पर संपर्क करें।
कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसी **1. मेसर्स नेक्सझेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ऑगियो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. हेक्टा प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न है।
प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : जुलाई 24, 2024
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

राष्ट्रपति चुनाव

पीछे हटे बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन पीछे हट गए हैं और उन्होंने ट्रंप का मुकाबला करने के लिए कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य के बारे में आशंकाओं को देखते हुए अंततः जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। उनके स्थान पर संभवतः अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होंगी। इस प्रकार अब मुकाबला कमला बनाम ट्रंप होगा जो पिछले चुनाव में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए चुनाव में जो बाइडेन से हार गए थे। चुनाव के समय 82 वर्ष की आयु वाले राष्ट्रपति बाइडेन ने व्यक्तिगत कारणों से नए नेतृत्व को स्थान देने की इच्छा प्रकट की है। व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस में उनके प्रशासन का एजेंडा आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र को आगे ले जाने की नेतृत्व क्षमता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि 'काफी लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने व उनकी पत्नी ने सोचा कि यह नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का समय है।' उन्होंने उल्लेख किया कि उप-राष्ट्रपति हैरिस ने राष्ट्रपति कार्यकाल के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय में उनका साथ दिया और वे सुश्री हैरिस की प्रतिबद्धता, बुद्धि तथा अमेरिकन जनता के प्रति अडिग निष्ठा के गवाह रहे हैं। कमला हैरिस की उम्मीदवारी अनेक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है। चुने जाने पर वे पहली महिला राष्ट्रपति तथा इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत व दक्षिण एशियाई अमेरिकन होंगी। उप-राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुकी हैरिस, खासकर अपराध न्याय सुधार, आप्रवास व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रशासनिक क्षमता वाली हैं। लेकिन

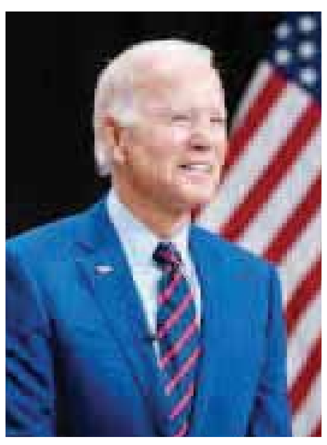

हैरिस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनको संभवतः 'प्राइमरी' की दौड़ के साथ ही आम चुनाव प्रचार अभियान में सफल होना होगा। उनको डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रगतिशील व मध्यमार्गी समूहों को संबोधित करते हुए भविष्य का एक आकर्षक दृष्टिकोण पेश करना होगा ताकि ढुलमुल मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो सके। उम्मीद है कि उनके अभियान में वर्तमान प्रशासन की उपलब्धियां रेखांकित की जाएंगी जिनमें आर्थिक सुधार प्रयास, कोविड-19 वैश्विक महामारी से मुकाबला तथा सामाजिक न्याय व समानता को प्रोत्साहित करने वाली पहलें शामिल हैं।

जो बाइडेन का निर्णय अभूतपूर्व है क्योंकि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने इतने विलम्ब से निर्णय नहीं लिया है। उनके निर्णय के पीछे दो महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। पहला, 'राष्ट्रपति बहस' में उनके निस्तेज प्रदर्शन के कारण विपक्षी देश का नेतृत्व करने की उनकी पहचान पर सवाल उठाने लगे थे। दूसरा, हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप सुर्खियों में आ गए हैं और उनके प्रति व्यापक संवेदना उमड़ी है। हालांकि, दोनों घटनायें असंबद्ध हैं, पर इनके कारण डेमोक्रेटों को अन्य विकल्पों पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपब्लिकन पक्ष को इस घोषणा के बाद नीतियों का पुनः आंकलन करना पड़ेगा। बाइडेन के दौड़ से बाहर होने के बाद अब संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवारों को कमला हैरिस की नीतियों से मुकाबले पर ध्यान देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप व फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में हैं। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि कमला हैरिस अपने अभियान को क्या रूप देती हैं, देश के सामने उपस्थिति महत्वपूर्ण मुद्दों को कैसे संबोधित करती हैं तथा अपने समर्थन में एक व्यापक गठबंधन बनाती हैं। उनकी उम्मीदवारी अमेरिकन राजनीति में नया अध्याय खोल रही है जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी तथा देश का भविष्य निर्धारित हो सकता है।

ग्रामीण आर्थिक विकास की रूपरेखा

भारत का ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लघु व हरित उद्यमों से उसका परिवर्तन हो सकता है। उसमें भारत का 'विकास इंजन' बनने की संभावना है।

मोनिका बी. सूद
(लेखिका, विकास विशेषज्ञ हैं)

समावेशी व टिकाऊ विकास के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। यह बदलाव लघु एवं हरित उद्यमों के माध्यम से संभव है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, महिला सशक्तीकरण होगा तथा कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। पूंजीगत परियोजनाओं तथा खोजी योजनाओं में आरबीआई द्वारा प्राप्त अतिरिक्त एक लाख करोड़ डिविडेंट जैसी धनराशि का प्रयोग कर भारत ग्रामीण क्षेत्रामें में स्व-टिकाऊपन को प्रोत्साहन दे कर युवाओं से दबाव कम कर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से न केवल रोजगार की तत्कालीन आवश्यकतायें पूरी होंगी, बल्कि दीर्घकालीन पूंजी निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण की नीव भी पड़ेगी। लघु एवं हरित उद्योगों को 'विकास इंजन' के रूप में अवसर मिलना चाहिए। लघु उद्यम हमेशा से भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। इन श्रम-बहुल उद्यमों में कृषक समाज की अकुशल व अर्धकुशल श्रमशक्ति को समाहित कर रोजगार सृजन के साथ बिना ज्यादा प्रशिक्षण के वर्तमान जीवन मानकों में बदलाव लाया जा सकता है।

इन उद्योगों के विकास से अन्य बिजनेसों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा जो उनको तथा सामान्य अर्थव्यवस्था की सहायता करते हैं। इसमें हरित उद्योग परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, आर्गेनिक खेती तथा टिकाऊ विनिर्माण को शामिल करने वाले ये क्षेत्र अक्सर दुहरा लाभ देते हैं। इससे उत्पादन एवं पर्यावरण प्रबंधन में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हरित उद्योगों की स्थापना से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के कारण पैदा सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है तथा आजीविका के टिकाऊ साधन विकसित होते हैं। इसके लिए बायोगैस व बायोफ्यूल प्लांट, सौर ऊर्जा फार्म, आयुर्वेदिक व यूनानी दवा उद्योग तथा सहकारी आर्गेनिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन उपायों से रोजगार सृजन होगा, फासिल ऊर्जा पर निर्भरता घटेगी तथा पर्यावरण संरक्षण होगा।

भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत है जिसमें से अधिकांश का लाभ नहीं उठाया गया है। इन महिलाओं में रोजगार और उद्यमिता की वृद्धि से काफी सामाजिक-आर्थिक लाभ हो सकते हैं। सूक्ष्म एवं टिकाऊ उद्योग महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं क्योंकि वे महिलाओं को रोजगार देने, कौशल विकास तथा बिजनेस अवसर प्रदान करते हैं। स्वयंसहायता समूह, महिला-आधारित कोआपरेटिव तथा सूक्ष्म उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उत्पादक सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पहलों का केन्द्र वे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं का प्रभुत्व है। इनमें हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल उत्पादन, वैकल्पिक व आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। महिलाओं को अपने बिजनेस स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए कर्ज, प्रशिक्षण तथा बाजार से संपर्क जरूरी हैं। इससे उनके परिवारों की आय बढ़ती है तथा सामुदायिक विकास होता है। ग्रामीण विकास में सार्वजनिक-निजी साझेदारी या पीपीपी को बढ़ावा देने से ग्रामीण विकास में कौशल व संसाधनों को एकत्र करने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार पीपीपी माडल लघु एवं हरित उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने की पहल कर सकते हैं तथा सरकारी और निजी निवेशकों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इसके लिए नीतिगत समर्थन के साथ ही विकास एवं वित्तीय समर्थन का परिवेश तैयार कर सकती है, जबकि निजी पक्ष फंड, तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन कौशल में उनकी सहायता कर सकते हैं। इस माडल के आधार पर ग्रामीण विकास के लिए आरबीआई द्वारा मिले एक लाख करोड़ रुपये डिविडेंट के एक हिस्से का प्रयोग निजी उद्यमों के साथ सह-फाइनेंस के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्लस्टरों के निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में किया जा सकता है जहां सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन व जवाबदेही सुनिश्चित हो।

पूंजी का निर्माण तथा ग्रामीण विकास विकास की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियायें हैं जिनको समझने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कुल मिला कर एक लाख करोड़ के आरबीआई डिविडेंट का प्रयोग टिकाऊ ग्रामीण विकास परियोजनाओं में पूंजीगत निवेश का मजबूत आधार बनाने के लिए हो सकता है। सड़कों, पुलों, नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं तथा इंडस्ट्रिल इस्टेटें बनाने के माध्यम से तत्काल रोजगार मिलेगा तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। लक्षित निवेश से हर साल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण बेरोजगारी और तनाव को काफी सीमा तक समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल और अर्धकुशल लोगों को रोजगार देना संभव होगा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की भावी पीढ़ियों को बेरोजगारी से सुरक्षा मिलेगी, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों का पलायन थमेगा तथा शहरी-ग्रामीण असमानता घटेगी। स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में ग्रामीण नौजवानों को रोजगार मिलने से मानवशक्ति संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायता मिलेगी, सेवायें प्रदान करने में सुविधा होगी तथा जनसंख्या का कल्याण होगा।

रणनीतिक ग्रामीण विकास एजेंडे की फंडिंग के लिए लीक से हट कर सोचने की जरूरत है ताकि अनेक स्रोतों से फंडिंग जुटाई जा सके। एक लाख करोड़ रुपये के आरबीआई डिविडेंट की तरह सीएसआर के योगदान, पंचायतों और नगरपालिकाओं के अपने फंड तथा ईंधन, आयकर व जीएसटी पर खास सेस से प्राप्त धन को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनिवार्य रूप से सीएसआर फंड का 25 प्रतिशत योगदान कार्पोरेट धन के ग्रामीण विकास में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही लक्ज़री वस्तुओं, कारों, विमान किरायों तथा जीएसटी पर 0.5 प्रतिशत सेस लगाने से बहुत बड़ी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही कौशल विकास योजनाओं-एसकेएस तथा अस्पतालों के एसकेएस फंडों से आवश्यक क्षेत्रों में वेतन के लिए समुचित फंड प्राप्त किए जा सकते हैं। शेयर व्यापार पर थोड़ा सेस लगा कर ऐसी योजना के लिए काफी राजस्व जुटाया जा सकता है जिससे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए स्थाई फंडिंग संभव होगी।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को संबोधित करना जरूरी है। वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी 8 प्रतिशत का आंकड़ा छू चुकी है। देश में बेरोजगारों की कुल संख्या का 1 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। यदि प्रधानमंत्री बेरोजगारी की दर घटा कर 6 प्रतिशत करना चाहते हैं और यह विकसित देशों में बेरोजगारी दर के लगभग बराबर हो तो कम से कम एक करोड़ ग्रामीण नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना होगा। इस योजना को ग्रामीण नौजवान जनसंख्या में कम वेतन वाले रोजगारों पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे रोजगार के अवसर युवाओं को अपने समुदाय में रहने के लिए प्रेरित करें ताकि वे कुशल रोजगार अवसरों के मामले में प्रतियोगिता न करें। इस दृष्टिकोण से मजदूरी को 10,000 रुपये महीना निर्धारित कर कार्य का वितरण 80:20 के आधार पर ग्रामीण परिवारों में किया जाना चाहिए।

इससे संगठित श्रम रोजगार बाजारों में बाधा नहीं आएगी। ग्रामीण विकास के लिए रिजर्व बैंक के अतिरिक्त एक लाख करोड़ डिविडेंट के साथ ही फंडिंग के अन्य स्रोत खोले जाने चाहिए। इसका प्रयोग कर ग्रामीण पुनर्जीवन फंड का गठन तथा इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा सकता है। लघु उद्योग, हरित उद्योग, महिला तथा अकुशल ग्रामीण श्रमिक इस योजना को टिकाऊ बना सकते हैं। इससे बेरोजगारी घटेगी तथा पर्यावरण पर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीपीपी तथा पूंजी निर्माण पर ध्यान देने से यह योजना टिकाऊ होगी, इसे विस्तार दिया जा सकेगा और यह ग्रामीण भारत की बेहतर तस्वीर पेश करेगी।

ओलम्पिक में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं

"खेल मामलों की इस दयनीय स्थिति को लेकर बीओए और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।"

ज्ञान भद्र
(लेखिका स्तम्भकार हैं)

बिहार एक बार फिर ओलंपिक में जगह बनाने से चूक गया। ज्ञान भद्र द्वारा इस महीने के आखिरी हफ्ते में पेरिस में 17 दिनों तक चलने वाले ओलंपिक खेलों का शानदार उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। इसके मद्देनजर भारत के खेल पंडित इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी देश के लिए कितने पदक जीतेंगे। हालांकि, इस लेख को लिखे जाने तक खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने 117 खिलाड़ियों और 140 सहायक कर्मचारियों की सूची पर अपनी मुहर लगा दी थी।

अब सवाल यह है कि क्या बिहार का कोई खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? इसका जवाब नहीं है। टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में भी बिहार के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला, जहां तक ??बिहार में खेल बुनियादी ढांचे की बात है तो यहां पर्याप्त संख्या में स्टेडियम, खेल से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र और कोचों के कुशल मार्गदर्शन का अभाव है। इसका कारण यह माना जा सकता है कि खेल क्षेत्र में सरकारी निवेश बहुत कम है। यहां तक कि बिहार सरकार को खेलो इंडिया योजना के तहत 50.83 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास या एथलीटों के कौशल को निखारने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। खेल क्षेत्र को धन के आवंटन का पैटर्न निराशाजनक रूप से चिंताजनक है। यह देखा गया है कि खेल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निर्धारित धन राजनेताओं की मर्जी के अनुसार डायवर्ट किया जाता है।

इससे खेल उद्योग पर हमेशा बुरा असर पड़ता है, जो खुद को उलझन में पाता है और हमेशा संघर्ष करता रहता है।दूसरा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रमुख खेल निकायों के साथ राजनेताओं का जुड़ाव एक पुराना शगल है। हर योग्य राजनेता खेल निकायों का सदस्य

बनना चाहता है। चाहे वह बीसीसीआई हो या राज्य स्तर पर खेल निकाय, हर राजनीतिक नेता खेल निकायों में निवेश किए गए भारी धन का लाभ उठाना चाहता है, फिर बिहार कैसे पीछे रह सकता है? बिहार में खेलों के विकास के लिए काम करने वाले नायक बनने के बजाय, राजनेता, एक बार खेल निकायों में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के बाद, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का दोहन करते हैं। लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। लेकिन इतनी भी कम नहीं कि वे यह भूल जाएँ कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने बिहार की उभरती प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया था। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लालू की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बीसीए के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, बिहार के किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं मिली थी; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े लीग मैचों की तो बात ही क्या करें। अब खेल पंडित यह तर्क दे सकते हैं कि बीसीए के अध्यक्ष के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान, बिहार के पास राज्य की रणजी टीम नहीं थी क्योंकि बिहार के विभाजन के कारण खेल सुविधाओं के मामले में बिहार को नुकसान हुआ था। झारखंड ने खेल सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा अपने पास ले लिया। हालांकि, खेल पंडितों द्वारा इस बहाने का सहारा लेना तब के कई युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बेकार था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस समय राजद की अगुआई राबड़ी देवी कर रही थीं और लालू यादव राज्य की रणजी टीम बनाने और राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए योग्यतम कोच नियुक्त करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे।

तीसरा, ओलंपिक खेलों के लिए एथलीटों को तैयार करने में बिहार ओलंपिक संघ (बीओए) की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, बीओए के अधिकारी एथलीटों को विश्व स्तरीय ओलंपिक खेलों के स्तर पर तैयार करने के लिए कार्यक्रम और ट्रायल आयोजित करने की जहमत नहीं उठाते। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पेरिस ओलंपिक के लिए 117 एथलीट-सदस्यीय टीमों की सूची में बिहार का कोई भी एथलीट शामिल नहीं था। इससे भी बुरी बात यह है कि खेल मामलों की इस दयनीय स्थिति को लेकर बीओए और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बीओए बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कोचों की कमी के बारे में लापरवाही के लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि बीओए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित करने में खुद को असमर्थ पाता है। दूसरी ओर, राज्य सरकार यह कहकर बीओए के बारे में अपनी आवश्यक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है कि बीओए एक स्वतंत्र इकाई है और सरकार इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इस चल रहे संघर्ष में, उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हार रहे हैं। अंत में, यह कहा जा सकता है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना पहली नज़र में बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, बिहार में आवश्यक खेल संसाधनों की कमी के कारण, यह योजना कई युवा प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं कर पाएगी।

आप की बात

आरक्षण की सीमा

आजादी के बाद 10 वर्ष तक के लिए लागू आरक्षण अब राजनेताओं की चुनावी खेती बन गया है। इससे एक ओर तो जनता में आरक्षित व अनारक्षित के बीच खाई बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण के कारण आरक्षित जातियों में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो इसके लाभ को अपनी ही जातियों के गरीबों तक नहीं पहुंचने देता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का चुनावी वादा पूरे देश और समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए प्रबंधन क्षेत्र में 50 प्रतिशत और गैर प्रबंधन क्षेत्र में 70 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को देने हेतु कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर लिया था। लेकिन उद्योग जगत के भारी विरोध होने के कारण सरकार को इसे विधानसभा में लाने की हिम्मत नहीं पड़ी और इसे चौबीस घंटे में ही वापस ले लिया गया। लेकिन आशंका है कि कांग्रेस सरकार इसे किसी दूसरे तरीके से ला सकती है। सरकारी नौकरियों में मोटे वेतन, आरामतलबी तथा रिश्वतखोरी की प्रवृत्तियों के कारण अब अनेक समृद्ध जातियां भी आरक्षण की जिद पर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने लगी हैं। अतः आरक्षण की सीमा बढ़ाने के सारे विचार स्पष्ट रूप से खारिज होने चाहिए।

– **बी.एल. शर्मा,** उज्जैन

पर्यटन के प्रभाव

यात्रा और पर्यटन उद्योग का 2023 में वैश्विक जीडीपी में 9.1 प्रतिशत हिस्सा था। यह योगदान लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार अतिथि सत्कार एक तरह से अमेरिका, स्पेन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों के लिए उद्योग का काम करता है। सरकारें भी पूरा जोर लगाती हैं ताकि पर्यटकों को आकर्षित कर अधिकाधिक लाभ कमाया जाय। मगर आजकल दुनिया के अनेक हिस्सों में इसका विपरीत प्रवृति दिखाई दे रहा है। वहां स्थानीय निवासी बढ़ते पर्यटकों से न सिर्फ ऊब चुके हैं बल्कि उनके कारण उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन के मैलोर्का में अति-पर्यटन का विरोध करते हुए पचास हज़ार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह शहर उन लोगों के लिए है जो इसमें रहते हैं। रैली में पर्यटन मॉडल में बदलाव की मांग की गई। पर्यटन के मौजूदा मॉडल ने सार्वजनिक सेवाओं व प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया तथा स्थानीय लोगों का किराये पर रहना मुश्किल कर दिया है क्योंकि पर्यटकों से मकान मालिकों को ज्यादा आमदनी होती है। भारत में भी अनेक पर्यटन स्थलों पर स्थानीय निवासियों को संकट तथा पर्यावरण विनाश जैसी हालत है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

इलाज का खर्च

सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एक आंख के लिए लगभग 10,000 रुपये तक खर्च आ सकता है, जबकि निजी अस्पताल में यह 30,000 से 1,40,000 रुपये तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को 14 साल पुराने कानून-क्लिनिकल स्थापना नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर महानगरों, शहरों व कस्बों में इलाज के लिए एक मानक दर तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को मानक दर अधिसूचित करने के लिए राज्यों के अधिकारियों संग बैठक बुलाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक एनजीओ की जनहित याचिका पर दिया। इसमें मांग की गई थी कि न्यायालय लोगों को चिकित्सा के नाम पर की जाने वाली लूट से बचाए। उल्लेखनीय है कि आजकल दवा इलाज का खर्च बहुत लोगों की कमर तोड़ने वाला बन गया है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ निजी अस्पतालों की लूट जारी है। इस पर कठोरता से लगाम लगनी चाहिए।

– **गोपाल सोनी,** धार

शिक्षकों की छवि

स्कूल शिक्षकों के बारे में अनेक सकारात्मक व नकारात्मक खबरें सामने आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कोचिंगों के कारण अनेक शहर मशहूर हो गए हैं। लेकिन हाल ही में वहां के कुछ शिक्षक बच्चों को नकल कराते दिखे। शिक्षा विभाग के सतर्कता दल ने एक गांव में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला डालकर अंदर शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर सामूहिक रूप से नकल कराते पाया। वैसे छात्रों को गलत ढंग से नंबर देने, या ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों का पक्षपात करने की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, पर शिक्षकों द्वारा सामूहिक नकल कराने की घटनायें विरल हैं। ऐसे शिक्षको की हरकतों से पूरा शिक्षक समाज शर्मिंदा होता है। राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों की सरकारों तथा भारत सरकार को स्कूली शिक्षा का स्तर उठाने के प्रयास करने चाहिए। अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के साथ ऐसे भ्रष्ट व अनैतिक शिक्षकों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना भी जरूरी है। स्वयं शिक्षकों को भी अच्छे वेतन के साथ अपनी छवि की चिन्ता भी करनी चाहिए।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजटः मुख्यमंत्री

● टैक्स स्लैब में नई रियायत को मुख्यमंत्री ने बताया स्वागत योग्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत होने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहीं। सीएम योगी ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम का अभिनंदन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है। खास तौर पर तब, जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही 'मिशन शक्ति' के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ-साथ मध्यमवर्गीय

आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहमः आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि यह देश के 140 करोड़ लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक न्याय दिलाने वाला है। राज्यपाल ने कहा कि बजट में किसान, गरीब, युवा तथा महिला सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि आज प्रस्तुत बजट देश को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने वाला है, जिसमें मध्यम वर्ग को न्याय,औद्योगीकरण को बढ़ावा, बेरोजगारों को रोजगार तथा गरीब आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों को न्याय देने की व्यवस्था है। उन्हांने कहा कि बजट में कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं युवाओं के कौशल विकास पर बल देने से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्यपाल ने कहा कि बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, शोध और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार हेतु अनेक कारकों का प्राथमिकता दिया जाना शामिल है।

एक्शन में सीएम योगी, लापरवाह पांच एडीएम और तीन एसडीएम से जवाब तलब

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● आपदा से हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही पर की कार्रवाई

● बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को किया निलंबित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसमें पांच जिलों के एडीएम एफआर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जबकि तीन एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया। सीएम ने सभी लापरवाह अधिकारियों को दो दिनों में अपना स्पष्टीकरण शासन के सौंपने के निर्देश दिये हैं। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के अंदर प्रदान किया जाए।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में आपदा से हुई जनहानि का सर्वे पूरा कर 24 घंटे में मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इनमें बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फनगर के एडीएम एफआर क्रमशः संतोष सिंह, उमेश चंद्र निगम, उमा शंकर, एस सुधाकरन और गजेंद्र कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि सौंपी गयी है। इसके साथ ही लापरवाही पर सिद्धार्थनगर की सदर तहसील के एसडीएम ललित कुमार मिश्रा, हाथरस की शादाबाद तहसील के एसडीएम संजय कुमार सिंह और अलीगढ़ की अतरौली तहसील के एसडीएम अनिल कुमार कटियार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार को निलंबित कर दिया है।

बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिलाः केशव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट गाँव-गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को प्रोत्साहन और किसानों की आय में वृद्धि को धरातल पर उतारने वाला बजट है। यह गरीबों, महिलाओं, उत्तम स्वास्थ्य, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित बजट है। जिसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का रोड मैप और गरीब कल्याण तथा समग्र विकास पर केंद्रित बजट है, सर्व समावेशी बजट है। महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों और सर्व समाज के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नीव रखने वाला यह बजट है। मौर्य ने कहा कि गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों व नारीशक्ति को समर्पित बजट है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मिडिल क्लास के घर के सपने पूरे होंगे बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया गया है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला है। बजट में रोजगार का पिटारा खोला गया है। किसानों व युवाओं के लिए बड़े ऐलान किये गए हैं। नौकरी पेशा व पेंशनरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे चरण का शुभारम्भ होगा, बजट विकसित भारत का रोड मैप है। गरीब कल्याण व समग्र विकास पर केंद्रित बजट है।

सबका साथ, सबका विकास वाला बजटः ब्रजेश पाठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है।

कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजटः सुरेश खन्ना

● केन्द्रीय करों में यूपी का अंश 218816.84 करोड़ से बढ़कर हुआ 223737.23 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3.0 सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को एक शानदार बजट बताया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत सातवें बजट को हिंदुस्तान के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फायदा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, अन्नदाता गरीब वंचित सभी का बजट में ध्यान रखा गया है। बजट में नौ सूत्र दिए गए हैं। कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजट है।

मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अन्तरिम बजट में केन्द्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश रू. 218816.84 करोड़ था जोकि इस बजट में बढ़कर 223737.23 करोड़ हो गया है। बजट में सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवायें, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, जिससे आमजन को सीधा फायदा होगा। आयकर अधिनियम, 1961 को सुगम बनाने के लिये छह माह में इसकी समीक्षा की जायेगी। व्यक्तिगत आयकर में स्टेंटर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये प्रस्तुत किये गये अन्तरिम बजट में 4 वर्गों गरीब, युवा, महिला एवं अन्न दाता पर फोकस किया गया था। इन्ही वर्गों पर मुख्य बजट में भी फोकस है। पी.एम. गरीब कल्याण योजना 5 वर्षों के लिये बढ़ायी गई। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 9 प्राथमिकतायें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवायें (मैनुफैक्चरिंग एवं सर्विसेस), शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा (एनर्जी सिक्योरिटी), अवसंरचना/ अवस्थापना सुविधा, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार बतायी हैं। खन्ना ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन लाने के लिये 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। दलहन-तिलहन की उत्पादकता एवं भण्डारण क्षमता बढ़ायी जायेगी एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र एवं सहायक गतिविधियों के लिय 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा। समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला केन्द्रित विकास के लिये रू. 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिये 2.66 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे । 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिये तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण प्रारम्भ किया जयेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिये ब्याज मुक्त ऋण योजना हेतु 1.50 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। यह योजना आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिये होगी। इसमें 63 हजार गांवों को आच्छादित किया जायेगा जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे।

दो सप्ताह के विशेष चेकिंग अभियान में 5913 स्कूली वाहन पाए गए अनफिट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवहन विभाग द्वारा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक स्कूल वाहनों के विरूद्ध चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत 5913 स्कूली वाहन अनफिट पाये गये। उक्त अभियान में स्कूली वाहनों के फिटनेस संबंधी जांच प्रवर्तन दल द्वारा किया गया। जांच के दौरान पूरे प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड 61921 स्कूली वाहनों में से 47624 वाहनों के फिटनेस संबंधी जांच किये गये, जिसमें से कुल 41675 स्कूली वाहन फिट पाये गये एवं 5913 स्कूली वाहन अनफिट पाये गये। यह जानकारी परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान में अनफिट पाये गये 2076 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 456 स्कूली वाहनों को बंद किया गया। उक्त कार्यवाही से 60.84 लाख रूपये प्रशमन शुल्क वसूला गया और 552 स्कूली वाहनों को नोटिस भेजी गयी। लखनऊ संभाग में 6775 स्कूली वाहन चेक किये गये, जिसमें से 5763 स्कूली वाहन फिट पाये गये एवं 1012 अनफिट पाये गये। इसी प्रकार अयोध्या संभाग में 3050 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 151 वाहन अनफिट पाये गये, गोण्डा संभाग में 1744 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 600 वाहन अनफिट पाये गये, बस्ती संभाग में 2052 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 400 वाहन अनफिट पाये गये। कानपुर संभाग में 2294 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 211 वाहन अनफिट पाये गये, प्रयागराज संभाग में 2384 वाहन चेक किये गये, 280 वाहन अनफिट वाहन पाये गये, बांदा संभाग में 663 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 39 वाहन अनफिट पाये गये, बरेली संभाग में 1987 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 184 वाहन अनफिट पाये गये, मुरादाबाद संभाग में 2702 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 327 वाहन अनफिट पाये गये, वाराणसी संभाग में 5159 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 297 वाहन अनफिट पाये गये, गोरखपुर संभाग में 4384 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 985 वाहन अनफिट पाये गये, आजमगढ़ संभाग में 1840 वाहनों की चेकिंग की गयी।

बजट में गरीबों व महिलाओं के विकास के लिए कोई योजना नहीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट से जनता निराश हुई है। इस सरकार ने दस साल में बेरोजगारी बढ़ायी है।

नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। यह सरकार आधी अधूरी नौकरी का सपना दिखा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के ग्यारहवें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा नौ दो ग्यारह हो गया है। किसान की आय दोगुनी करने के लिए कोई योजना नही। मंडियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। खाने-पीने की चीजों से लेकर सब चीजों की महंगाई आसमान पर है। सरकार महंगाई नहीं कम करना चाहती है। बजट में गरीबों और महिलाओं के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। मंडी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए बिना किसानों को लाभ नहीं मिल सकता है। 'ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है कि इंसान इन हालातों में भी जिंदा है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कुछ नहींः डिम्पल यादव

लखनऊ। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है। क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है।

बजट सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहींः अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार का भी बजट सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं। देश की सभी बड़ी समस्याओं फिर चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, य फिर महंगाई की बात हो किसी भी समस्या के निवारण का स्पष्ट रोड मैप नहीं है। पिछले बजट में जो वादे किय गये थे, जो योजनाएं घोषित हुई थी, उनकी कोई चर्चा न करते हुए फिर से नये वादे नई घोषणाएं। राय ने कहा कि 2023 और 2024 का बजट भाषण ध्यान से देखते हुए कई झूठ यूहीं पकड़ में आ जाते हैं जैसे पिछले बजट में भी यह वादा किया गया था कि प्राकृतिक खेती की जद में एक करोड़ किसान लाये जायेंगे अगले तीन वर्षों में और इस बार उसी वादे को फिर से दोहराया गया है, यह कहते हुए कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाया जायेगा तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि पिछले 1 वर्ष में इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से पिछले बजट में 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने की बात कही गई थी जो इस बार के बजट में भी दोहराई गई है। स्पष्ट है कि 1 साल में कोई भी रिसोर्स सेंटर नहीं खोला गया है। पिछले 10 सालों में मोदी जी की बहुचर्चित स्मार्ट सिटी परियोजना की चर्चा बंद हो चुकी है क्योंकि इनकी लगभग सभी स्मार्ट सिटी की हालत यह है कि पहली ही बारिश के बाद वहां नाव चलने की नौबत आ जा रही है। इसीलिए इस बजट में स्मार्ट सिटी की बात न करके शहरों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने के नए वादे की बात की जा रही है।

कृषि क्षेत्र में बढ़े निवेश व नीतियों में हो बदलावः रालोद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने मंगलवार को जारी एक बयान में केंद्र सरकार से बजट सत्र में कृषि पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि बजट सत्र से पूर्व केंद्र सरकार ने कृषि व किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें प्राथमिकता पर लिया है। पर, सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों की आय बढ़े साथ ही बदलते समय के साथ परंपरागत कृषि के तरीकों के साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी पिछले दस वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सशक्त आधार तो तैयार कर ही लिया है बस अब आवश्यकता उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूलभूत सुधारों की है।

बजट अच्छे दिनों की उम्मीद वाला कम मायूस करने वाला ज्यादाः मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश किया है। हालांकि उनके इस बजट से विपक्षी दल के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में आज पेश केन्द्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव. बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आँकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे/ आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति-जरूरी. सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे।

नई क्रेडिट गारंटी स्कीम से प्रदेश की छोटी इकाइयों को मिलेगी बड़ी राहत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● आम बजट 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान

आम बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे प्रमुख घोषणा एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की है, जिसके तहत एमएसएमई इकाइयों को कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक स्व-वित्तपोषित गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जो प्रत्येक उधारकर्ता को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। इस पहल से प्रदेश की उन छोटी इकाइयों को भी लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं और इससे उनके खातों को एनपीए होने से भी बचाया जा सकेगा। मालूम हो कि योगी सरकार प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। बजट में नए प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आम बजट 2024-25 को सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋ ण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से असेट्स और टर्नओवर के आधार पर ऋण देती रही हैं। बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए होगी जिन्होंने पूर्व में लिए गए ऋण को तय समय सीमा में चुकाया है। एमएसएमई क्लस्टर्स में अगले तीन वर्षों में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।

ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की सीमा को वर्तमान 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक एमएसएमई इकाइयां इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो सकेंगी और आसानी से क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगी।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे प्रदेश के लाखों युवा

● अधिक संख्या में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे प्रदेश के युवा

आम बजट 2024-25 में युवाओं के कौशल विकास को लेकर की गईं महत्वपूर्ण घोषणाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आम बजट 2024-25 में किए गए प्राविधानों से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। यही नहीं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वो रोजगार से जुड़ सकेंगे।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋ ण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है। यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओ को सेवायोजन प्रदान किए जाने के लिए नियुक्ति प्रदान कराई हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। निर्मला सीतारमण ने जो प्रमुख घोषणाएं कीं, उनमें प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में की बैठक

● मुख्यमंत्री संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल व समाधान दिवस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में हो संतुष्टिपरक, गुणवत्तापूर्ण निस्तारणः जिलाधिकारी

डीएम कलेक्ट्रेट सभागार में पोर्टल पर प्राप्त शिकायातों के निस्तारण की समीक्षा करते हुये

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों से आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भोंए निस्तारण की स्थिति, डिफाल्टर सन्दर्भ की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मुख्यमंत्री सन्दर्भ, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल व समाधान दिवस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में संतुष्टिपरक, गुणवत्तापूर्ण रूप में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सन्दर्भित प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवंटित समयावधि से आधे समय में सन्दर्भो का निस्तारण कराया जाये, जिससे कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच एवं पुनः जांच कराये जाने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री संदर्भ से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सात दिन व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सन्दर्भो का निस्तारण 15 दिन के भीतर किया जाये।

इसके अतिरिक्त डीएम ने सभी अधिकारियों को सीयूजी नम्बर उठाने व उस पर आने वाली शिकायतों का संवेदनशील होकर निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये। आईजीआरएस पोर्टल से संबंधित शिकायतें अथवा सीयूजी नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में यदि शिथिलता पायी जाती हैए तो सम्बन्धित अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। सीडीओ लक्ष्मी एन.ए एडीएम प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर, परियोजना निदेशक वीरेंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी सुबोध कुमार, उपनिदेशक कृषि रामबचन राम, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, खाद्य एवं विपणन अधिकारी, उपयुक्त उद्योग, ईडीएम आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला ने फांसी लगाकर जान दी

मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपसा में नव विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगा आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की है। कपसा के मदाइन पुरवा निवासी धीरज सिंह की गर्भवती पत्नी सरोज (23) ने घर में कमरे के अंदर फंद्दा आत्महत्या कर ली। मृतक सरोज के ससुर चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मेरे तीन पुत्र व दो पुत्री है जिसमे दोनों पुत्रियों की शादी कर दी है स वही मेरे दो पुत्र सूरत में रहते है व धीरज कानपुर में प्राइवेट कम्पनी में काम करता है और वही रहता है धीरज की शादी दो वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हरडोनी गाँव में बलराम सिंह की पुत्री के साथ हुआ था शादी बाद दोनों पति पत्नी कानपुर में ही रहने लगे हम कपसा में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे बहू सरोज गर्भवती थीं इस कारण धीरज ने दो माह पूर्व गाँव छोड़ गया था, किस कारण बहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया वह खुद नही समझ पा रहा है।

सड़क सुरक्षा के नियमों का अधिकारी कराए पालनः एडीएम

● अपर जिलाधिकारी ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, दिए निर्देश

●एडीएम ने स्कूल वाहन के वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन, लाइसेंस की जांच कराये जाने के दिये निर्देश

एडीएम प्रशासन अमित कुमार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश देते हुये

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि एनएच पर अनधिकृत कट को बंद करने की कार्यवाही व रनियां में सर्विस रोड़ से विद्युत पोल हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही हैए जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी ने कराए जा रहे कार्यों की फोटोग्राफलोकेशन सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने एनएचएआई के पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। ओवर स्पीडिंग रोकने स्वचालित चालान व्यवस्था लगाने, रोड पर रंबल स्ट्रिप बनाने, साइनेज बोर्ड आदि लगाने के निर्देश दिए। संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर ट्रैफिक नियमों का पालन कराएए जो ट्रैफिक नियमों का पालन नही कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्यवाही करें। नबीपुर में अण्डर पास बनाये जाने के संबंध में एडीएम को एनएचआई के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैए शीघ्र ही अण्डरपास का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 548 स्कूल वाहन पंजीकृत हैए जिसमें से 150 वाहनों का फिटनेस वर्तमान में फेल हैए इसमें से 42 के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 8 से 22 जुलाई के मध्य स्कूली वाहनों की सघन जांच की गयीए जिसमें 55 वाहन मानक के अनुरूप न पाये जाने पर सीजर की कार्यवाही की गयी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को सुनायी उम्रकैद व जुर्माना

हमीरपुर। मुस्करा थाना के एक गांव निवासी नाबालिग वर्ष 2015 में घर से सोते समय अचानक लापता हो जाने के मामले में पीड़ित मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद घर पहुंची नाबालिग ने उसके साथ गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित को दोषी मानते हुए उम्रकैद सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि थाना मुस्करा के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की की मां ने मुस्करा थाने में तहरीर दी थी कि 16 मई 2015 की रात 12 बजे घर में सोते समय उसकी पुत्री अचानक कहीं लापता हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नही मिली। जिस पर गांव निवासी सुरेश द्वारा बेटी को फोन किए जाने की बात पर उसने सुरेश के खिलाफ बेटी को बहला कर ले जाने समेत एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। वहीं बेटी की बरामदगी के बाद जब पुलिस ने कोर्ट में 164 के बयान कराएं तो उसमें बेटी ने सुरेश द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। जिस पर कोर्ट में हुए बयान के आधार पर आरोपित सुरेश के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पाक्सो एक्ट की धारा और बढ़ गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित सुरेश को दोषी मानते हुए एससी एसटी मामले में आजीवन कारावास सुनाया है। इसके साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सीआरपी और समिति पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

फतेहपुर। ब्लाक इंडिया द्वारा संचालित अश्वकल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड तेलियानी में समिति पदाधिकारी और सीआरपी का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें परियोजना के अलग-अलग ब्लॉक से समिति के पदाधिकारी और सदस्य, सीआरपी आदि ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत विकास खंड अधिकारी राहुल द्वारा की गई, जिन्होंने विकासखंड स्तर पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, समूह केडर निर्माण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जीवन ज्योति अश्वकल्याण समिति द्वारा किए गए अश्वकल्याण कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में श्रम विभाग से अधिकारी इजहार अहमद उपस्थित रहे। सभी को लेबर कार्ड की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से समझाया और लेबर कार्ड की योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझाया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जिला मिशन मैनेजर रणजीत सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने एनआरएलएम द्वारा चलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को विस्तृत समिति और सीआरपी को समझाया और समिति को मजबूत करने हेतु क्लस्टर स्तर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके अलग-अलग प्रोजेक्ट को काम करने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एडीओ एग्रीकल्चर दिनेश उपस्थित रहे, जिन्होंने कृषि विभाग और होर्टीकल्चर विभाग की योजनाएं जो समूह और समिति के लिए चलाई जा रही है, उनकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि ग्रामीण स्तर पर विकासखंड से समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वयन हो रही है, जिसमे समिति और समूह लाभ ले सकते है। मैनेजर शिवम साहू ने ब्रुक इंडिया के उद्देश्यों, अश्वकल्याण संबंधी मुद्दों पर समझाया गया। इस कार्यक्रम में बृजेश कुमार, उषा अवस्थी, मानसिंह तथा समिति से पदाधिकारी और सीआरपी रीता, सुनैना, पिंकी, पुष्पा, कमला सुनैना, मो. रफी, मो. अनीस, विनोद, संतोष, राजाराम, नीतू उपस्थित रहे।

अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम ने ली बैठक

फतेहपुर। लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित होने वाली राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन हेतु विद्यालय व संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम सी. इन्दुमती की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। शासन की मंशानुरूप राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय जो आयोग के दिशा निर्देशानुसार सभी मानकों को पूरा करते हो और जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाए जा रहे है, कि एलआईयू रिपोर्ट प्राप्त कर ले साथ ही विद्यालय के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यो से सहमति पत्र अवश्य ले लिया जाये। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाए जाने की कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अविनाश त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा, एसडीएू सदर, एएसडीओ, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्नीक, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे।

क्विक न्यूज

जमीनी विवाद में दो पक्ष भिड़े, कई जख्मी

फ़तेहपुर, खागा। नगर के जोकीपर मुहल्ले में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जिसमे कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफपुलिस को लिखित तहरीर देकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने व लाइसेंसी असलहों से फायरिंग कर दहशत फैलाने समेत जानमाल की धमकी देने की तहरीर दी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नगर पंचायत क्षेत्र के जोकीपर मुहल्ले निवासी पीड़ित अश्वनी मौर्य पुत्र लाला उर्फरामेश्वर मौर्य सोमवार की रात अपने खेत में पानी लगाए था। तभी परिवार के राजकुमार, अरविंद पुत्रगण देशराज, शिवम पुत्र रविशंकर, अंकित पुत्र राजकुमार व लल्लू पुत्र अरविंद ने एकराय होकर खेत की बल्लियों व तार को हटाना शुरू कर दिया। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने अश्वनी को लाठी डंडो व लाइसेंसी असलहों से पीटना शुरू कर दिया। चीखपुकार सुनकर पीड़ित के बीच बचाव के लिए दौड़े आरोपी मौके से फरार हो गये। मारपीट के दौरान दोनों पक्षो से कई लोग चोटहिल हो गये। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित अश्वनी ने आरोपियों के खिलाफनामजद तहरीर दी है।

फांसी पर लटकी मिली महिला, हत्या का आरोप

फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र के ग्राम बरौरा में मंगलवार की सुबह 23 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगा ली। जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बरौरा गांव निवासी अखिलेश कुमार की पत्नी प्रियंका ने मंगलवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी लगा लिया। परिजनों की नजर पड़ी तो तत्काल उसे फंदे से छुड़ा सरकारी एंबुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाए। जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर आए पति अखिलेश ने बताया कि पंद्रह दिनों से उसकी पत्नी बीमार चल रही थी। दवा खाने के लिए कहा तो मना कर दिया जिस पर उसे डांट-डपट दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता उमाशंकर निवासी मुत्तौर थाना ललौली ने बताया कि उसकी पुत्री ने फांसी नहीं बल्कि ससुरालीजनों ने हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया है।

करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

फतेहपुर। ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा बहुआ में सोमवार की रात करंट की चपेट में आ जाने से लगभग 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को विच्छेदन के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार गाजीपुर थाना क्षेत्र के लिलरा गांव निवासी रामस्वरूप का पुत्र विनय कुमार साथी अतुल के साथ बहुआ कस्बा एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। तभी अर्द्धरात्रि करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सालय के मार्च्युरी हाउस में मृतक के परिजनों ने बताया कि बहुआ में कथा का कार्यक्रम हो रहा था। जिस पर मृतक आर्गेन बजाता था। स्टेज के पास लगे टेंट के पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया। इसी बीच बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे प्लास्टिक की कुर्सी से धक्का दिया तो नहर में गिर गया। साथ में गए अतुल ने नहर में कूदकर उसे बाहर निकाला और सदर अस्पताल लाए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

गंगा में डूबे किशोर का शव बरामद

फतेहपुर। कानपुर नगर के थाना पनकी मुहल्ला गंगागंज निवासी महेंद्र सिंह भदौरिया का पुत्र नैतिक अपने मामा अनिल सिंह निवासी तेलियानी के यहां आया था। बताते हैं कि सोमवार की सुबह दस बजे वह मामा के परिवार सहित स्नान करने के लिए गया था। तभी वह गंगा में डूब गया। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम व गोताखोर किशोर को खोजने के लिए जुट गए लेकिन कोई सुराग न मिला। मंगलवार की शाम किशोर का शव सुखरूपुर घाट से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

फर्जी फंसाने का लगाया आरोप

राठ (हमीरपुर)। कोतवाली के बिलरख गांव निवासी रोहित कुमार पुत्र कढ़ोरी लाल ने बताया कि गांव के कालीचरन पुत्र शिवनाथ व उसकी पत्नी रचना ने पुत्री को नाबालिग दिखाते हुए उसके ऊपर छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया था। जिसमें वह जेल भी गया था। उस समय कालीचरन ने अपनी नाबालिग पुत्री की शादी 11 मई 23 को औड़ेरा गांव निवासी सुरेंद्र पुत्र शिवनाथ के साथ नरसिंह मंदिर कछवां की पहाड़ियां से हिंदू रीति.रिवाज के साथ संपन्न कराई थी। जो कानूनन अपराध है। पीड़ित ने उसे फर्जी फंसाने पर उक्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

उप चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 4 पदों पर पांच नामांकन

फर्रुखाबाद। राजेपुर विकास खंड क्षेत्र के तीन ग्राम पंचायतों में चार ग्राम पंचायत पदों के लिए 5 नामांकन दाखिल किये गये स एक सदस्य निर्धारित समय से 12 मिनट लेट आने के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं हो सका स ग्राम पंचायत रतनपुर पमारान के बार्ड संख्या चार अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित सरस्वती पत्नी राजेश ने नामांकन पत्र दाखिल किया, ग्राम पंचायत सबासी के वार्ड संख्या 6 से ओबीसी महिला हेतु आरक्षित शिल्पी देवी पत्नी प्रदीप कुमार ने तथा भाग संख्या 10 से अनारक्षित लज्जाराम पुत्र नत्थू ने पर्चा भरा सजबकि ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर बार्ड संख्या पांच अनारक्षित में सुभद्रा पत्नी हरदेव सिंह, तथा मीना सिंह पत्नी अमर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि इसी वार्ड में 4रू12 बजे पर पर्चा जमा करने आयी मीना देवी पत्नी देवेंद्र कुमार का समय समाप्त होने के बाद पर्चा जमा नहीं हो सकास सहायक निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया

परिवहन ज्वाइंट टीम को रोडवेज बस में मिले 14 बिना टिकिट यात्री

● परिचालक पर गिरी गाज, दर्ज हुई एफआईआर

निरीक्षण करती टीम

सुमेरपुर (हमीरपुर)। प्रवर्तन दल ने बीती रात इंगोहटा के पास बिना टिकट यात्रियों को लेकर महोबा से लखनऊ के लिए जा रही परिवहन निगम की बस को पकड़ा। प्रवर्तन दल के बीच रास्ते में बस को रुकवाने पर कंडक्टर ने जल्दबाज़ी में टिकट मशीन से टिकट निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक टीम ने उसे दबोच लिया। यात्रियों से पूछताछ की गयी तो बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री मिले जो कंडक्टर को किराये के पैसे दे चुके थे। प्रवर्तन दल ने बस को हमीरपुर डिपो में खड़ा कराकर टिकट मशीन सहित बैग को डिपो में जमा कराया है। हमीरपुर प्रवर्तन दल द्वारा महोबा डिपो की बस पर मौदहा सुमेरपुर के मध्य इंगोहटा में औचक निरीक्षण किया गया था। टीम ने मशीन और बैग को अपने कब्जे में लेते हुए जब यात्रियों से टिकट माँगा तो 14 यात्रियों के पास टिकट नहीं मिला जो कंडक्टर को पैसे दे चुके थे। चेकिंग टीम ने फिलहाल बस को हमीरपुर डिपो में खड़ा कराकर बैग सहित मशीन को डिपो में जमा कराया है। टीम के सदस्य सत्येन्द्र सिंह सहायक यातायात निरीक्षक ने बताया कि महोबा डिपो की बस में 14 यात्री बिना टिकट मिले थे। 14 यात्रियों के किराए का दस गुना कंडक्टर से वसूला जाएगा। फिलहाल बस को डिपो में खड़ा करा लिया गया है। बैग और टिकट मशीन को डिपो में जमा कराया गया। डिपो के एआरएम राम प्रताप साहू ने बताया कि महोबा डिपो के कंडक्टर लक्ष्मण दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी है।

आमबजट में मध्यवर्गीय, युवाओं, महिलाओं पर विशेष फोकसः मुकेश गुप्ता

फर्रुखाबाद। स्टेट बैंक अधिकारी एवम् अर्थशास्त्री मुकेश गुप्ता ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश देश के आम बजट 2024-25 में इस बार मध्यम वर्गीय लोगों को काफी फायदा होते दिखाई पड़ रहा है । इस बार के बजट में आयकर के नए टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने के साथ-साथ 3 लाख से 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को टैक्स रेट के बदलाव के कारण लगभग 17500 रुपयो तक की बचत होगी । इस प्रकार जब मध्यम वर्गीय लोगों की बचत होगी तो उनकी बचत में वृद्धि होगी जिसके साथ-साथ उनकी पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ने से वह बाजार में उपलब्ध उत्पादों की ज्यादा खरीद करेंगे इस प्रकार माल की ज्यादा खपत होने के कारण कारखानो को अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। अंततः देश में औद्योगिक विकास होगा।

अपराध और अपराधियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

मोहम्मदी खीरी। चन्द्र शेखर सिह की जगह आऐ नवागंतुक प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह मीडिया से हुए रूबरू एपहली प्रेस वार्ता मे उन्होंने बताया कि मैं मूल रूप से फतेहपुर हसवा का रहने वाला हूं, 2001 में सब इंस्पेक्टर के रूप में मेरी भर्ती हुईए 2016 में इंस्पेक्टर बन इंस्पेक्टर के रूप में जनपद इटावा, बलरामपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, आगरा और जनपद लखीमपुर खीरी के पसगवां, गोला एभीरा के बाद मोहम्मदी कोतवाली का दायित्व मिला, प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हमारी प्राथमिकताएं जो फरियादी कोतवाली आऐ उसकी समस्या को सुनना और उसका निराकरण कराना रहेगाए वही अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, महिलाओं पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगानाए यातायात को और सुधार करना जिससे दुर्घटना में कमी आए, कावड़ यात्रा के संबंध में उन्होंने बताया यह माह सावन का महीना है जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त गोला गोकर्णनाथ शिव के मंदिर पर कावड़ यात्रा के रूप में जाते हैं जिसमें उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगह.जगह पर पुलिस पिकेटए खाने पीने सहित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है एवही उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जाऐगाएतथा किसी भी कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त को किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नही करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे जो बंद है पुलिस प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता कर इसको चालू कराया जाएगा। वहीं सामाजिक अपराध गौकशीए सट्टा एस्मैक जैसे सामाजिक अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगाए वहीं उन्होंने मीडिया से सकारात्मक रूप से सहयोग की अपेक्षा की है।

मण्डलीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न

बाँदा। आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों को तेज गति के साथ गुणवत्तायुक्त तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने मासिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य में तेजी लाते हुए सम्पादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित रहने तथा अधिकारियों को जन समस्याओं को प्राथमिकता पर गम्भीरता से लेते हुए गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सड़कों का निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ किये जाने तथा निर्माण की गयी सड़कों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने सेतुओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ निर्माणाधीन पुलों के सभी कार्य एप्रोच रोड सहित पूर्ण किये जायें। उहोंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारियों को अवशेष अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा कराये जाने के निर्देश दिये तथा जिन लाभार्थियों द्वारा अभी तक आवास पूर्ण नही किये गये हैंए उनसे संम्पर्क कर शीघ्र पूर्ण करायें।

बैठक में जल निगम के अधिशाषी अभियंता एवं नेडा के मण्डलीय अधिकारी के उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मण्डल के जनपदों की जीडीपी को बढाये जाने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा दिये गये प्रजेन्टेशन के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए लाइनलास को कम किये जाने तथा खराब ट्रान्सफार्मर को समय से बदलने एवं विद्युत बिलों में समय से बिलों का सुधार कराये जाने एवं सभी अधिकारियों को नियमित रूप से टेलिफोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिये। जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के अन्तर्गत जिन गाँवों में कनेक्शन दिये गये हैंए वहां पर जलापूर्ति समय के अनुसार कराये जाने तथा जल निगम द्वारा टूटी सड़कों को मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बाढ प्रभावित ग्रामों को चिन्हित करते हुए बाढ चैकी की स्थापनाए बाढ से बचाव हेतु समस्त तैयारी किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर न घूमने पायें, उन्हें गौशालाओं में सुरक्षित रखने के साथ उनके चारे, पेयजल, छाया आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाए। जिन किसानों के द्वारा सहभागिता योजना के अन्तर्गत गायों को दिये जाने तथा लभार्थियों का भुगतान समय से कराया जाए। उन्होंने वृक्षारोपण में रोपित किये गये विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की जीओ टैगिंग कराये जाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उपाय किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संरक्षण हेतु मेडबन्दीएखेत.तालाब के अन्तर्गत जल संरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें कराये जाने की निर्देश दिए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने वाले कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश अपर निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को दिए।

टीम ने उर्वरक दुकान व गोदाम का किया निरीक्षण

फतेहपुर। जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि विकास खंड हसवा के ग्राम थरियांव स्थित राजकुमार पुत्र बनवारी लाल के उर्वरक दुकान व गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इफ्को की नकली व मिलावटी प्रतीत हो रही खुली 65 बोरियां, आईपीएल डीएपी की 700 बोरी, जिप्सम की 45 बोरी, किसान बेन्टोनाइट सल्फर की 02 बोरी, जिंक 25 पैकेट, भारत एनपीके 20-20-00-13 की 200 बोरी तथा खैतान एसएसपी की 20 बोरी बरामद हुई जिसका संबंधित के पास कोई अभिलेख नहीं पाया गया। संदिग्ध उर्वरकों के नमूने ग्रहीत कर विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं व संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जा रही है। डीएम ने निर्देशित किया कि किसी भी दशा में जनपद के कृषकों को नकली व मिलावटी खाद वितरित नहीं की जानी चाहिए, प्रत्येक दशा में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक प्राप्त कराये जाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

सीडीओ ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित माह जून 2024 की प्रगति आख्या के आधार पर कम रैंक प्राप्त कार्यक्रमों की सीडीओ अभिषेक कुमार ने सोमवार शाम को विकास भवन सभागार में समीक्षा की संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को महीने की अंतिम तिथि तक शत.प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी आवेदन समय सीमा के बाद लंबित ना रहे। फसल बीमा योजना में किसानों के फसल नुकसान के दावों को समय के अंदर भुगतान कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त स्वतः रोजगार द्वारा सभी ठडड को लक्ष्य निर्धारित कर उनके कार्यों साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के शत.प्रतिशत बैंक खाते खुलवाकर उन्हें सशक्त, क्रियाशील बनाने के लिए निर्देशित किया।

सीडीओ ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की स्थिति के बेहतर करते हुए रैंकिंग में उज्ज्वल से उत्कृष्ट तक लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देशित किया। गांव को उज्ज्वल से उत्कृष्ट में लाकर मॉडल बनाए। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवक्ता, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित निरीक्षण करनेए विद्यालयों में कालाकल्प के पैरामीटर शत.प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। ओडीओपी योजना के अन्तर्गत एजेन्सी न चुने जाने पर रोष जताते हुए एजेन्सी का जल्द से जल्द चुनकर इसके लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देशित किया। सभी विभाग माह जुलाई की ऑनलाइन प्रगति 30 जुलाई तक डीएसटीओ को उपलब्ध कराएं। बैठक में डीडीओ, उपायुक्त स्वतः रोजगार, डीएसटीओ, डीपीआरओ के अलावा अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारी उपस्थित हुए।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

● शोध, टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन देगी सरकार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अनुसंधान, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने और कृषि परिदृश्य में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान ढांचे की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा करेगी। शोध निधि चुनौती-आधारित होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुली होगी, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ शोध के संचालन की देखरेख करेंगे। सीतारमण ने घोषणा की कि किसानों की जल्द ही 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज वाली, जलवायु-सहिष्णु किस्मों तक पहुंच होगी।

महत्वपूर्ण फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने दलहन और तिलहन पर केंद्रित मिशन की योजनाओं का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सीतारमण ने कहा, अंतरिम बजट में घोषित की गई रणनीति के अनुसार, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, एक रणनीति बनाई जा रही है। अनुसंधान और फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आता है।

सीतारमण ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने की पहल की घोषणा की, जिसे प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करते हुए, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इस पहल में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान और भूमि रजिस्ट्री का निर्माण शामिल है।

सीतारमण ने कहा, चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला में किसान-उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने झींगा मछली उत्पादन और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली चारे पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर पांच प्रतिशत करने तथा झींगा एवं मछली चारे के निर्माण के लिए विभिन्न आदानों पर सीमा शुल्क में छूट देने का भी प्रस्ताव रखा। सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की योजनाओं का खुलासा किया। पांच राज्यों में जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम किया जाएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन ग्रामीण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान ने खुदकुशी की

मथुरा (उप्र)। मथुरा जनपद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा में तैनात प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 15वीं बटालियन के एक जवान ने अपनी बैरक में कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) अरविंद कुमार ने बताया कि सोमवार रात पीएसी के प्लाटून कमांडर ने सूचना दी थी कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा ड्यूटी कर रहे जवान सुधीर मलिक (25) ने हाईवे थानाक्षेत्र में स्थित पीएसी बैरक में सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुधीर गौतमबुद्ध नगर के निवासी थे। कुमार ने बताया कि वैसे तो यह साधारण खुदकुशी का मामला लग रहा है, परंतु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने तथा परिजनों द्वारा कोई तहरीर दिए जाने के बाद अन्य पहलुओं से भी जांच कराई जा सकती है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर संसद में विरोध जताएंगे इंडिया गठबंधन के घटक

भाषा। नई दिल्ली

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों ने मंगलवार को फैसला किया कि वे केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बुधवार को संसद के बाहर और भीतर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सदन में नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बैठक में खरगे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता टी आर बालू, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन एवं कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एवं राघव चड्ढा और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे।

बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। बजट में हिंदुस्तान के तीन चौथाई राज्यों खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। हम संसद के बाहर और भीतर अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा, यह अन्याय है। यह संघीय ढांचे के खिलाफ बजट है। तिवारी ने दावा किया, यह भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, भारत सरकार का बजट है। लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया कि मानो यह भाजपा का बजट हो।

वेणुगोपाल ने कहा, इस सरकार ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। अधिकतर राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए, इसका विरोध कैसे किया जाए, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से अनैतिक है। इससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के.स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।

2024 में जनगणना की संभावना नही, बजट में केवल 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित

भाषा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मंगलवार को जनगणना के लिए 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 की तुलना में काफी कम है। उस समय दशक में एक बार होने वाले इस कार्य के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपए की लागत से भारत की 2021 की जनगणना कराने और 3,941.35 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

जनगणना के तहत मकान सूचीकरण चरण और एनपीआर को अद्यतन करने का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। जनगणना कार्य अब भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक इसके लिए नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस वर्ष आम चुनाव हो चुके हैं, इसलिए 2024 में जनगणना का कार्य नहीं हो सकेगा। बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में 578.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। यह कार्य जब भी होगा, तो यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर प्रदान करेगी।

बजट में 10 लाख रुपए तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा, यूजीसी के आवंटन में कटौती

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि उच्च शिक्षा नियामक विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए अनुदान 60 प्रतिशत से अधिक घटा दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है। स्कूल शिक्षा के लिए बजट 535 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाया गया है लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9,600 करोड़ रुपए से अधिक कम हो गया।

शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की गई है। केंद्र ने 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रहे हमारे युवाओं की मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यापक और ठोस उपाय छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग-सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हैं। प्रधान ने कहा, इससे हमारे युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी, लोगों को अधिक आजीविका के अवसर मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल तक पहुंच बढ़ेगी और अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे।

शैक्षणिक संस्थानों में शोध और नवाचार के लिए बजट में 161 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह, विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए आवंटन 1,300 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए वित्त पोषण को पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 6,409 करोड़ रुपए से घटाकर 2,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 60.99 प्रतिशत कम हुआ है। सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में भी इसमें कटौती की गई थी।

प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों आईआईएम को लगातार दूसरे साल बजट में कटौती का सामना करना पड़ा है। पिछले साल आईआईएम के बजट को 608.23 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से घटाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस साल इसे 331 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से घटाकर 212 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के लिए बजट में भी पिछले साल के संशोधित अनुमान से मामूली कमी देखी गई है। पिछले साल का संशोधित अनुमान 10,384.21 करोड़ रुपए था और चालू वित्त वर्ष के लिए 10,324.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 6,21,940 करोड़ रुपए का प्रावधान

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को 2024-25 में रक्षा व्यय के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के साथ-साथ रणनीतिक जलमार्गों में उभरती सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच अंतरिम बजट में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर ही है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 6,21,540 करोड़ रुपए था। रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 2023-24 में किए गए बजटीय प्रावधान की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के लिए सेना को 1,72,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिसमें मुख्य रूप से नए आयुध, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है। दैनिक परिचालन लागत और वेतन के लिए राजस्व व्यय 2.82 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए चिह्नित किए गए हैं, जो 2023-24 में किए गए आवंटन से 2.17 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र का कुल बजट भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। पूंजीगत परिव्यय पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवंटन का उद्देश्य मौजूदा और बाद के वित्त वर्षों में बड़े अधिग्रहणों के जरिए बड़े क्षमता अंतराल को पाटना है। उसने कहा, ए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित वायु यान, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से होने वाले पूंजी अधिग्रहणों पर वार्षिक नकद व्यय की जरूरत को पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण बजट का 75 प्रतिशत यानी 1,05,518.43 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू उद्योगों के जरिए खरीद के लिए तय किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वास्तविक अर्थों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बलों को पूंजीगत मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 प्रतिशत ज्यादा और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 प्रतिशत ज्यादा है। उसने कहा, परिचालन तत्परता के लिए निरंतर ऊंचा आवंटन सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है। सरकार ने इस मद में चालू वित्त वर्ष के दौरान 92,088 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू पूंजी खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जहां तक रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन की बात है, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6,21,940.85 करोड़ रुपए के सर्वाधिक आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं जो 2024-25 के लिए सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 1,72,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देगा। सिंह ने कहा, मुझे खुशी है कि सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक आवंटन किया गया है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपए का यह आवंटन हमारे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को और गति देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी और तेज गति वाले विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, यह बजट देश के आर्थिक बदलाव को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह 2027 तक भारत को 5 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

त्रिपुरा में 70 प्रतिशत पंचायत सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते

अगरतला। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में लगभग 70 प्रतिशत सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पंचायत प्रणाली में कुल 6,889 सीट हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं और भाजपा को 4,805 सीट पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। ग्राम पंचायतों में भाजपा को कुल 6,370 सीट में से 4,550 पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। इस वजह से 71 प्रतिशत सीट पर मतदान नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के सचिव असित कुमार दास ने बताया कि जिन 1,819 ग्राम पंचायत सीट पर मतदान होगा।

पुंछ में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम एक जवान बलिदान

जम्मू। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिस दौरान एक जवान बलिदान हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। कोर ने कहा, भारी गोलीबारी के दौरान एक वीर जवान घायल हो गया। अभियान जारी है। सैनिकों को कृष्णाघाटी के बट्टल अग्रिम क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह की गतिविधियों का पता चला और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लांस नायक सुभाष कुमार भीषण मुठभेड़ में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को भी नुकसान पहुंचा है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 574 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का पहला बजट है। सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था, हालांकि संशोधित बजट में यह राशि 2608.93 करोड़ रुपए हो गई थी।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3183.24 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इस बार 326.16 करोड़ रुपए तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में कुल 1575.72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मंत्रालय की प्रमुख योजनाओंपरियोजनाओं के लिए कुल 2120.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए इस बार 910.90 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी व लोस अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक्स कॉर्प और गूगल इंक को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंतरिम आदेश में अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा, और यदि वादी को समान तरह की किसी अन्य पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेंगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स , गूगल , केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा।

अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी बन गईं। अंजलि के वकील ने बताया कि वह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थीं और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वह आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं।

सुनवाई के दौरान अंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा, तीन साल बाद, यह सोशल मीडिया अभियान फिर से शुरू हो गया है जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी बदनाम करता है, जिसमें उनके पिता भी शामिल हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ संवैधानिक पद पर आसीन हैं।

अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल 2021 में एक अधिकारी बनी, लेकिन अब नीट और यूपीएससी परीक्षा विवाद के कारण अचानक ए चीजें फिर से सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब इसका हिस्सा हैं। अधिवक्ता ने कहा कि अंजलि (वादी) की निजी तस्वीरें यह कहते हुए ऑनलाइन पोस्ट की जा रही हैं कि वह एक मॉडल हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि साइबर अपराध विभाग में भी इसकी शिकायत की गई है।

पेज 1 का शेष

मध्यम वर्ग...

15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुई है। सीतारमण ने कहा, ऐसे समय जब दुनिया में अनिश्चितताएं हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि एक अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग और पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपए करने के साथ नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव किया। मानक कटौती के तहत आयकर की गणना करने से पहले वर्ष में अर्जित कुल वेतन में से निश्चित राशि घाटा दी जाती है। उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 17,500 रुपए तक की बचत होगी।

युवाओं के...

के वेतन का भुगतान, दोनों कर्मचारियों को निर्दिष्ट बिक्री पर प्रोत्साहन और रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके सेवानिवृत्ति निधि योगदान के संबंध में सशक्तिकरण और नियोक्ताओं को रुपये तक की प्रतिपूर्ति शामिल है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल के लिए 3,000 प्रति माह। चूंकि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव का सामना करने के लिए तैयारी कर रही है, इसलिए भी यह तत्परता महसूस की जा रही है, जहां पार्टी को लोकसभा चुनावों में झटका लगा था। मोदी 3.0 का बजट इस बात का भी संकेत है कि सरकार रोजगार सृजन पर अधिक गंभीरता से विचार करेगी, यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि बेरोजगारी और बेरोजगार विकास अभियान के दौरान और उसके दौरान विपक्ष के कथन का प्रमुख विषय रहा है। सीतारमण ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए तीन योजनाएं पेश कीं, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान को लक्षित करना और पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना, रोजगार सृजन पर स्पष्ट जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अगले पांच वर्षों में नौकरियां पैदा करने के लिए 2 ट्रिलियन रुपये आवंटित करेगा। सीतारमण ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, कौशल में सुधार और उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के कार्यक्रमों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र सहित कंपनियों के लिए प्रोत्साहन शुरू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत है, लेकिन निजी एजेंसी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसे 8.4 प्रतिशत से अधिक बताती है। फर्स्ट टाइमर्स योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। तीसरी योजना नियोक्ता केंद्रित होगी जो सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। प्रति माह एक लाख रुपये के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है। चूंकि भाजपा पिछले कुछ वर्षों से एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के विरोध का सामना कर रही थी और हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपनी लोकसभा सीटों में गिरावट को देखते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों के लिए नए 109 उच्च उपज वाले, जलवायु लचीले बीज जारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभोग केंद्रों के करीब विकसित किए जाएंगे। हम संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे। 6 करोड़ किसानों और उनके बारे में वित्त मंत्री ने कहा, भूमि को किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में लाया जाएगा, इसके अलावा, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम बनाया जाएगा।

सुनहरे...

आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने और उस पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इससे नया मध्यम वर्ग बना है, यह उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का भी बजट है। उन्होंने कहा, यह नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।

बिहार...

वहीं जेडी (यू) के लोकसभा में 12 सदस्य हैं, जो इसे सत्तारूढ़ गठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा घटक बनाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश को समर्थन देने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट ने बिहार के लिए बड़े उपायों की घोषणा की, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया गया, जिसमें तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारे और नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण शामिल है। सीतारमण ने तीन सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की। बजटीय घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंध्र प्रदेश टीडीपी सुप्रीमो और सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जरूरतों को पहचानने और केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी और सीतारमण को धन्यवाद दिया। अपनी प्रतिक्रिया में, केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने विपक्ष के इस दावे की आलोचना की कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट के उपायों का उद्देश्य अस्तित्व के लिए राज्यों के क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता के कारण सरकार को बचाना है। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने या तो दर्जा या विशेष वित्तीय पैकेज मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई विकास उपायों की सीतारमण की घोषणाओं को अपनी सरकार को 'बचाने' के लिए भाजपा की राजनीतिक मजबूरी से जोड़ा और पूछा कि क्या भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए कुछ है।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, अन्य उपायों की घोषणा

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी से सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी।अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीतारमण ने कहा, हमने एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, नियामकीय बदलाव और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए एक पैकेज तैयार किया है, ताकि उन्हें बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना ऐसी संस्थाओं के ऋण जोखिमों को एकत्रित करके संचालित होगी। वित्त मंत्री ने कहा, अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्एक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर प्रदान करेगी, जबकि कर्ज राशि इससे अधिक हो सकती है। उधारकर्ता को अग्रिम गारंटी शुल्क तथा कम किए गए ऋण शेष पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। उन्होंने संकट काल में एमएसएमई को बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को अपने नियंत्रण से परे कारणों से विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) चरण में होने के बावजूद अपना कारोबार जारी रखने और एनपीए चरण में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ऋण उपलब्धता को सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने एमएसएमई को ऋण देने के लिए एक नए मूल्यांकन मॉडल की भी घोषणा की।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ए केंद्र निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक ढांचे के तहत एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करेगी। टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ...बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए सक्षम नीतियां व नियम भी लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तरह किराए के आवास की सुविधा प्रदान करेगी। यह कार्य वीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड में किया जाएगा। कर प्रस्तावों पर सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि मकान या मकान के किसी हिस्से को मालिक द्वारा किराए पर देने से होने वाली आय को व्यापार या पेशे से होने वाले लाभ व प्राप्ति शीर्षक के तहत नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस पर केवल गृह संपत्ति से आय शीर्षक के तहत कर लगाया जाएगा। अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक हस्तांतरक या हस्तांतरिती हैं, तो अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए ऐसा प्रतिफल, सभी हस्तांतरितियों द्वारा हस्तांतरक को या सभी हस्तांतरकों द्वारा ऐसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई या देय राशि का योग होगा। सीतारमण ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, पूर्ण और सत्य खुलासा करने पर बेनामीदार को दंड तथा अभियोजन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। संपत्ति की कुर्की और न्याय निर्णय प्राधिकरण को संदर्भित करने के लिए समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।

महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचारः सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करप्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा`गी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा,`हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सकें। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कराधान उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान का उल्लेख बंद करने का भी प्रस्ताव रखा।

शेयर पुनर्खरीद पर चुकाई गई राशि को लाभांश माना जाएगा, शेयरधारकों पर लगेगा करः सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद पर शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश के समान कर लगाया जाएगा। यह एक ऐसा कदम जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, इन शेयरों को हासिल करने के लिए शेयरधारक जिस राशि का भुगतान करेंगे, उसे उनके पूंजीगत लाभ या हानि की गणना में जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, इक्विटी के लिए मैं प्राप्तकर्ता के हाथों में शेयरों की पुनर्खरीद से हुई आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। यह प्रस्ताव है कि कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय को प्राप्तकर्ता निवेशक को मिले लाभांश के रूप में मानकर कर लिया जाए। वर्तमान व्यवस्था के तहत इसे कंपनियों को हुई अतिरिक्त आमदनी मानकर इस पर आयकर लगाया जाता है।

दूरसंचार मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ आवंटित

बीएसएनएल को 82,916 करोड़ रुपए मिले

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है।कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। बजट के अनुसार, बजट अनुमान 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपए (1,11,915.43 करोड़ रुपए और 17,000 करोड़ रुपए) है। 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। बजट में प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 34.46 करोड़ रुपए, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए 70 करोड़ रुपए तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 1,806.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवंटन के अलावा, सरकार ने घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मैं निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।ूरसंचार पीसीबी निर्माण के लिए मूल सीमा शुल्क में वृद्धि, संचार उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों को छूट के साथ आती है।वित्त मंत्री ने 25 खनिजों जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है। ए खनिज परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क कम किया जाएगा।सीतारमण ने कहा, इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा तथा इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र ने भविष्यदर्शी बजट की सराहना की

टिकैत ने खाली हाथ बताया

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर कृषि क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग विशेषज्ञों ने शोध और आत्मनिर्भरता पर इसके ध्यान बिन्दु (फोकस) की प्रशंसा की है, जबकि कुछ किसान नेताओं ने बजट पर निराशा जताई है। कृषि उद्योग के विशेषज्ञों ने बजट को भविष्यदर्शी बताते हुए इसकी सराहना की है, जिसमें कृषि-अनुसंधान और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हालांकि, भारत किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट ने किसानों को खाली हाथ छोड़ दिया क्योंकि यह प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन का स्वागत करते हुए कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयात निर्भरता को कम करने में परिवर्तनकारी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण मिशन को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

टिकैत ने जलवायु परिवर्तन के नाम पर कृषि अनुसंधान में निजी क्षेत्र को धन मुहैया कराने, विदेशी लॉबी समूहों और बड़ी कंपनियों को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने देने पर चिंता व्यक्त की। गुड फूड इंस्टिट्यूट इंडिया की कार्यवाहक प्रबंध निदेशक स्नेहा सिंह ने कहा, हम आयात पर निर्भरता कम करने और प्लांट प्रोटीन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अधिक रास्ते बनाने के लिए दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर विशेष ध्यान देने की सराहना करते हैं। धानुका समूह के अध्यक्ष आर जी अग्रवाल ने कहा, बजट ने अनुसंधान और विकास में कम निवेश और कम फसल पैदावार की दोहरी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूआरएमएस) के सह-संस्थापक और सीटीओ, आशीष अग्रवाल ने कहा, इस प्रगति का पूरा लाभ उठाने के लिए, आईओटी, एआई और डेटा एनालिटिक्स में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

बजट घोषणाओं से शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव

सेंसेक्स, निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद

मुंबई।(भाषा) वायदा एवं विकल्प सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मंगलवार को बजट में प्रावधान किए जाने से घरेलू शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव रहा। हालांकि, मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आखिर में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स एक समय।,200 अंक से ज्यादा गोता लगा गया था। लेकिन बजट भाषण खत्म होने के बाद इसने धीरे-धीरे अपने नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली। कारोबार के अंत में यह 73.04 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 80,429.04 अंक पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले कर एसटीटी में बढ़ोतरी और इक्विटी निवेश पर दीर्घकालिक अवधि में होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर को बढ़ाने की घोषणा की। बजट में इन कदमों की घोषणा होते ही शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर गिरावट देखी जाने लगी। उस समय सेंसेक्स।,277.76 अंक यानी 1.58 प्रतिशत तक टूटकर 79,224.32 अंक के निचले स्तर पर आ गया था। हालांकि, कर रियायतों और सीमा शुल्क में कटौती ने टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों और दैनिक उपभोग वाले सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) के शेयरों को बढ़ावा देने में मदद की, जिससे शेयर दिन के निचले स्तर से उबरने में सफल रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 30.20 अंक यानी 0.12 प्रतिशत गिरकर 24,479.05 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 435.05 अंक यानी 1.77 प्रतिशत फिसलकर 24,074.20 पर आ गया था। सेंसेक्स के समूह में शामिल टाइटन ने छह प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई जबकि आईटीसी में पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़त रही।

इनके अलावा अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और सन फार्मा के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए।

संक्षिप्त समाचार

कई खरीदारों को 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर लगेगा एक प्रतिशत टीडीएस

नई दिल्ली। वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 50 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगेगा, भले ही लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों। कर प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामलों के बीच सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधान का उल्लेख किया। बजट दस्तावेज के मुताबिक, अधिनियम की धारा 194-आईए में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले के भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान है। इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में किए गए संशोधन एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा, यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक विक्रेता या खरीदार होने की स्थिति में भुगतान सभी विक्रेताओं को चुकाई गई राशि का योग होगा। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, एक खरीदार अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विक्रेता को भुगतान की गई राशि पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है। बजट दस्तावेज में सरकार ने धारा 194-आईए की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए चुकाई गई कुल राशि को इसका मूल्य माना जाएगा।

सरकार राज्यों को संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संपत्तियों की खरीद पर अधिक स्टाम्प शुल्क लगाने वाले राज्यों को दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुधार शहरी विकास योजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा होगा।उन्होंने राज्यों से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क को और कम करने पर विचार करने को भी कहा। सीतारमण ने कहा, हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं, ताकि सभी के लिए दरों में कमी की जा सके और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार किया जा सके। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य तत्व बनाया जाएगा। स्टाम्प शुल्क एक ऐसा कर है जो राज्य सरकारों द्वारा संपत्तिसंपत्ति स्वामित्व की बिक्री पर लगाया जाता है। यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा तीन के तहत देय है। राज्यों के लिए स्टाम्प शुल्क विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

रेलवे का बड़ा ध्यान सुरक्षा संबंधी कार्यों, कवच लगाने परः वैष्णव

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा रेल सुरक्षा संबंधी गतिविधियों और स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली कवच पर खर्च करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आम बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए यह बात कही। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पूंजी निवेश के लिए एक रिकॉर्ड आवंटन है। वैष्णव ने कहा, इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा -।,08,795 करोड़ रुपए - सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए है, जैसे पुरानी पटरियों को नए से बदलना, सिग्नल प्रणाली में सुधार और फ्लाईओवर तथा अंडरपास का निर्माण, और कवच लगाना। उन्होंने कहा कि इन सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में कवच लगाना रेलवे की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।

मंत्री के अनुसार स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली के उन्नत संस्करण कवच 4.0 को हाल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन से मंजूरी मिली है। अब इसे तेजी से रेलगाड़ियों में लगाया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि कवच के घटकों में शामिल ऑप्टिकल फाइबर केबल 4,275 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिछाई गई है और अन्य घटक- जैसे दूरसंचार टावर, ट्रैक आरएफआईडी उपकरण, स्टेशन कवच और लोको कवच भी तेजी से लगाए जा रहे हैं। संप्रग शासन के दौरान रेलवे के लिए बजटीय आवंटन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के आसपास रेलवे के लिए बजटीय आवंटन केवल लगभग 35,000 करोड़ रुपए हुआ करता था और आज यह 2.62 लाख करोड़ रुपए के नए स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के शासन की कड़ी मेहनत और लक्ष्य केंद्रित नजरिए को आगे बढ़ाता है।

अर्थशास्त्रियों ने कहा, बजट में रोजगार मुद्रास्फीति पर ध्यान देना अच्छा संकेत

नई दिल्र्ली (भाषा) प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने मंगलवार को बजट 2024-25 को रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति प्रबंधन और राजकोषीय विवेक पर केंद्रित बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत बताया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को पहली प्राथमिकता दी है। कुमार ने कहा, इससे पता चलता है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वह कुछ अर्थशास्त्रियों की तरह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के झूठे दावों से प्रभावित नहीं हो रही है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती ने पीटीआई-भाषा से कहा कि केंद्र सरकार के ऋण और घाटे को राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप स्तर तक कम करने के लिए राजकोषीय विवेक के एक स्थिर मार्ग पर चलना जारी रखना होगा। उन्होंने कहा, बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने पीटीआई-भाषा से कहा, केंद्रीय बजट 2024-25 मोटे तौर पर अंतरिम बजट की ही निरंतरता है जिसमें कुछ बेहतर राजकोषीय गुंजाइश के साथ-साथ नौकरियों की ओर भी ध्यान दिया गया है। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक नागेश कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वित्त मंत्री का बजट व्यापक क्षेत्र को अपने दायरे में लेने वाला है। प्रमुख विषयों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था की स्थिरता और गतिशीलता को बढ़ाना शामिल है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी है तो उसके आवंटन को काफी हद तक बढ़ाना होगा, न कि मामूली रूप से। उन्होंने कहा, रोजगार सृजन के लिए पूंजी गहन क्षेत्रों के बजाय श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

हमास और फतह ने मतभेद खत्म करने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए

भाषा। बीजिंग

गाजा में युद्ध के बीच एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फतह और हमास सहित 14 फलस्तीनी समूहों ने मंगलवार को चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में, आपसी मतभेदों को खत्म करने और फलस्तीनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले तीन दिन प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बातचीत का समन्वय किया। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह घोषणा इजराइली हमलों से त्रस्त गाजा पट्टी में व्यापक, टिकाऊ और सतत युद्धविराम को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम है। चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने इन गुटों के नेताओं से मुलाकात की और कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर फलस्तीन मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक क्षण है।

उन्होंने कहा कि समझौते के तहत प्रतिद्वंद्वी समूह युद्ध के बाद गाजा पर शासन करने के लिए एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार बनाने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ संघर्ष में फलस्तीनियों को एकजुट करना है। इजराइल ने पिछले साल अक्टूबर में 200 से अधिक इजराइली बंधकों के अपहरण के बाद गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। हस्ताक्षरकर्ताओं में हमास के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक और फतह के दूत महमूद अल-अलौल के साथ-साथ 12 अन्य फलस्तीनी समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार है जब 14 प्रतिद्वंद्वी समूह सुलह वार्ता के लिए बीजिंग में एकत्र हुए। वांग ने कहा, सुलह फलस्तीनी गुटों का आंतरिक मामला है, लेकिन साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। वांग ने कहा, मुख्य परिणाम यह है कि पीएलओ (फलस्तीन मुक्ति संगठन) सभी फलस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध के बाद शासन और एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार के गठन पर समझौता हुआ है। हालांकि, वांग की टिप्पणियों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमास, जो पीएलओ का हिस्सा नहीं है, ऐसी व्यवस्था में क्या भूमिका निभाएगा, या किसी भी समझौते का तत्काल प्रभाव क्या होगा। हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है, जबकि फतह फलस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रित करता है, जिसका वेस्ट बैंक पर आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण है। इजराइल ने गाजा में युद्ध समाप्त होने से पहले हमास को नष्ट करने का संकल्प लिया है। इजराइल ने बीजिंग घोषणा को तुरंत खारिज कर दिया। इजराइल के विदेश मंत्री आई. काट्ज ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, आतंकवाद को खारिज करने के बजाय, महमूद अब्बास हमास के हत्यारों और बलात्कारियों को गले लगाते हैं, जिससे उनका असली चेहरा सामने आया है। इस घोषणापत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं, जब इजराइल और हमास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नौ महीने से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइली नागरिकों की आजादी की राह तैयार कर सकता है।

हालांकि, समझौते पर सहमति बनने के बावजूद युद्ध के बाद गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल इस क्षेत्र के शासन में हमास की किसी भी भूमिका के खिलाफ है। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी के मुताबिक, फलस्तीन के दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों ने मतभेद खत्म करने और फलस्तीनी एकता को मजबूत करने के संबंध में बीजिंग घोषणापत्र पर दस्तखत किए। हमास ने वर्ष 2007 में हिंसक संघर्ष के दौरान फलस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह लड़ाकों को गाजा पट्टी से खदेड़कर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों समूह एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।

साल 2023 में करीब चार करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रह रहे थेः संयुक्त राष्ट्र

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल करीब चार करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रह रहे थे और 90 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था जिसके चलते हर मिनट एड्स संबंधी कारण से किसी न किसी संक्रमित की मौत हुई है। एचआईवी संक्रमण आगे जाकर एड्स बन जाता है। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए प्रगति तो हो रही है, लेकिन इसकी गति धीमी हो गई है, वित्तपोषण कम हो रहा है तथा नए क्षेत्रों -पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तथा लैटिन अमेरिका में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएड्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में 6.30 लाख लोगों की एड्स से संबंधित बीमारियों के कारण मौत हो गई। इस तादाद में 2004 की तुलना में खासी कमी आई है जब 21 लाख लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा एड्स से संबंधित मौतों की संख्या को 2025 तक ढाई लाख से कम कम करने के लक्ष्य का दोगुना से ज्यादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक असमानता लड़कियों और महिलाओं के लिए जोखिम बढ़ा रही है तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में किशोरों और युवतियों में एचआईवी के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं।

यूएनएड्स की कार्यकारी निदेशक विनी ब्यानईमा ने कहा, वैश्विक नेताओं ने संकल्प लिया है कि 2030 तक एड्स महामारी को लोक स्वास्थ्य के लिए खतरे के तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा और वे अपना वादा निभा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे यह सुनिश्चित करें कि एचआईवी संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, और सभी के मानवाधिकारों की रक्षा हो। रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 3.99 करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रहे थे जिनमें से 86 फीसदी को पता था कि वे संक्रमित हैं जबकि 77 प्रतिशत संक्रमित इलाज करा रहे थे।

ब्रिटेन की संसद में सुनक दो नवंबर तक अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे

लंदन। ब्रिटेन की संसद में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दो नवंबर तक अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की समय सारिणी के अनुसार नवंबर तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। टोरी (कंजर्वेटिव पार्टी) का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय करने के लिए संसद के बैकबेंच सदस्यों की 1922 समिति ने सोमवार शाम को दो चरण की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके तहत दो नवंबर को नए नेता की नियुक्ति की जाएगी।

ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक (44) ने आम चुनाव में पार्टी की सबसे बुरी हार के बाद पांच जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता तब तक वह टोरी के अंतरिम नेता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे।

सुनक ने कहा, पार्टी का नेतृत्व हासिल करने के उम्मीदवारों या इससे जुड़े अभियान के बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। मुझे विश्वास है कि पार्टी बोर्ड और 1922 समिति द्वारा तय की गई यह समय सारिणी एक विचारशील, पेशेवर और सम्मानजनक मुकाबले की अनुमति देगी। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नेताओं में भारतीय मूल की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल और सुएला ब्रेवरमैन, शैडो मंत्री जेम्स क्लेवरली, केमी बेडेनोच, टॉम तुगेंदट, मेल स्ट्राइड और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक शामिल हैं।

ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं : कमला हैरिस

वाशिंगटन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले के साथ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। डेलावेयर के विलमिंगटन में सोमवार को अपनी प्रचार टीम को संबोधित करते हुए कमला (59) ने कहा कि ट्रंप का विवादित प्रोजेक्ट 2025 मध्यम वर्ग को कमजोर करेगा और हमें एक बार फिर उन विफल नीतियों की ओर ले जाएगा, जिनके तहत अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को करों में भारी छूट दी गई और कामकाजी लोगों से इसकी भरपाई करवाई गई।

राष्ट्रपति जो बाइडन (81) के गत रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला (59) के नाम की सिफारिश की थी। इसके अगले दिन बाइडन की प्रचार अभियान टीम का नाम बदलकर हैरिस कैंपेन कर दिया गया था। कमला ने प्रचार टीम के सदस्यों से कहा कि वह बाइडन-हैरिस कैंपेन टीम को बरकरार रख रही हैं।

ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को उस दौर में ले जाना चाहते हैं, जब कई अमेरिकियों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार हासिल नहीं थे। लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य में यकीन करते हैं, जिसमें सभी अमेरिकियों के लिए जगह है। हम एक ऐसे भविष्य में यकीन करते हैं, जहां हर व्यक्ति के पास न केवल आजीविका जुटाने का, बल्कि आगे बढ़ने का भी मौका हो।

कमला ने कहा, हम ऐसे भविष्य में यकीन करते हैं, जहां किसी भी बच्चे को गरीबी में न पलना-बढ़ना पड़े, जहां हर व्यक्ति घर खरीद सके, परिवार बढ़ा सके और धन अर्जित कर सके, जहां हर व्यक्ति को सवैतनिक पारिवारिक अवकाश और बच्चों की किफायती देखभाल की सुविधा मिले। हम ऐसा ही भविष्य चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को किफायती स्वास्थ्य देखभाल मिले, जहां हर कर्मचारी को उचित वेतन मिले, और जहां हर वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो सके। ए सब मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल के अहम लक्ष्य होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मध्यम वर्ग मजबूत होगा, तो अमेरिका मजबूत होगा।

कमला ने आरोप लगाया कि यह वह भविष्य नहीं है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप और उनका विवादित प्रोजेक्ट-2025 मध्यम वर्ग को कमजोर कर देगा। यह हमें उन विफल नीतियों की ओर वापस ले जाएगा, जिनके तहत अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को भारी कर छूट दी गई और कामकाजी वर्ग से इसकी भरपाई करवाई गई। कमला ने याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति बनने या सीनेट के लिए चुने जाने से पहले वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थीं। उन्होंने लंबे समय तक वकालत भी की।

इथियोपिया में भूस्खलन में बच्चों समेत कम से कम 157 लोगों की मौत

अदीस अबाबा। इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्राधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्थानीय प्रशासक दागमावी आएले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबेयनेह ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 157 हो गई। सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है। ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए। उस समय बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। आएले ने बताया कि मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया। गोफा में एक अन्य अधिकारी मार्कोस मेलीसे ने बताया कि अन्य लोगों को बचाने की कोशिश करते वक्त भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से कई लापता हैं। गोफा जोन में आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी के निदेशक मेलीसे ने बताया, हम अब भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया, कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट कर रो रहे हैं। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

वेंस ने अपनी शुरुआती चुनावी रैलियों में कमला हैरिस पर तीखे हमले किए

रेडफोर्ड (अमेरिका)। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जे डी वेंस ने सोमवार को अपनी शुरुआती चुनावी रैलियों में मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर तीखे हमले किए। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से हटने की घोषणा की और इस पद के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था। ओहायो के सीनेटर ने वर्जीनिया के रेडफोर्ड में शाम को एक रैली को संबोधित करने से पहले मिडलटाउन में अपने पूर्व हाई स्कूल में प्रचार किया। वेंस ने वर्जीनिया में कहा, इतिहास जो बाइडन को मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ ही अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में याद रखेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, कमला हैरिस उनसे भी लाख गुना बदतर हैं और यह बात हर कोई जानता है। उन्होंने जो बाइडन की हर विफलता पर मुहर लगाई है और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम करने की उनकी (बाइडन) मानसिक क्षमता के बारे में झूठ बोला है। वेंस (39) ने अपनी और हैरिस की जीवनशैली की भी तुलना की। उन्होंने कहा कि वह मरीन कोर में सेवा दे रहे थे और छोटा-सा कारोबार चला रहे थे जबकि हैरिस पिछले 20 साल से सरकारी तनख्वाह पा रही हैं। ट्रंप और वेंस ने शनिवार को फॉक्स न्यूज को संयुक्त साक्षात्कार दिया था जिसका प्रसारण वेंस की रैलियों के बाद सोमवार शाम को किया गया।

ब्रिटिश-पाकिस्तानी कट्टरपंथी उपदेशक आतंकी संगठन को दिशा-निर्देश देने के लिए दोषी करार

लंदन। ब्रिटिश-पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामवादी उपदेशक अंजम चौधरी को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को दिशा-निर्देश देने का दोषी पाया गया और संयुक्त अंतरराष्ट्रीय जांच के बाद ब्रिटेन में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। चौधरी (57) को अल-मुहाजिर (एएलएम) में कार्यवाहक की भूमिका निभाते पाया गया था और लंदन के वूलविच क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उसने 2014 के बाद एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए आतंकवादी समूह को दिशा-निर्देश दिए थे और ऑनलाइन माध्यम से की गई बैठकों को संबोधित करके संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया था। 30 जुलाई को उसे सजा सुनाई जाएगी, माना जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की ओर से की गई जांच के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो पाई।

श्रीलंका ने नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया

कोलंबो। श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वर्ष श्रीलंका द्वारा ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 261 हो गई है। नौसेना ने कहा कि उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के डेल्फ्ट द्वीप पर नौ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी दो नौकाएं जब्त की गई। नौसेना ने 11 जुलाई को कहा था कि इस साल अवैध शिकार करने को लेकर 252 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और 35 नौकाएं जब्त की गई है। इस माह के आरंभ में श्रीलंका ने भारत के समक्ष एक नौसैनिक की मौत के मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। नौसैनिक की द्वीपीय राष्ट्र के जलक्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से मछली पकड़ने में लगी एक भारतीय नौका को जब्त करने के अभियान के दौरान मौत हो गई थी।

कनाडा में स्वामी नारायरण मंदिर को विरूपित किया गया

ओटावा। कनाडा के एडमॉन्टन शहर में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर कथित तौर पर घृणास्पद और भारत विरोधी बातें लिखकर उसे विरूपित किए जाने का मामला सामने आया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हम एडमॉन्टन में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर को भारत विरोधी नारे लिखकर विरूपित किए जाने की निंदा करते हैं। हमने कनाडाई अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्वाई करने का अनुरोध किया है।

मंदिर संचालन संस्था बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण (बीएपीएस) ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एडमॉन्टन सेंटर से सांसदाप्रतिनिधि रैंडी बोइसोनॉल्ट ने कहा, एडमॉन्टन मंदिर को पेंट से विरूपित किया गया, उस स्थान की दीवारों पर घृणित बयानबाजी लिखी गई, जो शरणस्थली होना चाहिए था। कनाडा में घृणा का कोई स्थान नहीं है - पूजा और प्रार्थना के स्थानों पर तो कतई नहीं। यह घटना निंदनीय है और हमारे शहर के मूल्यों के विरुद्ध है।

कनाडा में हिंदू व्यापारिक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीएचसीसी) के एक बयान में कहा गया, यह घटना न केवल एक भौतिक संरचना पर हमला है, बल्कि हिंदू समुदाय की भावनाओं और हमारे समाज के सम्मान एवं सहिष्णुता के सिद्धांतों का भी अपमान है। उसने घृणा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य और कनाडा में हिंदूफोबिया (हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रह) की बढ़ती लहर की निंदा की और कहा, ए घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं और हमारे बहुसांस्कृतिक एवं समावेशी समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। पिछले साल मंदिरों को विरूपित किए जाने की कम से कम तीन घटनाएं हुई थीं।

मध्य माली में हिंसक हमले में कम से कम 26 ग्रामीणों की मौत

बमाको। बुर्किना फासो की सीमा के समीप माली के मध्य क्षेत्र के एक गांव पर एक सशस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बैंकोस कस्बे के मेयर मौलाए गुइंडो ने बताया कि डेंबो गांव में हमलावरों ने रविवार शाम को ग्रामीणों पर उस समय हमला कर दिया, जब उनमें से अधिकतर लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। देश की सैन्य सरकार उत्तरी क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। मध्य माली में ऐसे हमले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार के हुए हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे अल-कायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन जेएनआईएम का हाथ माना जा रहा है जो क्षेत्र के ग्रामीणों को अक्सर निशाना बनाता है। विद्रोहियों ने जुलाई में भी इसी तरह एक विवाह समारोह पर हमला किया था और कम से कम 21 लोगों की हत्या कर दी थी।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा आतंकवाद जैसा खतरा : ब्रिटेन की पुलिस ने दी चेतावनी

भाषा। लंदन

ब्रिटेन के पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक बढ़ गई है और पुलिस इससे आतंकवाद के खतरे के तौर पर निपट रही है। नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल और कॉलेज ऑफ पुलिसिंग द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की पुलिस ने 2022 से 2023 के बीच महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं जो इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए कुल मामलों का पांचवां हिस्सा है।

इसी अवधि में हर छह में से एक हत्या घरेलू हिंसा से संबंधित थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 12 में से एक महिला यौन अपराध, बलात्कार, पीछा करने, उत्पीड़न या ऑनलाइन यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों का शिकार होती है। हालांकि, यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि इस तरह के अपराध के कई मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं।

उप प्रमुख कांस्टेबल मैगी ब्लिथ ने एक बयान में कहा, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक राष्ट्रीय आपात स्थिति है। उन्होंने कहा, हमें बदलाव लाने के लिए एक समाज के रूप में आगे बढ़ना होगा और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को अपरिहार्य मानना बंद करना होगा। ब्रिटेन की सरकार ने पिछले वर्ष, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खतरा माना था, तथा पुलिस से कहा गया था कि उसे इस मुद्दे को आतंकवाद और गंभीर संगठित अपराध के समान प्राथमिकता देना चाहिए।

कोविड-19 पीड़ितों के जबरन दाह संस्कार पर मुसलमानों से माफी मांगेगी श्रीलंकाई सरकार

भाषा। कोलंबो

श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कोविड-19 से जान गंवाने वाले मुस्लिम व्यक्तियों के जबरन दाह संस्कार के लिए देश के मुस्लिम समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। श्रीलंकाई सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कोरोना महामारी के दौरान विवादित शवदाह नीति लागू की थी। वर्ष 2020 में कोविड-19 पीड़ितों के दाह संस्कार का अनिवार्य आदेश जारी किया गया था जिससे मुसलमानों सहित कई अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। हालांकि, बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बीच फरवरी 2021 में इस आदेश को रद्द कर दिया गया था।

एक कैबिनेट नोट के अनुसार, श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक बैठक में मार्च 2020 में थोपे गए आदेश के लिए मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से सभी समुदायों से माफी मांगने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने ऐसे विवादास्पद कदमों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कानून लाने का भी निर्णय लिया। बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने धर्म के आधार पर शवों को दफनाने या दाह संस्कार पर एक प्रस्तावित कानून को भी मंजूरी दे दी है। इसमें एक कानून लाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो किसी खास व्यक्ति या रिश्तेदारों को मृत व्यक्ति को दफनाने या उसका दाह संस्कार के चयन की अनुमति देगा।

मुस्लिम समुदाय ने जबरन दाह संस्कार नीति का विरोध किया था और कुछ ने तो अपने प्रियजनों के शवों को अस्पताल के मुर्दाघरों में छोड़ दिया था। समुदाय के सदस्यों ने कहा था कि या तो उन्हें शव जलाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया गया था या उनकी जानकारी के बिना ऐसा किया गया था। इस्लाम में शव दाह वर्जित है।

फरवरी 2021 में आदेश के रद्द किए जाने से पहले श्रीलंका में 276 मुस्लिमों का दाह संस्कार किया गया। श्रीलंका की सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देकर दफनाने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया था। तब सरकार ने कुछ विशेषज्ञों की राय का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने से जल स्तर प्रदूषित हो जाएगा जिससे महामारी और फैलेगी।

कमला के लिए प्रचार करेंगे बाइडन, राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हटने के फैसले को सही कदम बताया

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटने के अपने फैसले को सोमवार को सही कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते वह अभी लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वह जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।

बाइडन (81) ने गत रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस (59) के नाम की सिफारिश की थी। अपनी पूर्व प्रचार टीम को फोन पर संबोधित करते हुए बाइडन ने इसके सदस्यों से उपराष्ट्रपति कमला को दिल से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभियान टीम का नाम बदलकर भले ही हैरिस कैंपेन कर दिया गया है, लेकिन इसका मिशन वही है-डोनाल्ड ट्रंप को हराना। बाइडन जून में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के दबाव का सामना कर रहे थे। उनकी सेहत को लेकर जारी अटकलों के कारण भी डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी जगह किसी और को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी सौंपने की मांग जोर पकड़ने लगी थी।

राष्ट्रपति अभी कोविड-19 संक्रमण की चपेट में होने के कारण पृथकवास में हैं। उन्होंने अपनी पूर्व प्रचार टीम से कहा, अगर मुझे कोविड नहीं हुआ होता, तो मैं वहां आपके साथ बैठा होता, आपके साथ खड़ा होता। कोविड अगले तीन-चार दिन तक मुझे लोगों से दूर रखेगा, लेकिन मैं जल्द मैदान में उतरने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बाइडन ने कहा, कोविड ने मुझे अभी कुछ दूर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग याद रखें कि हमने जो किया है, वह अविश्वसनीय है और हम आगे भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं।

उन्होंने अपनी पूर्व प्रचार टीम से कमला को दिल से अपनाने, एकजुट होकर काम करने और ट्रंप को हराने का आग्रह किया। बाइडन ने कहा, मैं टीम से कहना चाहूंगा कि उन्हें (कमला हैरिस) दिल से अपनाएं। वह शानदार हैं। मैं सभी के प्रयासों के लिए उनका आभार जताना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि कल का घटनाक्रम चौंकाने वाला है और इसे स्वीकार करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यह सही कदम था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि आपने मुझे इस दौड़ में जिताने के लिए, उम्मीदवारी हासिल करने के लिए, और फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजई बनाने के लिए अपना तन-मन और आत्मा झोंक दी थी। बाइडन ने स्पष्ट किया कि प्रचार टीम का नाम बदल गया है, लेकिन मकसद नहीं। उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कमला के साथ चुनाव प्रचार करूंगा। मैं निवर्तमान राष्ट्रपति के रूप में, कानून पारित कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में कड़ी मेहनत करूंगा।

बाइडन ने कहा, हमें अभी भी लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ट्रंप अभी भी समुदाय के लिए खतरा हैं। वह देश के लिए खतरा हैं। मेरे विदेश नीति सहयोगियों, मेरे समकक्षों और देश-दुनिया के लोगों से पूछें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह कमला का भी पूरे दिल और आत्मा से सहयोग करेंगे।

बाइडन कोविड-19 से लगभग उबरे, जनता से दूरी कायम

रेहोबोथ बीच (अमेरिका)। अमेरिका के राष्ट्रपति के चिकित्सक ने बताया कि जो बाइडन कोविड-19 से लगभग उबर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने सोमवार को लगातार पांचवें दिन जनता से दूरी बनाए रखी। बाइडन ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट कर, अगले राष्ट्रपति की दौड़ से हटने की घोषणा की थी। उन्होंने इस पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने की भी घोषणा की थी। राष्ट्रपति को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार देर रात को डेलावेयर में अमेरिकी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था। इसके बाद वह कार में बैठकर डेलावेयर के रेहोबोथ बीच स्थित अपने घर चले गए थे। बाइडन के चिकित्सक डॉ. केविन ओ कोनोर ने कहा, राष्ट्रपति संक्रमण से लगभग उबर चुके हैं। उनकी धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर और तापमान पूरी तरह सामान्य बना हुआ है।

नेपाल को हराकर भारत महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में

भाषा। दाम्बुला

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 48 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत ने तीन विकेट पर 178 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को नौ विकेट पर 96 रन पर रोक दिया।

भारत ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई जबकि नेपाल का सफर तीन मैचों में एक जीत से दो अंक के साथ खत्म हो गया। इस ग्रुप से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के तीन मैचों में चार अंक है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि राधा यादव और अरुंधति रेड्डी को दो-दो सफलता मिली। रेणुका सिंह को एक विकेट मिला।नेपाल के लिए सीता राणा मागर ने 18 जबकि बिंदु रावल ने नाबाद 17 रन बनाए। रुबीना छेत्री (15) और कप्तान इंदु वर्मा (14) भी दहाई में रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रही। शेफाली ने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाने के अलावा डी हेमलता के साथ पहले विकेट के लिए 84 गेंद में 122 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरूआत दिलाई। हेमलता ने 42 गेंद की पारी में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 47 रन का योगदान दिया।

आखिरी ओवरों में जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंद में पांच चौके की मदद से नाबाद 28 रन की पारी खेलीनेपाल के लिए सीता राणा मागर ने दो और कविता जोशी ने एक विकेट लिया।लक्ष्य का बचाव करते हुए अरुंधति ने दूसरे ओवर में समझना खड़का (सात) को बोल्ड कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। कविता कुंवर और सीता राण ने इस गेंदबाज के अगले ओवर में एक-एक चौके के साथ आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की। रेणुका ने पांचवें ओवर में कविता (छह) को पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं राधा ने इंदु को चलता किया।नेपाल को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को 10.2 ओवर में जीतना था लेकिन टीम 10 ओवर में तीन विकेट पर 48 रन ही बना सकी थी।सीता राणा ने 11वें ओवर में अरुंधति के दूसरे स्पैल का स्वागत चौके से किया लेकिन इस गेंदबाज ने अगली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया। रुबिना ने दीप्ति के गेंद पर पारी का पहला छक्का जड़ा लेकिन इस ऑफ स्पिनर की अगली गेंद पर बोल्ड हो गई। इसी ओवर में कविता जोशी खाता खोले बगैर पगबाधा हो गई।दीप्ति ने इसके बाद शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए पूजा महतो (दो) को रन आउट किया तो वही राधा ने 17वें ओवर में डॉली भट्टा को विकेट के पीछे लपकवाया। बिंदु ने अरुंधति के खिलाफ चौका जड़कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की लेकिन वह टीम के रनों का शतक पूरा करने में सफल नहीं रही। भारतीय टीम ने इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरफनमौला पूजा वस्त्राकर को विश्राम दिया। शेफाली वर्मा के साथ मैच में टीम की अगुवाई कर रही स्मृति मंधाना की जगह हेमलता ने भारतीय पारी का आगाज किया।शेफाली ने पहले ओवर में कविता कुंवर और चौथे ओवर में शबनम राय के खिलाफ दो-दो चौके जड़कर एक बार फिर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरे छोर से संभल कर खेल रही हेमलता ने पूजा के खिलाफ दर्शनीय चौका जड़ आत्मविश्वास हासिल किया। भारतीय टीम ने छठे ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया। शेफाली ने अगले ओवर में रुबीना के खिलाफ छक्का और चौका लगाया तो वहीं हेमलता ने आठवें ओवर में कविता जोशी के खिलाफ ऐसा किया। शेफाली ने इसी ओवर में चौका जड़ने के बाद एक रन के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

शेफाली जहां नेपाल की गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन जुटा रही थी तो वहीं हेमलता को गैप ढूंढने में परेशानी हो रही थी।सीता राणा ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हेमलता को आउट कर नेपाल को पहली सफलता दिलाई। उनके अगले ओवर में आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शेफाली भी स्टंप हो गई। वस्त्राकर की जगह टीम में आई संजीवन सजना कुछ खास नहीं कर सकी और 12 गेंद में 10 रन बनाकर कविता जोशी का शिकार बन गई।

पीसीबी ने भारत को पाकिस्तान आने के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ा

भाषा। कराची

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अगले साल की शुरुआत में होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पर छोड़ दिया है। पीसीबी के एक सूत्र के अनुसार कोलंबो में हाल ही में हुई आईसीसी की बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को मंजूरी दी गई थी लेकिन कार्यक्रम और प्रारूप पर चर्चा नहीं हुई। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, पीसीबी ने अब वह कर दिया है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में उससे अपेक्षित था। उसने प्रतियोगिता का मसौदा कार्यक्रम और प्रारूप सौंप दिया है तथा प्रतियोगिता के लिए बजट भी सौंप दिया है। उन्होंने कहा, अब यह आईसीसी पर निर्भर है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को कितनी जल्दी प्रसारित, चर्चा और अंतिम रूप देते हैं। पीसीबी ने मसौदा कार्यक्रम में भारत के सभी मैचों की मेजबानी लाहौर में करने का सुझाव दिया है जिसमें सेमीफाइनल (अगर भारत क्वालीफाई करता है) और फाइनल भी शामिल है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में आईसीसी के साथ अपनी रुचि के दस्तावेज में सभी विवरण पहले ही सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, पीसीबी ने अपनी ओर से आईसीसी को कर से जुड़े नियमों, स्थल चयन और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम की मेजबानी के लिए अपनी सरकार से मंजूरी के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी है। सूत्र ने खुलासा किया कि पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने आईसीसी बैठकों के इतर बीसीसीआई सचिव जय शाह या किसी अन्य बीसीसीआई अधिकारी के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं की लेकिन बैठकों के दौरान नकवी और शाह के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। पीसीबी ने अब टूर्नामेंट के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और घोषित करने तथा बीसीसीआई से यह पुष्टि प्राप्त करने का काम आईसीसी पर छोड़ दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा करेगी या नहीं। आईसीसी ने अपने टूर्नामेंट बजट में सप्लीमेंटरी (पूरक) खर्चे को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रखा है जिसमें भारतीय टीम के पाकिस्तान के बाहर अपने मैच खेलने की संभावना भी शामिल है।

बीसीसीआई ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से सरकार का फैसला है और यहां तक कि पीसीबी की मेजबानी में हुए 2023 एकदिवसीय एशिया कप में भारत ने हाइब्रिड मॉडल के आधार पर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। मसौदा कार्यक्रम के अनुसार संभावित सेमीफाइनल और फाइनल सहित भारत के सभी मैच लाहौर में निर्धारित किए गए हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच एक मार्च को निर्धारित किया गया है। इस बीच अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में खेलने का आश्वासन दे दिया है। आईसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक में भाग लेने कोलंबो गए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मीरवाइज अशरफ और सीईओ नसीब खान ने नकवी से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। पीसीबी ने कहा, उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि अफगानिस्तान अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए उत्सुक है क्योंकि वे पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, बीसीसीआई के टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला करने पर कुछ देशों के भारत की राह पर चलने की अटकलों के बीच उन्होंने यह आश्वासन दिया।

महिला टी20 रैंकिंग : हरमनप्रीत, शेफाली संयुक्त 11वें और मंधाना पांचवें स्थान पर

दुबई। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में पांचवां स्थान बनाए रखा है जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। हरमनप्रीत को एक पायदान का फायदा मिला जबकि शेफाली बल्लेबाजों की सूची में चार पायदान ऊपर आ गई। शीर्ष 20 में भारत के चार खिलाड़ी हैं। जेमिमा रौड्रिग्स 19वें स्थान पर हैं। रिचा घोष 24वें स्थान पर है। बेथ मूनी 769 अंक लेकर शीर्ष पर है। गेंदबाजों की सूची में आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर है जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह नौवे स्थान पर है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव 20वें स्थान पर है। इंग्लैंड की सोफी एस्सेलेटोन शीर्ष पर हैं।

भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में असालांका होंगे श्रीलंका के कप्तान

पाल्लेकल। चरित असालांका भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में श्रीलंका के कप्तान होंगे। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है।हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असालांका ने इस साल की शुरूआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी जब हसरंगा निलंबन झेल रहे थे। श्रीलंका के पूर्व अंडर 19 कप्तान असालांका ने इस साल एलपीएल में जाफना किंग्स को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाया था। भारतीय टीम सोमवार की रात को यहां पहुंच गई।

श्रीलंका टीम : चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंता चामीरा, बिनुरा फर्नांडो।

पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेट से रौंदा, सेमीफाइनल का दावा मजबूत

दाम्बुला(भाषा)। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा के नाबाद अर्धशतक से पाकिस्तान ने महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में यूएई को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। यूएई के 104 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुल की 55 गेंद में आठ चौकों से नाबाद 62 रन की पारी और मुनीबा अली (नाबाद 37) के साथ उनकी पहले विकेट की अटूट शतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने 14.1 ओवर में बिना विकेट खोए 107 रन बनाकर बेहद आसान जीत दर्ज की।

यूएई की टीम इससे पहले सादिया (11 रन पर दो विकेट), तुबा हसन (17 रन पर दो विकेट) और नासरा संधू (22 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 103 रन ही बना सकी। यूएई की ओर से सलामी बल्लेबाज तीर्था सतीश ने 36 गेंद में पांच चौकों की मदद से सर्वाधिक 40 रन बनाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज और कप्तान ईशा ओझा (16) और खुशी शर्मा (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। इस जीत से पाकिस्तान के तीन मैच में दो जीत से चार अंक हो गए हैं और टीम का सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत हो गया है। यूएई की टीम तीनों मैच हारकर बाहर हो चुकी है।शाम को दूसरा मैच गत चैंपियन भारत और नेपाल के बीच होगा। भारत दो मैच में दो जीत से चार अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि नेपाल दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

आईओए ने बीपीसीएल को चार साल के लिए मुख्य प्रायोजक बनायाः नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को पेरिस ओलंपिक से 2028 लॉस एंजिल्स खेलों तक चार साल के लिए अपना आधिकारिक मुख्य प्रायोजक नामित किया। महारत्न कंपनी बीपीसीएल और आईओए के बीच सहयोग में राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, युवा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन युवा ओलंपिक भी शामिल होंगे। इस सहयोग के तहत बीपीसीएल पेरिस जाने वाले भारतीय दल का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए अभियानों की श्रृंखला शुरू करेगा। इन पहलों का उद्देश्य राष्ट्र को प्रेरित करना, खिलाड़ियों के लिए समर्थन जुटाना और वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता के लिए उनकी निरंतर खोज का जश्न मनाना है।

एमसीए चुनावः संजय नाईक को हराकर अजिंक्य अध्यक्ष बने

मुंबई। अजिंक्य नाईक मंगलवार को यहां अपने प्रतिद्वंद्वी संजय नाईक को 107 मतों से हराकर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के नए अध्यक्ष बन गए। एमसीए के निवर्तमान सचिव अजिंक्य ने 221-114 के अंतर से एकतरफा जीत दर्ज की। सैंतीस साल के अजिंक्य को अनुभवी राजनेता और बीसीसीआई के साथ-साथ आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार का समर्थन प्राप्त था। वह एमसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी संजय एमसीए के मौजूदा उपाध्यक्ष हैं। उन्हें आशीष शेलार समूह का समर्थन प्राप्त था। भाजपा नेता शेलार बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी हैं। टी20 विश्व कप के दौरान न्यूयॉर्क में अमोल काले के असामयिक निधन के बाद चुनाव प्रक्रिया चार जुलाई को शुरू हुई थी। अजिंक्य ने यहां जारी बयान में कहा, यह जीत अमोल काले की अनुकरणीय उपलब्धि का प्रमाण है। मेरा प्रयास मुंबई क्रिकेट की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को दोहराना और उनकी विरासत को आगे ले जाना होगा। चुनावों में कुल 335 मत डाले गए। मतदान करने वालों में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एवं राष्ट्रीय और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर, जहीर खान, संजय मांजरेकर, बलविंदर सिंह संधू और पारस म्हाम्ब्रे भी शामिल थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े दो मौजूदा सहित आठ खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

भाषा। नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय की मौजूदा छात्र निशानेबाज रमिता जिंदल और रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक के लिए चुने गए भारतीय खिलाड़ियों के 117 सदस्यीय दल में शामिल हैं। रमिता और रिदम के अलावा विश्वविद्यालय के छह पूर्व छात्र भी पेरिस में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। हंसराज कॉलेज की बी. कॉम अंतिम वर्ष की छात्रा रमिता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाज रिदम लेडी श्रीराम कॉलेज में अंग्रेजी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही है। रिदम के कॉलेज की सीनियर पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। बिहार विधानसभा में भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह (महिला ट्रैप निशानेबाजी) ने 2012 में हंसराज कॉलेज से बीए प्रोग्राम किया था। स्कीट निशानेबाज महेश्वरी चौहान और ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी भी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। महेश्वरी ने 2017 में लेडी श्री राम कॉलेज से फिलॉसफी (ऑनर्स) की पढ़ाई की, जबकि राजेश्वरी 2010 में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की बीए प्रोग्राम की छात्रा थीं। राजेश्वरी एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) की कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह की बेटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल निदेशक अनिल कुमार कलकल ने बताया कि एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जीसस एंड मैरी कॉलेज से समाजशास्त्र (ऑनर्स) की पढ़ाई की है। ट्रैक एवं फील्ड में 400 मीटर के धावक अमोज जैकब ने 2016 से 2019 के बीच श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बी.कॉम किया है। वह चार गुणा 400 मीटर पुरुष रिले टीम का अभिन्न अंग हैं। कलकल ने बताया कि इन खिलाड़ियों के अलावा मनु के व्यक्तिगत कोच जसपाल राणा भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे है। उन्होंने अरविंदो कॉलेज से पढाई की है। कुलपति योगेश सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सराहनीय प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पदक जीतेंगे।

विश्वास, टीम भावना पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम की सफलता की कुंजी : फुल्टोन

नई दिल्ली। पिछले साल भारतीय पुरूष हॉकी टीम से जुड़े कोच क्रेग फुल्टोन का लक्ष्य आपसी विश्वास मजबूत करना था और उन्हें यकीन है कि उनके प्रयासों का नतीजा पेरिस ओलंपिक में पदक के बेहतर रंग के रूप मे मिलेगा। चौदह महीने पहले पदभार संभालने वाले फुल्टोन ने पीटीआई से कहा , मुझे नही पता कि तोक्यो ओलंपिक से पहले क्या तैयारियां थी लेकिन 14 महीने पहले मेरे आने के बाद से फोकस खिलाड़ियों मे आपसी विश्वास बेहतर करने पर रहा है। उन्होंने बेहतर नतीजों के लिए दक्षिण अफ्रीका के मानसिक अनुकूलन कोच पैडी उपटन की सेवाएं ली जो 2011 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके है। उपटन टीम के साथ पेरिस मे है। मानसिक दृढता के लिए उन्होने इस महीने की शुरूआत मे स्विटजरलैंड के माइक होर्न्स बेस मे तीन दिन का शिविर लगाया। फुल्टोन ने कहा , मैने अल्पकालिन और दीर्घकालिन रणनीति बनाई और उसके हिसाब से काम किया। उन्होंने कहा , हमारी तैयारियां अच्छी रही और स्विटजरलैंड मे तीन दिन का शिविर बहुत अच्छा साबित हुआ। हमने आपसी विश्वास, टीम भावना और एकजुटता बढाने पर काम किया। इसके बाद नीदरलैंड मे नौ दिन अभ्यास किया और कुछ अभ्यास मैच भी खेले। तोक्यो ओलंपिक मे 41 साल बाद कांस्य पदक विजेता से अपेक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा , मुझे अपेक्षाओं का पता है और मै इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। भारत का हॉकी का गौरवमई इतिहास रहा है और हम उस विरासत को आगे बढाना चाहते है। उन्होंने कहा , मै पोडियम पर रहने के बारे में क्यास नही लगा सकता क्योंकि ओलंपिक मे 12 टीमों के बीच ज्यादा अंतर नही है। पहले तीन मैच अहम है जिन पर फोकस रहेगा।

असम के मुख्यमंत्री ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आर्डर मिलने पर बधाई दी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनके असाधारण योगदान के लिए ओलंपिक आर्डर मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा , उम्मीद है कि वह आने वाली पीढियों को खेलों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने बिंद्रा को बताया कि उन्हें ओलंपिक आर्डर दिया गया है और पुरस्कार समारोह 10 अगस्त को पेरिस मे आईओसी के 142वे सत्र के दौरान होगा। असम सरकार ने गुवाहाटी और जोरहट मे दो हाई परफार्मेंस खेल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए असम सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 250 सरकारी और गुवाहाटी के निजी स्कूलो मे ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) लागू करने के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए है। इसका मकसद बदलती जीवन शैली, एकाग्रता के अभाव और स्कूल से बच्चो का नाम वापिस लेने जैसी समस्याओ से निपटना है।

भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू किया अभ्यास

पाल्लेकल (श्रीलंका)। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की देख रेख में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला से पहले यहां अपने शुरूआती अभ्यास सत्र में मैदान पर उतरी। दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह कोच बने गंभीर ने मैदान पर टीम का नेतृत्व किया और अभ्यास सत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने हलका अभ्यास किया जिसमें क्षेत्ररक्षण अभ्यास, दौड़ने और गेंद को पकड़ने का अभ्यास शामिल था। इस दौरान टीम के खिलाड़ी टी 20 अंतरराष्ट्रीय टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ बातचीत करते देखे गए। गंभीर ने बल्लेबाजी अभ्यास कर रहे संजू सैमसन के साथ बातचीत करने के बाद मैदान पर हरफनमौला शिवम दुबे के साथ समय बिताया। भारत के पूर्व हरफनमौला अभिषेक नायर और नीदरलैंड के बल्लेबाज रयान टेन डोशेट श्रीलंका दौरे के लिए गंभीर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। इन तीनों ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आईपीएल 2024 खिताब दिलाने के लिए सहयोग किया था। राष्ट्रीय टीम के साथ उनका पहला कार्य 27 जुलाई को टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के साथ शुरू होगा जिसके बाद तीन वनडे मैच होंगे। द्रविड़ के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप टीम के साथ बने हुए है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से जुड़े साईराज बहुतुले इस दौरे में अंतरिम गेंदबाजी कोच के रूप में काम करेंगे।

एसीटी से पहले हॉकी इंडिया ने ओलंपिक टीम से इतर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर में बुलाया

नई दिल्ली, । हॉकी इंडिया ने सितंबर में चीन में होने वाली एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरू में सीनियर पुरूष टीम के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में उन खिलाड़ियों को बुलाया है जो पेरिस ओलंपिक की टीम का हिस्सा नहीं हैं। इसमें विकास ग्रुप और जूनियर पुरूष हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं। ओलंपिक टीम में शामिल खिलाड़ी छोटे ब्रेक के बाद 24 अगस्त से राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे जो चार सितंबर तक चलेगा।मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने हॉकी इंडिया द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति में कहा , सीनियर टीम पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरूआत की तैयारी में जुटी है लेकिन हमारे पास उससे इतर भी खिलाड़ियों का मजबूत पूल है जो भारत के लिए फिर खेलने के मौके के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा , एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी ओलंपिक के कुछ सप्ताह बाद ही है लिहाजा इसके लिए बेंगलुरू के साइ केंद्र में शिविर लगाया जा रहा है। ए खिलाड़ी उसके लिए तैयारी करेंगे।

पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे एंडी मे

पेरिस। दो बार ओलंपिक पुरूष एकल चैम्पियन एंडी मे ने मंगलवार को पुष्टि की कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह खेल से संन्यास लेंगे। सैंतीस वर्ष के मे ने एक्स पर पोस्ट किया , अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया हूं। पेरिस ओलंपिक मे टेनिस स्पर्धा रोलां गैरो पर शनिवार से शुरू होगी। मे ने पहला स्वर्ण पदक 2012 लंदन ओलंपिक मे ग्रासकोर्ट पर जीता था जिसमे उन्होने रोजर फेडरर को तीन सेटों मे हराया था। इसके बाद 2016 मे रियो दि जिनेरियो मे हार्डकोर्ट पर जुआन मार्टिन देल पोत्रो को हराकर खिताब जीता था। मे ने 2019 मे कूल्हे की प्रत्यारोपण सर्जरी कराई थी।

पेरिस ओलंपिक से पहले असम के लोगों ने लवलीना को शुभकामनाएं दी

गुवाहाटी। पेरिस खेलो मे अपने दूसरे ओलंपिक पदक की तैयारी कर रही स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को उनके गृह राज्य असम से गमोसा (अंग वस्त्र), चॉक्लेट और दिल के छूने वाले संदेशों के रूप मे शुभकामनाएं दी गईं। मंगलवार को यहां एक समारोह के दौरान शुभचिंतकों के साथ उभरते खिलाड़ियों से लेकर सीनियर खिलाड़ियों ने एक बड़े बोर्ड पर लवलीना के लिए संदेश लिखे जबकि उनकी बहन की सास ने एक गमोसा और चॉक्लेट पैक करके भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के महासचिव हेमंत कलिता को सौंपी। अगले हफ्ते पेरिस जाने वाले कलिता ने समझाया कि चॉक्लेट पिघल सकती है और गमोसा पर दाग लग सकता है जिसके बाद महिला ने अनिच्छा से चॉक्लेट वापस ले ली। लवलीना की बहन लीमा ने अपनी सास और बेटे के साथ हस्ताक्षर अभियान मे भाग लेते हुए कहा, यह उनके प्रति हमारे स्नेह की गहराई को दर्शाता है। हमें विश्वास है कि वह अपनी पिछली उपलब्धियों से बेहतर करेंगी।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाषः 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादकः प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5,बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।